राष्ट्रीय मासिक पत्रिका

मूल्य: ₹15/-

RNI No. BIHHIN/2007/22741

उभरता बिहार

सच्चाई, ऊर्जा, सकारात्मक विचार

वर्ष : 13, अंक : 8, फरवरी 2021

www.ubhartabihar.com | Email : ubhartabihar@gmail.com

बजट को किसी ने सराहा तो किसी ने नकारा

नर और नारी के बिना सृष्टि अधूरा है

कोराना काल में याद आती हैं बच्चों की शरारतें

SVR
HOTEL & BANQUET
SVR
HOTEL & BANQUET
SHIV LAXMI PLAZA
TRENDS FOOTWEAR
SHIV LAXMI PLAZA
Near Rajendra Nagar Terminal Main Road
KANKARBAGH, Patna 800020

उभरता बिहार

वर्ष : 13, अंक : 8, फरवरी 2021

RNI No. BIHHIN/2007/22741

संपादक

राजीव रंजन

छायाकार

विनोद राज

विधि सलाहकार

उपेन्द्र प्रसाद

चंद्र नारायण जायसवाल

साज-सज्जा

मयंक शर्मा

प्रशासनिक कार्यालय

सी-49 हाऊसिंग कॉलोनी, लोहियानगर

कंकड़बाग, पटना - 800020

फोन : 7004721818

Email : ubhartabihar@gmail.com

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक व संपादक रांजीव रंजन द्वारा कृत्या पब्लिकेशन, लंगरटोली, बिहार से मुद्रित एवं सी-49 हाऊसिंग कॉलोनी, लोहियानगर, कंकड़बाग, पटना - 800020 से प्रकाशित।

संपादकः राजीव रंजन

सभी कानूनी विवाद पटना न्यायिक क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत निपटाये जायेंगे। लेखकों द्वारा व्यक्त विचार उनके अपने है। इसकी जिम्मेदारी उनकी है एवं इसके लिये संपादक, प्रकाशक की सहमति अनिवार्य नही है। सामग्री की वापसी की जिम्मेवारी उभरता बिहार की नहीं होगी। इस अंक में प्रकाशित सभी रचनाओं के सर्वोधिकार सुरक्षित है। कुछ छाया चित्र और लेख इंटरनेट, एजेंसी एवं पत्र-पत्रिकाओं से साभार। उपरोक्त सभी पद अस्थायी एवं अवैतनिक है। किसी भी आलेख पर आपत्ति हो तो 15 दिनों के अंदर खंडन करें।

नोट : किसी भी रिपोर्टर द्वारा अनैतिक ढंग से लेन-देन के जिम्मेवार वे स्वयं होंगे।

संरक्षक

डॉ. संतोष कुमार

अखिलेश कुमार जायसवाल

प्रभात कुमार चौधरी

डॉ. राकेश कुमार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया विरोधियों को एक्सपोज 10

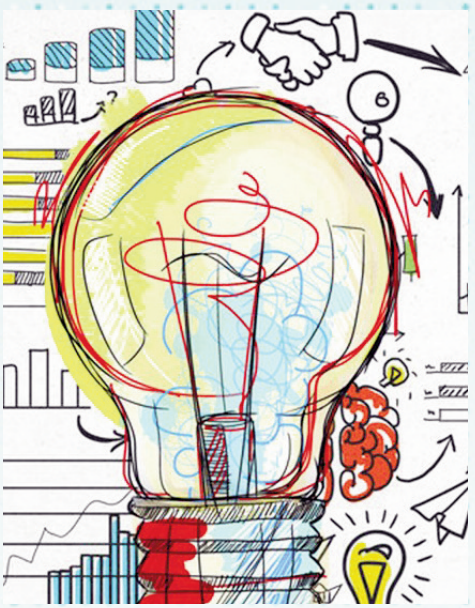

विकास के पथ पर बड़ी मजबूती ... 12

कोराना काल में याद आती हैं .. 43

मातृछाया ऑर्थो एण्ड हेल्थ केयर

Consultant Trauma & Spinal Surgeon

हड्डी, जोड़, रीढ़, नस एवं गठिया रोग विशेषज्ञ

विशेषताः

1. यहां हड्डी रोग से संबंधित सभी रोगों का इलाज होता है।
2. मशीन के द्वारा टूटे-हड्डी बैठाने की सुविधा उपलब्ध है।

विशेषताः

3. स्पाइन सर्जरी की भी सुविधा है।
4. Total Joint Replacement विशेषज्ञों की टीम के द्वारा सस्ते दरों पर की जाती है।

24 HRS.

ORTHO & SPINAL EMERGENCY

Dr. Rakesh Kumar

M.B.B.S. (Pat), M.S. (Pat), M.Ch, Ortho, Fellowship is Spine Surgery
Indian Spinal Injury Centre, New Delhi

G-43, P.C. Colony, Kankarbagh, Patna-20, Mob. - 7484814448, 9504246216

बजट में अर्थ व्यवस्था को बल देने की कोशिश

राजीव रंजन
संपादक
rradvocate@gmail.com

संसद में केन्द्रीय बजट अर्थ व्यवस्था को बल देने की जो कोशिश हुई है, उनका जमीनी असर न केवल योजनाओं और बजट के क्रियान्वयन पर, बल्कि सरकार के भावी निर्णय पर निर्भर करता है। यह प्रयास मूलभूत ढाँचे में निवेश उद्योग जगत को प्रोत्साहित करने के लिए किए गए हैं। बजट से भी जाहीर है। लोगों को मिल रही आर्थिक मदद के प्रयासों से सरकार संतुष्ट हैं और इसका उल्लेख बजट में बखूबी किया गया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में आत्मनिर्भर पर जोड़ दिया है, यह कोई कोई आश्चर्य भी नहीं है। कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए सरकार के 27.1 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत पैकेज से संरचनात्मक सुधारों को बढ़ावा मिला है। अब आम बजट में सरकार ने 64.180 करोड़ रुपए के कड़ी व्यय के साथ आत्मनिर्भर स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। स्वास्थ्य ढाँचा मजबूत करना कितना जरुरी है, यह हमने कोरोना के समय अच्छी तरह समझ लिया है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भी जारी रहेगा।

जब सरकारी खजाना दवाव में है, तब वैसे आयकरदाताओं को राहत की उम्मीद नहीं थी। जबकि सरकार ने 75 साल या उससे अधिक उम्र के पेंशनभोगियों को कुछ राहत दी है। देश के 135 करोड़ लोगों में से करीब 6 करोड़ लोग आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं, जबकि 3 करोड़ लोग हीं आयकर चुकाते हैं। मुश्किल समय में सरकार आयकर का दायरा बढ़ाने के लिए कुछ कर सकती थी। लेकिन अभी आयकर या अन्य करों को बढ़ाने का समय नहीं है। ऐसे में, सरकार ने पेट्रोल पर 2.5 रुपये प्रति लीटर का अधिभार लगाया है, जबकि डीजल पर 4 रुपए का हीं अधिभार लगायाहै। इससे पेट्रोल डीजल की कीमतों को तीन अंको में जाने और बने रहने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, मतलब महंगाई बढ़ेगा। मोबाईल उपकरण पर कस्टम ड्यूटी बढ़ेगी, लेकिन इसका लाभ तभी है, जब देशी कम्पनियाँ स्वयं पर्याप्त उपकरण बनाने लगें, वरना आज के समय में मोबाईल फोन को महँगा करने की दिशा में कोई निर्णय अनुकूल नहीं है।

जब भारत को निर्यात बढ़ाने के लिए ज्यादा प्रयत्न करने हैं, तब आयात बढ़ाने के छोटे-मोटे उपाय भले हीं किसी निजी कम्पनी या उपभोक्ता के लिए फायदेमंद हो, लेकिन हमें व्यापकता में देश की आत्मनिर्भरता बढ़ाने के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। सस्ते घर की सुबिधा, डूबते कर्ज का प्रबंधन, सरकारी बैंकों को पूँजी देने का प्रस्ताव, उज्ज्वला योजना का विस्तार, रेल एवं बस सेवा विस्तार, किसानों को फसल लागत से डेढ़ गुना मूल्य देने का इरादा इत्यादि अनेक प्रशंसनीय कोशिशें हैं, हम समझ सकते हैं। विनिवेश से भी सरकार पैसे जुटाना चाहती है, यह पुराना एजेंडा है।

बजट को किसी ने सराहा तो किसी ने नकारा

निर्मला की बाजीगीरी से बाजार बमबम,आम आदमी का निकलेगा दम

जनजातीय आबादी के लिए एकलव्य मॉडल स्कूल की स्थापना का निर्णय स्वागत योग्य

गौतम सुमन गर्जना

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का पहला पेपरलेस बजट पेश किया और इसे मेड इन इंडिया टैबलेट से पढ़ा। अन्य सांसदों को भी बजट उनके मोबाइल पर मिला,इसमें मध्यम वर्गों के हाथ खाली ही रहे। सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया,न ही कोई छूट दी। हालांकि, किफायती घर खरीदने वालों को ब्याज में 1.5 लाख रुपए की एक्स्ट्रा छूट का समय एक साल बढ़ाकर मार्च 2022 तक कर दिया। वहीं 75 साल से ज्यादा उम्र वाले पेंशनर्स को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से छूट भी दी है। सरकार की बाजीगीरी से जहां शेयर बाजार बमबम हुआ,वहीं आम आदमी के हाथ निराशा लगी है।

बजट पेश करते वक्त वित्त मंत्री ने कहा कि हमने लॉकडाउन खत्म होने के बाद सरकारी खर्च बढ़ाया है। 2020-21 में 30.42 लाख करोड़ रुपए के सरकारी खर्च का अनुमान था, जो बढ़कर 34.5 लाख करोड़ रुपए हो गया। 2020-21 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 9.5 प्रतिशत है। इसकी भरपाई के लिए हमें 80 हजार करोड़ रुपए और चाहिए। इसके लिए हमें बाजार से उम्मीद है। 2021-22 में 34.83 लाख करोड़ रुपए के सरकारी खर्च का अनुमान है। 2021-22 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है। 2025-26 तक इसे घटाकर 4.5 प्रतिशत करना चाहते हैं। कंटीजेंसी फंड को 500 करोड़ से बढ़ाकर 30 हजार करोड़ रुपए करने का प्रावधान है।

> सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया,न ही कोई छूट दी। हालांकि, किफायती घर खरीदने वालों को ब्याज में 1.5 लाख रुपए की एक्स्ट्रा छूट का समय एक साल बढ़ाकर मार्च 2022 तक कर दिया। वहीं 75 साल से ज्यादा उम्र वाले पेंशनर्स को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से छूट भी दी है। सरकार की बाजीगीरी से जहां शेयर बाजार बमबम हुआ,वहीं आम आदमी के हाथ निराशा लगी है।

30 साल में सबसे ज्यादा घाटे में सरकार

सरकार का राजकोषीय घाटा 1991 से शुरू हुए उदारीकरण के बाद सबसे ज्यादा है। राजकोषीय घाटा यानी जब सरकार की आमदनी से ज्यादा उसका खर्च हो जाए। 1991 में यह जीडीपी का 5.6 प्रतिशत था। 2020-21 में यह जीडीपी का 9.5 प्रतिशत है। वित्त मंत्री ने कहा कि हमने लॉकडाउन खत्म होने के बाद सरकारी खर्च बढ़ाया है। 2020-21 में 30.42 लाख करोड़ रुपए के सरकारी खर्च का अनुमान था, जो बढ़कर 34.5 लाख करोड़ रुपए हो गया। इसकी भरपाई के लिए हमें 80 हजार करोड़ रुपए और चाहिए। इसके लिए हम अगले दो महीने में बाजार से मदद लेंगे। 2021-22 में 34.83 लाख करोड़ रुपए के सरकारी खर्च और 6.8 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे का अनुमान है। सरकार 2025-26 तक इसे घटाकर 4.5 प्रतिशत करना चाहती है। कंटीजेंसी फंड को 500 करोड़ से बढ़ाकर 30 हजार करोड़ रुपए करने का प्रावधान है।

पेट्रोल-डीजल पर एग्री सेस

सबसे पहले बात आम आदमी की जरूरत से जुड़े पेट्रोल-डीजल की। वित्त मंत्री ने पेट्रोल पर 2.5 रुपए और डीजल पर 4 रुपए प्रति लीटर सेस का प्रस्ताव रखा। इसका नाम होगा एग्री इन्फ्रा डेवलपमेंट सेस। यह 2 फरवरी से ही लागू हो गया। हालांकि, वित्त मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि इसका आम आदमी पर बोझ नहीं आने दिया जाएगा। इसके लिए बेसिक एक्साइज ड्यूटी और स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी घटा दी गई है। इसी तरह कस्टम ड्यूटी लगने वाली शराब पर 100 प्रतिशत, मसूर की दाल पर 20 प्रतिशत, सेब पर 35 प्रतिशत, सोयाबीन और सनफ्लावर ऑयल पर 20 प्रतिशत सेस का प्रस्ताव है, लेकिन आम आदमी पर इसका भी असर नहीं होगा।

75 साल से अधिक उम्र के करदाताओं को राहत

सरकार ने 75 साल से अधिक उम्र के करदाताओं को राहत दी है। सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021-22 के अपने बजट भाषण में यह घोषणा भी की कि केवल पेंशन और ब्याज आय वाले 75 साल से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता नहीं होगी। ब्याज का भुगतान करने वाले बैंक अपनी ओर से कर की कटौती कर लेंगे। इसके अलावा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर आकलन मामलों को फिर से खोले जाने की समय सीमा छह साल से घटाकर तीन साल कर दी। इसके साथ ही कर धोखाधड़ी से जुड़े ऐसे गंभीर मामलों में जहां छिपायी गई आय 50 लाख रुपये या उससे अधिक है, यह अवधि 10 साल होगी।

हेल्थ बजट में 137 प्रतिशत इजाफा

कोरोना की वजह से ही इस बार हेल्थ बजट में 137 प्रतिशत का इजाफा हुआ। हेल्थ बजट अब 2.23 लाख करोड़ रुपए का होगा, जिसके लिए पिछली बार 94 हजार करोड़ रुपए रखे गए थे। वित्त मंत्री ने कहा कि कोरोना वैक्सीन के लिए 35 हजार करोड़ रुपए दिए जाएंगे। जरूरत पड़ी तो इसके लिए और बजट मिलेगा। बच्चों को निमोनिया से बचाने के लिए देशभर में निमोकोक्कल वैक्सीन लगाई जाएगी। इस निमोनिया से हर साल 50 हजार बच्चों की मौत होती है। 602 जिलों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स शुरू होंगे। 15 हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स और 2 मोबाइल हॉस्पिटल शुरू होंगे।

डिजिटल भुगतान के लिए 1500 करोड़ की योजना

केंद्र सरकार ने देश में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिये इस बजट में 1500 करोड़ रुपए की योजना का प्रस्ताव रखा। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछले कुछ समय में डिजिटल भुगतान में कई गुना वृद्धि हुई है। उन्होंने 2021 . 22 का बजट पेश करते हुए कहा," डिजिटल लेन देन को और बढावा देने के लिये मैं 1500 करोड़ रुपए की योजना का प्रस्ताव रखती हूं,जिससे डिजिटल भुगतान को बढावा देने के लिये वित्तीय प्रोत्साहन दिया जायेगा।

> सरकार का राजकोषीय घाटा 1991 से शुरू हुए उदारीकरण के बाद सबसे ज्यादा है। राजकोषीय घाटा यानी जब सरकार की आमदनी से ज्यादा उसका खर्च हो जाए। 1991 में यह जीडीपी का 5.6 प्रतिशत था। 2020-21 में यह जीडीपी का 9.5 प्रतिशत है। वित्त मंत्री ने कहा कि हमने लॉकडाउन खत्म होने के बाद सरकारी खर्च बढ़ाया है।

सोना-चांदी होगा सस्ता, मोबाइल महंगा

सरकार के इस बजट से मोबाइल खरीदने की चाह रखने वालों को झटका लगा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोबाइल उपकरण पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मोबाइल उपकरण पर अब कस्टम ड्यूटी 2.5 फीसदी तक लगेगा। वहीं, कॉपर और स्टील में कस्टम ड्यूटी को घटाया गया है। इतना ही नहीं, सोना-चांदी से भी कस्टम ड्यूटी को घटाया गया है। इसका मतलब है कि अब सोना-चांदी सस्ता होगा और मोबाइल महंगा।

सात बंदरगाह परियोजनाओं के लिए 2000 करोड़

सरकार ने 2000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से सात बंदरगाह परियोजनाओं की घोषणा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि ये परियोजनाएं सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत कार्यान्वित की जाएंगी। वित्त मंत्री सीतामरण ने लोकसभा में पहला कागज रहित आम बजट पेश करते हुए कहा कि उन्होंने पीपीपी मोड के जरिए 2000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से सात बंदरगाह परियोजनाओं का प्रस्ताव किया है। भारत में अभी 12 प्रमुख बंदरगाह हैं, जो केंद्र सरकार के नियंत्रण में हैं। इनमें दीनदयाल (पूर्ववर्ती कांडला), मुंबई,जेएनपीटी, न्यू मेंगलूर, कोच्चि, चेन्नई,पारादीप, कोलकाता (हल्दिया सहित) शामिल हैं।

बीमा क्षेत्र में एफडीआई 74 प्रतिशत

सरकार ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश(एफडीआई) की सीमा को बढ़ाकर 74 प्रतिशत करने का प्रस्ताव दिया है। इस कदम का उद्देश्य विदेशी कंपनियों को निवेश के लिए आकर्षित करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहली बार कागज रहित बजट पेश करते कहा कि सभी वित्तीय उत्पादों के लिए निवेशक चार्टर पेश किया जाएगा। यह सभी वित्तीय निवेशकों का अधिकार होगा। उन्होंने बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा को 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत करने तथा रक्षोपाय के साथ विदेशी भागीदारी तथा नियंत्रण की अनुमति के लिए बीमा अधिनियम-1938 में संशोधन का प्रस्ताव किया। आम बजट 2021-22 पेश करते हुए सीतारमण ने कहा कि नए ढांचे के तहत ज्यादातर निदेशक और बोर्ड तथा प्रबंधन स्तर के अधिकारी निवासी भारतीय होंगे। कम से कम 50 प्रतिशत निदेशक स्वतंत्र निदेशक होंगे। इसके अलावा मुनाफे का एक निश्चित प्रतिशत सामान्य आरक्षित निधि के रूप में रखा जाएगा।

लड़कियों के विवाह की उम्र सीमा में हो सकते हैं बदलाव,वित्त मंत्री ने बजट में दिया संकेत

वर्तमान दशक के पहले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट,शिक्षा, स्वास्थ्य,स्वच्छता,विकास निर्माण,रोजगार के अवसर को बढ़ाने पर आवंटित रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना काल के बाद बिगड़ती अर्थव्यवस्था में आनेवाले समय में इस बजट का असर निश्चित रुप में दिखेगा। लेखक व पत्रकार होने के नाते सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में बजट के कुछ सराहनीय योजनाओं का मैं स्वागत करता हूँ। आदिवासी क्षेत्रों में उनके बच्चों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की पहल अच्छी है।15 हजार सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने की बात करना और धरातल पर लाना निश्चय ही शिक्षा के स्तर को सुधरेगा।दलित छात्रों के लिए योजनाएं,पीपीपी मॉडल के सैनिक स्कूल, लेह में केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की बात और उच्च शिक्षा के लिए कमीशन बनाने की योजनाओं का भी स्वागत है।शिक्षा के अतिरिक्त मण्डियों को इंटरनेट से जोड़ना,एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की योजनाएं भी सराहनीय है।मिला-जुलाकर बजट में हर क्षेत्र की बात की गई।

महिलाओं के कल्याण के लिए जिम्मेदार समाज के मूल्य विषय पर जोर देते हुए वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान पोषण संबंधी कार्यक्रमों के लिए 35,600 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया। उन्होंने महिला विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए 28,600 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया। इसके अलावा, वित्त मंत्री ने 2020-21 के दौरान अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के कल्याण के लिए 85,000 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव दिया। इसी प्रकार वर्ष 2020-21 के दौरान,अनुसूचित जनजाति के विकास कल्याण को आगे बढ़ाने के लिए 53,700 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा कि सरकार वरिष्ठ नागरिकों

एवं दिव्यांगों की समस्याओं से चिंतित है, इसके लिए 2020-21 के लिए 9500 करोड़ रुपये का आवंटन दिया जा रहा है।महिला अधिकारों और उनके स्वास्थ्य की दिशा में मोदी सरकार एक अहम कदम उठा सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किए गए आम बजट में लड़कियों के विवाह की उम्र सीमा बढ़ाने को लेकर एक बड़ा एलान किया गया। सीतारमण ने एलान किया कि सरकार लड़कियों के विवाह और मातृत्व की उम्र सीमा की समीक्षा करेगी। वित्त मंत्री ने इस मामले पर विचार करने और सिफारिश करने के लिए अपने बजट भाषण में एक टॉस्क फोर्स के गठन का एलान किया। इसके अंतर्गत टॉस्क फोर्स को अपने गठन के 6 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी होगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक ऐसा कदम सरकार महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण को ध्यान में रखते हुए उठाने की योजना है। साथ ही, सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि भारत की आर्थिक तरक्की के साथ उच्चतर शिक्षा और कैरियर के नए रास्ते भी खुल रहे हैं। वित्त मंत्री ने इसी संदर्भ में इस मुद्दे पर पुनर्विचार करने की बात कही। सरकार के मुताबिक 2016 में भारत में मातृ मृत्यु दर का आंकड़ा 122 मौत प्रति 1 लाख महिला था। महिला अधिकारों और उनके स्वास्थ्य की दिशा में मोदी सरकार एक अहम कदम उठा सकती है।

1978 में बदला था कानून

भारत में महिलाओं के विवाह की उम्र सीमा पहली बार 1929 में अंग्रेजी शासन काल के दौरान शारदा एक्ट के माध्यम से हुआ था। तब लड़कियों के विवाह की उम्र सीमा 14 वर्ष जबकि पुरुषों की सीमा 18 साल रखी गई थी। हालांकि पहले 1940 और फिर बाद में 1978 में शारदा एक्ट में बदलाव किया गया। 1978 में विवाह की उम्र सीमा महिलाओं के लिए 18 जबकि पुरुषों के लिए 21 तय की गई जो आजतक लागू है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश वित्त वर्ष 2021-22 के आम बजट

> “ वर्तमान दशक के पहले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, विकास निर्माण, रोजगार के अवसर को बढ़ाने पर आवंटित रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना काल के बाद बिगड़ती अर्थव्यवस्था में आनेवाले समय में इस बजट का असर निश्चित रुप में दिखेगा। लेखक व पत्रकार होने के नाते सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में बजट के कुछ सराहनीय योजनाओं का मैं स्वागत करता हूँ।

में में शिक्षा मंत्रालय को 93,224.31 करोड़ रूपए आवंटित किए गए हैं जो चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमानों से 8,100 करोड़ रूपए अधिक है। मैंने इस बजट को लेकर अंग प्रदेश के हृदय स्थल भागलपुर के राजनैतिक,शैक्षणिक,साहित्यिक,सांस्कृतिक व व्यवसायिक संगठन के लोगों से उनकी राय मांगी। प्रस्तुत है उनके बेबाक राय....

इस बजट को लेकर भाजयुमो के राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य सह पूर्व प्रत्याशी भागलपुर विधानसभा अर्जित शाश्वत चौबे ने प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना शुरू होने की घोषणा पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि गांव में स्वास्थ्य की बुनियादी ढांचे को इससे मजबूती मिलेगी। इस अभियान के लिए 64,180 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। 602 जिलों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल शुरू होंगे। 35 हजार करोड़ रुपए कोविड-19 के लिए उपलब्ध कराया गया है।

तो वहीं बिहार कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष सह अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटि के सदस्य प्रवीण सिंह कुशवाहा ने वित्त मंत्री द्वारा पेश किये बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस बजट से आम आदमी और किसानों को ठगा गया है। उनका कहना है कि यह बजट निजीकरण और चुनाव वाले राज्यों को समर्पित बजट है। इस बजट में इनकम टैक्स पेयर्स को कोई राहत नहीं दी गई है, उल्टे इनकम टैक्स की चोरी करने वालों को इस बजट से बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस बजट में किसानों को इनकम बढ़ाने के लिये कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। पूरे देश में मात्र 30 लाख किसानों को ही एमएसपी के दायरे में बढ़ाया गया है। ऊपर से कृषि सेंस के नाम पर डीजल में 4 रु.और पेट्रोल पर 2.50 रु. सेंस लगाकर जनता पर अतिरिक्त बोझ डाला गया है। इस बजट से आम आदमी को कोई राहत नहीं दी गई है। लॉकडाउन में जिन लोगों की नौकरी चली गई उनके लिये भी कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने बताया कि एलआईसी सहित अन्य बीमा कंपनियों में 74% की एफडीआई निजीकरण को बढ़ावा देने वाली व्यवस्था है।इस वर्ष चुनाव वाले राज्यों प. बंगाल,असम,तमिलनाडु,केरल आदि राज्यों में नेशनल हाइवे का प्रोजेक्ट चुनावी राजनीति के तहत दी गई है` 3 साल से अधिक पुरानी इनकम टैक्स की फाइलों को बन्द करना इनकम टैक्स की चोरी को बढ़ावा देगा।देश की सरकारी लाभदायी अच्छी कंपनियों को बेचकर स्रोत इकट्ठा करना सरकार की नाकामी को दशार्ने के लिये काफी है। कुल मिलाकर यह बजट मध्यमवर्गीय, किसानों, गरीब-गुरबों और आम लोगों को निराश करने वाला बजट है।

भागलपुर महानगर जदयू के पूर्व जिलाध्यक्ष सुड्डु सांई ने वित्त मंत्री द्वारा पेश किये गए इस आम बजट का स्वागत किया है। कोरोना महामारी के बाद प्रस्तुत बजट की खूबियों की सराहना करते हुए उन्होंने इस बजट को जनता और देश के हित में बताया।

वहीं भागलपुर- नाथनगर में विकास पुरुष के नाम से चर्चित राजद के कद्दावर नेता पप्पू यादव ने इस बजट को देश बेचने वाला बजट बताया और कहा कि यह बजट नहीं सरकारी प्रतिष्ठानों व संपत्तियों को बेचने की हरेक माल वाली सेल लगी थी। उनका मानना है कि रेल,रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट,लाल किला, बीएसएनएल,एलआईसी बेचने के बाद यह बजट नहीं बल्कि अब बैंक,बंदरगाह,बिजली लाइनें,राष्ट्रीय सड़कें,स्टेडियम, तेल की पाइप लाइन से लेकर वेयरहाउस बेचने का भाजपाई निश्चय योजना है। उन्होंने कहा कि इस बजट में बिहार को कुछ नहीं मिला है। लालू प्रसाद यादव ने बिहार को रेल के तीन चार कारखाने दिए थे लेकिन इस बजट से आम लोगों को निराशा हुई है।

ईस्टर्न बिहार रेडीमेड, होजयरी एसोसिएशन के अध्यक्ष राम गोपाल पोद्दार ने बताया कि

वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 2021-22 के बजट में आधार भूत संरचनाओ पर जोर दिया गया है साथ ही इनमें डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बनाने का ऐलान किया गया है,जिससे आर्थिक विकास बढ़ने की सम्भावना दिखती है। उन्होंने बताया कि आयकर स्लैब में कोई बदलाव नही किया गया है ,जो मध्यम बर्ग को निराश करता है। इसके साथ ही इस बजट में सीनियर सीटिजन के लिये भी किसी

“ बिहार कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष सह अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटि के सदस्य प्रवीण सिंह कुशवाहा ने वित्त मंत्री द्वारा पेश किये बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस बजट से आम आदमी और किसानों को ठगा गया है। उनका कहना है कि यह बजट निजीकरण और चुनाव वाले राज्यों को समर्पित बजट है।

तरह की छूट का प्रावधान नही रखा गया है। खासकर बैंको में जमा राशि पर ब्याज दर को नही बढ़ाया जाना निराशा हुई है। सरकार के इस बजट से मोबाइल,चार्जर,सूती कपड़े,चमड़े के समान महंगे हो जायेंगे।जिसका सीधा असर कम आय वालों पर पड़ेगा।स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में बजट में 137%की बढ़ोतरी से स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में सुधार की उम्मीद की जा सकती है। उनका मानना है कि कुल मिलाकर यह बजट मध्यम बर्ग को निराश करता है।

वहीं भाजपा वाणिज्य प्रकोष्ठ के भागलपुर जिलाध्यक्ष शरद सालारपुरिया ने इस बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इस बजट में नैशनल एजुकेशन पॉलिसी को तहे दिल से स्वीकार किया गया है। उन्होंने बताया कि 100 नए सैनिक स्कूल बनेंगे। इस पर उन्होंने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार जताया है। उन्होंने आगे बताया कि रेलवे के लिए रिकॉर्ड 1,10,055 करोड़ का प्रावधान, सडक परिवहन मंत्रालय के लिए 1,18,101 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान है।असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए एक पोर्टल बनेगा। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए हेल्थ,हाउसिंग और फूड स्कीम शुरू होगी।

भागलपुर भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष संतोष कुमार ने केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट आत्मनिर्भर भारत की नींव तैयार करने में सहायक सिद्ध होगा। बजट नया भारत और आत्मनिर्भर भारत को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। कोरोना महामारी के बीच प्रस्तुत किया गया 2021-22 का यह बजट लोकल फॉर वोकल के मंत्र पर चलने वाला तथा 130 करोड़ भारतीय के हित में है।

वहीं इस केन्द्रीय बजट पर जिला परिषद के पूर्व चेयरमैन सह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉ.शंभू दयाल खेतान ने कहा कि इस बजट से देश की गरीब जनता को कोई लाभ नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि 135 करोड़ जनता के अरमानों पर पानी फेर कर आसन्न पांच राज्यों के विधान सभा चुनाव में राजनैतिक लाभ लेने के लिए पेश किया गया, जो न केवल निंदनीय है वरन भाजपा के संकिर्ण राजनैतिक एवं सत्ता लोलुपता को प्रदर्शित करता है।

वहीं केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश आम बजट पर भागलपुर नगर निगम की.पूर्व उपमहापौर सह भाजपा नेत्री डॉ.प्रीति शेखर ने बधाई देते हुए कहा कि यह बजट अबतक का सर्वश्रेष्ठ बजट है,जिसमें कि सभी क्षेत्रों के गुणात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। यह बजट ऐसी परिस्थितियों में तैयार किया गया है,जो पूर्व में कभी नहीं थी।

वहीं भागलपुर जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष शाह अली सज्जाद ने लोकसभा में वर्ष 2021-22 के लिए पेश आम बजट को पूरी तरह से निराशाजनक,महंगाई बढ़ाने और सिर्फ पूंजीपतियों को ध्यान में रखकर बनाया गया बजट बताया। उन्होंने कहा कि बजट से सबसे बड़ी उम्मीद सैलरी क्लास को रहती है, लेकिन उनकी उम्मीदें भी टूटी हुई है। इस बजट में स्वास्थ्य,शिक्षा,मकान,स्वच्छ पेयजल और सड़क समेत अन्य आधारभूत सुविधा कराने में भी नाकामी हासिल हुई है।

श्रद्धा भारती के संयोजक सह ईस्टर्न बिहार इंडस्ट्रीज ऑफ एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजीव कुमार उर्फ लालू शर्मा ने इस आम बजट पर अपनी राय देते हुए कहा कि इस बजट में नया भारत नई राह की तर्ज पर पेश किया लगता है, जिसमें भारतवर्ष के हर वर्गों पर कुछ न कुछ ध्यान दिया गया है।

साथ ही पंचायती राज किसानों व ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए भी कुछ बातें कही गई है।

इसके साथ ही भारत में लघु उद्योगों, कृषि उत्पादों, कुटीर उद्योगों आदि के लिए भी कई बातें कही गई हैं। कुल मिलाकर इस बजट को एक लंबे समय के लिए बनाया गया है, जिसके लागू होने से इसका प्रभाव तत्काल न होकर आने वाले कुछ वर्षों में कुछ सकारात्मक बातों के साथ नजर आने वाला है। उन्होंने बताया कि आज भारत सरकार द्वारा पेश किया गया यह बजट में नई बातों के तहत नया देश गढ़ने की ओर जा रहा है।

खानकाह-ए- पीर शाह दमड़िया के नायब सज्जादनशीं सैयद शाह फकरे आलम हसन ने एक तरफ कहा कि इस बजट में गरीब-गुरबों व जरुरतमंदों को नजरअंदाज कर उनके लिए कुछ खास ध्यान नहीं रखा गया है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि इस आम बजट में पेंशनरों-जिनकी उम्र 75 साल से ऊपर है को छूट दी गई है यह एक नया और सराहनीय कदम है। सरकार के इस कदम की उन्होंने तारीफ करते हुए कहा कि इससे आजादी के बाद पहली बार इस तरह बुजूर्गों को एक सम्मान दिया गया है।

टेक्सटाइल चैंबर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष सुनील जैन ने कहा कि बजट में छोटे करदाताओं के लिए एक विवाद समाधान समिति का गठन करने का प्रस्ताव किया गया है।यह समिति पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी। ₹5000000 तक कर योग्य आय और 1000000 रुपए तक विवादित आय वाले लोग इस समिति के पास जा सकेंगे।यह एक अच्छा प्रयास है इससे व्यापारियों को लाभ मिलेगा।त्वरित समाधान होगा और अनावश्यक देरी से बचेंगे।

लायंस क्लब के पूर्व जिलापाल कुंजबिहारी झुनझुनवाला कुंज बिहारी झुनझुनवाला ने कहा कि व्यापारियों को इस बजट में कोई विशेष प्रोत्साहन या छूट नहीं दी गई है। जबकि उनके टेक्स्ट से ही किसान श्रमिक मजदूरों को राहत दी जाती है साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स के स्लैब में किसी प्रकार की ना छूट देना भी प्रोत्साहित कदम नहीं है। 65 वर्ष से ऊपर के करदाताओं को भी 75 वर्ष से ऊपर पेंशनरों की तरह छूट मिलनी चाहिए क्योंकि वह भी सीनियर सिटीजन के रूप में अपना व्यवसाय करते हैं।

गांधी शांति प्रतिष्ठान से जुड़ीं 75 वर्षीय लाभार्थी प्यारी देवी ने इस बजट की सराहना करते हुए कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के बाद इस तरह देश में बुजुर्गियत को सम्मान देकर वर्तमान केन्द्र सरकार ने देश के मान-सम्मान को बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों का सम्मान हमारे सुसंस्कारी को साबित करता है।

वहीं इसी गांधी शांति प्रतिष्ठान के अध्यक्ष प्रकाश चंद्र गुप्ता ने कहा कि लोक लुभावन परंतु क्रांतिकारी नहीं है यह बजट। इस बजट मेर बुनियादी विकास पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। इससे बीमा व बैंकिंग को ज्यादा लाभ होगा और आवासीय ऋण लेने वालों को भी राहत यह राहत पहूंचाएगा। उन्होंने बतायाकि इस बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं होना मध्यम वर्ग को राहत नहीं दिखाता है। महंगाई का भी बोलबाला रहेगा क्योंकि पेट्रोल और डीजल पर टैक्स पहले से ही ज्यादा था, इसे और बढ़ा दिया गया है।

> **“ खानकाह-ए- पीर शाह दमड़िया के नायब सज्जादनशीं सैयद शाह फकरे आलम हसन ने एक तरफ कहा कि इस बजट में गरीब-गुरबों व जरुरतमंदों को नजरअंदाज कर उनके लिए कुछ खास ध्यान नहीं रखा गया है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि इस आम बजट में पेंशनरों-जिनकी उम्र 75 साल से ऊपर है को छूट दी गई है यह एक नया और सराहनीय कदम है।**

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया विरोधियों को एक्सपोज

जितेन्द्र कुमार सिन्हा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपनी शासनकाल में देश के आम जनता को अपना मानता है, इसलिए 26 जनवरी को किसान आन्दोलनकारियों ने ट्रेक्टर रैली के नाम पर जितनी आसानी से लाल किले पर झंडा लहरा दिया, ऐसा नहीं होता, क्योंकि यदि देश के शासक चाहता तो आन्दोलनकारियों को चार कदम भी हिलने नहीं देता।

यह सोंचने का विषय है कि देश में मेरी समझ से यह पहलीवार है कि देश की चुनी हुई सरकार को देश की अन्य राजनीतिक पार्टियाँ तानाशाह सरकार साबित करने में लगी हुई है जबकि सरकार ने उसकी हर प्रयास को विफल कर दिया है, चाहे राफेल हो या शाहीन बाग, तीन तलाक हो या धारा- 370, चीन-भारत बॉडर हो या किसान आन्दोलन, सभी में विरोधियों को एक्सपोज किया है। सरकार ने विरोधियों की अराजकता को पूरी दुनियाँ के सामने दिखा दिया गया है कि आप एक पेड आन्दोलन में शामिल थे।

26 जनवरी को लाल किला की जो घटना हुई इसे अगर विरोधी समझता है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को एक्सपोज कर दिये हैं तो यह उनकी भूल होगी, क्योंकि सरकार ने आपको एक्सपोज कर दिया है कि किस प्रकार नेशनल डे तक किसी भी आंदोलन को खींचा जाता है और उसे शाहीन बाग जैसी घृणित आंदोलन की शक्ल दी जाती है। सरकार ने क्रियाकलाप का भीषण विरोध भी नही किया और यह संदेश भी दे दिया कि आप अराजक हो।

लाल किला के सड़कों पर जिस तरह से तलवारें लहराई गयी, जिस तरह से ईंट पत्थर फेंके गए, ट्रैक्टर से पुलिस वालों को कुचलने की कोशिश की गई, इन सब चीजों को जनता चैनलों के माध्यम से सीधा देखी है। इस सरकार में भाग्यशाली हैं लोग जिनकी उदंडता को भी सरकार सर माथे लगाया करता है ।

यह सोंच कर डर लगता है कि कहीं जिहादी इस आंदोलन में घुसकर और ज्यादा उत्पात न मचा दें, क्योंकि अभी तक खून खराबा नहीं हुआ है। विरोधियों

> “ 26 जनवरी को लाल किला की जो घटना हुई इसे अगर विरोधी समझता है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को एक्सपोज कर दिये हैं तो यह उनकी भूल होगी, क्योंकि सरकार ने आपको एक्सपोज कर दिया है कि किस प्रकार नेशनल डे तक किसी भी आंदोलन को खींचा जाता है और उसे शाहीन बाग जैसी घृणित आंदोलन की शक्ल दी जाती है। सरकार ने क्रियाकलाप का भीषण विरोध भी नही किया और यह संदेश भी दे दिया कि आप अराजक हो।

कि सोच रही हो कि सरकार इनका खूब विरोध करेगी और सैकड़ो लोगों की लाशें गिरेगी, जिससे लोग सरकार द्वारा किये गए सारे अच्छे कार्यों को भूला देगी और वर्षो तक इस दिन को काला दिवस के रूप में मनाया जायेगा।

हमलोग बचपन में किताब में पढ़ा था कि राजा समस्त प्रजा के लिए पिता समान होता है। इस बात को लगता है कि प्रधानमंत्री ने 26 जनवरी की उदंडता को माफ कर के अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है।

लेकिन अगर जिहादी इसमे घुसकर उत्पात मचाये तो उन्हें भीषणतम दंड देना भी राजा का कर्तव्य होता है।

ऐसा उम्मीद किया जा सकता है कि प्रधानमंत्री अपने इस कर्तव्य का भी निवर्हन करेंगे।

लाल किले पर झंडा फहराए जाने को ऐसा समझना चाहिए कि हमारे देश में कृष्ण युग है। कृष्ण युग में शिशुपाल को 99 तक माफ किया गया था, जहाँ कालयवन को स्वयं न मारकर राजा मुचुकुन्द की दृष्टि से मरवाया गया था। अभी के समय में कालयवन पेड आंदोलनकारी को माना जा सकता है और राजा मुचुकुंद देश की जनता को।

अब थोरा सोचीये की 20 साल से हम लोग इंपोर्टेड दाल खा रहे थे। 2 साल पहले मोदी ने इस पर रोक लगानी शुरू कर दी और अब पूरी तरह से बंद कर दिया। कृषि बिल तो बहाना है, सही बात तो यह है की 2005 में मनमोहन सरकार में दाल पर दी जा रही सब्सिडी को खत्म कर दी गई। उसके 2 साल के बाद मनमोहन सरकार ने नीदरलैंड ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से समझौता कर दाल आयात करना शुरू कर दिया। कनाडा ने अपने यहां लेंटील दाल के बड़े-बड़े फार्म स्थापित किए जिसकी जिम्मेदारी वहां रह रहे पंजाबी सिखों के पास था। कनाडा से भारत में बड़े पैमाने पर दाल आयात होने लगा। वर्त्तमान सरकार ने आयात पर रोक लगा दी, जिससे कनाडा के फार्म सूखने लगे।खालिस्तानियों की नौकरी जाने लगी इसीलिए जस्टिन ट्रुडो ने किसानों के आंदोलन का समर्थन किया था। कनाडा के खालिस्तानी सिखों को पंजाब वापस भेजा जाएगा। इसलिए कृषि कानून का सबसे ज्यादा विरोध विदेशी ताकते और खालिस्तानी सिख कर रहे है।

प्रधानमंत्री ने भारत को विकसित करने का बीडा उठाया है और जनता भी साथ दे रही है, जल्द ही भारत की आर्थिक हालत विश्व मे सबसे अच्छी होगी क्योंकि जिस देश में अन्न बाहर से खरीदना नहीं पड़ता वही देश सबसे जल्द् विकसित होते है। अब भारत का किसान अमीर होगा तो इन्हें तो कष्ट होगा ही।

“अब थोरा सोचीये की 20 साल से हम लोग इंपोर्टेड दाल खा रहे थे। 2 साल पहले मोदी ने इस पर रोक लगानी शुरू कर दी और अब पूरी तरह से बंद कर दिया। कृषि बिल तो बहाना है, सही बात तो यह है की 2005 में मनमोहन सरकार में दाल पर दी जा रही सब्सिडी को खत्म कर दी गई। उसके 2 साल के बाद मनमोहन सरकार ने नीदरलैंड ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से समझौता कर दाल आयात करना शुरू कर दिया।

विकास के पथ पर बड़ी मजबूती के साथ टिकी हुई है देश की अर्थव्यवस्था

महामारी को नियंत्रण में रखने के लिए समय पर लागू किए गए विभिन्नउपायों, बड़े पैमाने पर मौद्रिक विस्तार करने और व्यापक राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज की बदौलत ही देश की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2021 में मंदी की गिरफ्त में आने से बच पाई है

राजीव मिश्रा

आर्थिक सलाहकार,वित्त मंत्रालय
(ये लेखक के निजी विचार हैं)

आर्थिक समीक्षा में अर्थव्यवस्था की स्थिति (एसओई) 2020-21 -व्यापक नजरिया शीर्षक वाले विशेष अध्याय में कोविड काल की भारतीय अर्थव्यवस्था का अत्यंत सहज विवरण पेश किया गया है। इसमें बताया गया है कि सरकार द्वारा समय पर उठाए गए प्रभावकारी नीतिगत कदमों की मदद से सबसे पहले तो देश की जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) में दर्ज की गई तेज ऋणात्मक गिरावट को सफलतापूर्वक अत्यंत सीमित किया गया और फिर ठीक इसके बाद ही जीडीपी में 'वी' आकार में निरंतर बेहतरी हासिल की गई। इसके साथ ही इस अध्याय में उन सरकारी नीतियों से मिलने वाले अभिनव मजबूत सहारे का भी उल्लेख किया गया है जिनका उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था को महामारी से पहले के तेज विकास वाले पथ पर फिर से अग्रसर करना है।

एसओई में महामारी का प्रकोप शुरू होने के समय पूरी दुनिया के सामने उत्पन्न हुई जीवन बनाम आजीविका की उस नीतिगत दुविधा का भी उल्लेख किया गया है जिसके तहत समस्त देश इन दोनों में से किसी एक का चयन करने पर विवश हो गए थे। जहां तक भारत सरकार का सवाल है, इसने महामारी को नियंत्रण में रखने की रणनीति को अपनाते हुए सबसे पहले लोगों की जिंदगियां बचाने पर ही फोकस किया, लेकिन महामारी से निपटने की कारगर व्यवस्था हो जाने के बाद इसने जल्द ही लोगों की आजीविकाओं को बनाए रखने पर भी अपना ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। इसका मुख्य उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था को अनलॉक करने की प्रक्रिया में तेजी लाना था। इसके अत्यंत अच्छे नतीजे देखने को मिले। इसकी बानगी आपके सामने है। वित्त वर्ष 2021 की प्रथम तिमाही में जीडीपी में सालाना आधार पर 23.9 प्रतिशत की तेज ऋणात्मक गिरावट दर्ज की गई थी, जबकि दूसरी तिमाही में यह गिरावट काफी कम होकर 7.5 प्रतिशत के स्तर पर आ गई। यही नहीं, इसके बाद महामारी से जुड़े संक्रमण के मामले भी निरंतर घटते चले गए। यह सब कुछ लॉकडाउन को बिल्कुल सही समय पर लागू करने और अनलॉकिंग की प्रक्रिया को क्रमिक रूप से धीरे-धीरे आगे बढ़ाने से ही संभव हो

> एसओई में महामारी का प्रकोप शुरू होने के समय पूरी दुनिया के सामने उत्पन्न हुई जीवन बनाम आजीविका की उस नीतिगत दुविधा का भी उल्लेख किया गया है जिसके तहत समस्त देश इन दोनों में से किसी एक का चयन करने पर विवश हो गए थे। जहां तक भारत सरकार का सवाल है, इसने महामारी को नियंत्रण में रखने की रणनीति को अपनाते हुए सबसे पहले लोगों की जिंदगियां बचाने पर ही फोकस किया।

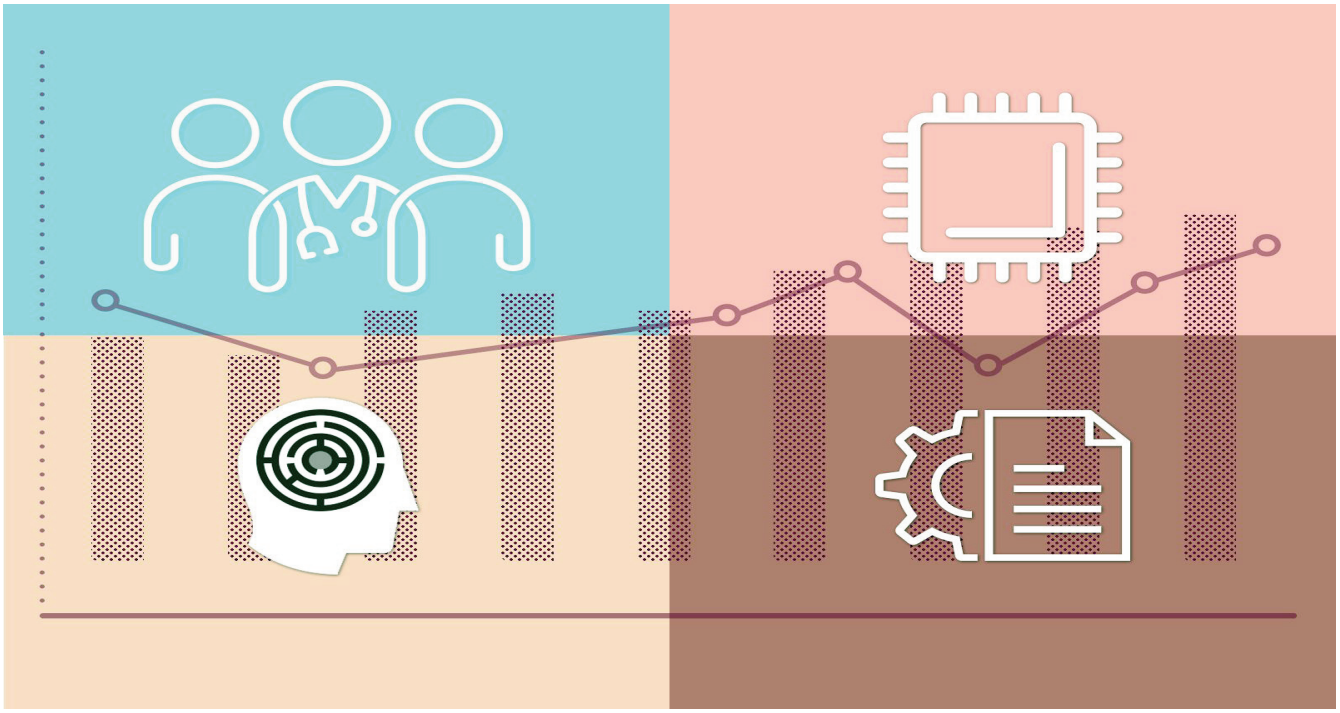

पाया। इतना ही नहीं, इसकी बदौलत भारत अन्य देशों की तुलना में काफी पहले ही उपर्युक्त नीतिगत दुविधा से बाहर निकल पाया। एसओई में जिस मौद्रिक रणनीति की चर्चा की गई है वह उधारी लागत कम करके और तरलता या नकदी प्रवाह बढ़ाकर कारोबारियों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए आरबीआई द्वारा किए गए विभिन्न उपायों से जुड़ी हुई है। आरबीआई ने नीतिगत दरों में कटौती की, खुले बाजार एवं दीर्घकालिक रेपो परिचालन की शुरूआत की, बैंकों के सीआरआर को कम किया, बैंकों की उधारी सीमाएं बढ़ाईं, सावधि ऋणों पर मोहलत दी एवं ब्याज अदायगी को स्थगन किया, सरकारों के अथोर्पाय अग्रिम को बढ़ाया, इत्यादि। नीतिगत दरों में उल्लेखनीय कटौती दरअसल इस रणनीति की खासियत प्रतीत होती है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप पूंजी के देश से बाहर जाने का खतरा था। हालांकि, महामारी से उत्पन्न आर्थिक सुस्ती से स्वयं को बाहर निकालने के लिए विकसित देशों द्वारा वैश्विक स्तर पर तरलता या नकदी प्रवाह की भरमार कर देने से पूंजी के भारत से बाहर जाने का खतरा टल गया। दरअसल, उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में दिख रही तेज विकास की संभावनाओं के मद्देनजर विशेषकर भारत अपने यहां पूंजी को निरंतर आकर्षित करता रहा है।

महामारी से निपटने के लिए अपनाई गई राजकोषीय रणनीति के तहत शुरूआत में देश की आबादी के कमजोर वर्गों को एक सुरक्षा कवर प्रदान किया गया जिसमें स्वास्थ्य संबंधी सहायता, खाद्य आपूर्ति, नकदी का हस्तांतरण, ऋण गारंटी, ब्याज संबंधी सब्सिडी और कर स्थगन, इत्यादि शामिल थे। राजकोषीय रणनीति के तहत किए जा रहे फोकस को वर्ष के उत्तरार्द्ध में बदल कर उपभोग या खपत बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। जैसा कि एसओई में विस्तार से बताया गया है, राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज का आकार बढ़ाने की जरूरत इसलिए महसूस की गई, ताकि बढ़ती निजी उपभोग मांग के साथ सामंजस्य स्थापित किया जा सके। अनिश्चितता के प्रारंभिक दौर में निजी उपभोग मांग कम थी और यह मुख्यतः आवश्यक खर्चों तक ही सीमित थी क्योंकि लोग सावधानी बरतते हुए अपनी बचत राशि को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। तदनुसार, आवश्यक खपत या उपभोग को पूरा करने के लिए ही राजकोषीय व्यय सुनिश्चित किया गया। जैसे ही लॉकडाउन में ढील देने से अनिश्चितता दूर हुई, लोगों ने गैर-आवश्यक उपभोग पर खुलकर खर्च करना शुरू कर दिया। आर्थिक विकास की गति तेज होने पर अतिरिक्त राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज की आवश्यकता महसूस होने लगी, ताकि अर्थव्यवस्था में दिख रही बेहतरी के शुरूआती लक्षण को मजबूती प्रदान की जा सके। अतः निजी उपभोग में बदलाव के अनुरूप ही आवश्यक राजकोषीय उपाय करने से राजकोषीय संसाधनों की बबार्दी को रोकना सुनिश्चित किया जा सका।

एसओई में इसके साथ ही अर्थव्यवस्था की विकास क्षमता में नई जान फूंकने में ढांचागत सुधार की अहम भूमिका के बारे में बताया गया है। सरकार द्वारा घोषित प्रमुख सुधारों में कृषि उपज के विपणन में किसानों को आजादी देना, विकास एवं रोजगार सृजन में आवश्यक सहयोग देने के लिए एमएसएमई की परिभाषा में परिवर्तन करना, चार श्रम संहिताओं को कानून का रूप देना, क्रॉस-पावर सब्सिडी को कम करना, सार्वजनिक उपक्रमों (पीएसयू) का विनिवेश और कोयले के वाणिज्यिक खनन का मार्ग प्रशस्त करना शामिल थे। पिछले 6-7 वर्षों में लागू किए गए सुधारों के साथ-साथ इन सुधारों का भी उद्देश्य निजी क्षेत्र के निवेश के मार्ग में मौजूद बाध्यकारी अवरोधों को कम करना है।

एसओई में उल्लेख किए गए आर्थिक आउटलुक में वित्त वर्ष 2021-22 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 11 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। इसी तरह आईएमएफ ने जनवरी 2021 के अपने अपडेट में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 11.5 प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया है। ये पूवार्नुमान दरअसल वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी वृद्धि दर की संभावनाओं को ध्यान में रखते ही लगाए गए हैं जिसके प्रथम छमाही के (-)19.4 प्रतिशत से काफी सुधर कर दूसरी छमाही में (+)23.9 प्रतिशत हो जाने का अनुमान लगाया गया है। यहां तक कि प्रथम छमाही में ही जीडीपी वृद्धि दर प्रथम तिमाही के (-)29.3 प्रतिशत से काफी सुधर कर दूसरी तिमाही में (+) 23.2 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गई है। जीडीपी की क्रमिक वृद्धि दरों में इस तरह की आकर्षक छलांग निश्चित रूप से किसी भी अर्थव्यवस्था में मंदी के व्याप्त होने को प्रतिबिंबित नहीं करती है। इसके ठीक विपरीत ये आंकड़े यही दशार्ते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था बड़ी मजबूती के साथ पटरी पर टिकी हुई है जो सरकार द्वारा महामारी को नियंत्रण में रखने के लिए लागू किए गए विभिन्न उपायों, व्यापक मौद्रिक विस्तार, राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज और ढांचागत सुधारों की बदौलत ही संभव हो पाया है।

> “ महामारी से निपटने के लिए अपनाई गई राजकोषीय रणनीति के तहत शुरूआत में देश की आबादी के कमजोर वर्गों को एक सुरक्षा कवर प्रदान किया गया जिसमें स्वास्थ्य संबंधी सहायता, खाद्य आपूर्ति, नकदी का हस्तांतरण, ऋण गारंटी, ब्याज संबंधी सब्सिडी और कर स्थगन, इत्यादि शामिल थे। राजकोषीय रणनीति के तहत किए जा रहे फोकस को वर्ष के उत्तरार्द्ध में बदल कर उपभोग या खपत बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

नर और नारी के बिना सृष्टि अधूरा है

आभा सिन्हा

'मातृदेवो भव' माता ही सर्वोपरि है। जीवन में माता ही परवरिश का प्रथम गुरू है। मानव के जीवन का पहला आवास गर्भ होता है, जहाँ गर्भरूपी वस्त्र और भोजन मिलता है। ऐसी माता हीं सर्वप्रथम जीवन में बालिका होती है। ऐसे भी देखा जाय तो सृष्टि में नर और नारी के बिना सृष्टि अधूरा है। समाज में धरती को स्त्री और आकाश को पुरूष माना जाता है। उसी प्रकार सूर्य को पुरूष और चंद्रमा को स्त्री कहते है। वहीं सागर को पुरूष और नदियाँ को स्त्री कहते हैं।

वर्त्तमान समय में बालिकाओं के लिए व्यापक प्रबंध होने से कुरीतियों पर कुठाराघात हो रहा है। आज पूरे देश में, गाँव-गाँव में बालिकायें निर्भीक होकर साइकिल चलाकर स्कूल जाने लगीं हैं। इसे परिवर्त्तन की ताजा हवा कहा जाता है। अब बालिकाओं के लिए गाँव-गाँव में शिक्षा का प्रचार और प्रशिक्षण का प्रबंध होना चाहिए ताकि बालिकाओं में शक्ति का संचार हो।

यह सही है कि प्रत्येक प्राणवान वस्तु, स्त्री और पुरूष में विभाजित है। भौगोलिक रूप से पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। वहीं सूर्य सम्पूर्ण आकाश-गंगा को आलोकित करती हैं, जिससे सूर्य का अस्तित्व पृथ्वी से ही प्रमाणित होता है। इसी तरह स्त्री की महत्ता भी है जो बालिका होने से ही प्रारंभ होती है। बालिका हीं विकसित हो कर माँ बनती है। जब बालिका रहेगी तभी हम माँ को बचा पायेंगे।

तकनीकी युग में तकनीक हमें समृद्ध करने के लिए बनाई गई है, लेकिन हमलोग इसी तकनीक का दुरुपयोग कर बालिकाओं की संख्या कम करने में लगे है, इसलिए लगता है कि यह तकनीक विनाश का कारण बन गया है। भारत में जहाँ स्त्री को देवी का दर्जा दिया गया है वहीं उसे आज कई जगहों पर मात्र संतानोत्पत्ति का उपकरण माना जा रहा है। यह सही है कि भारत पुरुष प्रधान देश है, लेकिन पुरूषवादी व्यवस्था यह भूल जाते हैं कि कुलवंश की वृद्धि बिना स्त्री के सम्पूर्ण नहीं हो सकता है। तकनीक तो एक कारण है हीं, साथ ही दहेज प्रथा भी इसका एक कारण है। जिसके कारण लोगों में मात्र पुत्र की आकांक्षा उत्पन्न हो रही है, इसलिए लोग नई तकनीक के माध्यम से गर्भ के लिंग की जाँच करा गर्भ को नष्ट कर देते हैं। जबकि यह एक जघन्य अपराध है। अब तो इन जघन्य पापों से बची हुई लड़कियाँ भी सुरक्षित नहीं रहतीं। शिशु से लेकर वयस्क लड़की कहाँ सुरक्षित है? आये दिन जबर्दस्ती की दिल दहला देने वाली घटनायें होती रहती हैं। ऐसी घटनाओं से डरे हुए लोग भी लड़की को जन्म ही नहीं होने देना चाहते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में कंधों से कंधे मिलाकर महिलाओं/बालिकाओं ने भी भाग लिया था। उदाहरण के लिए रानी लक्ष्मी बाई, बनमाला बोस, जिन्होंने अपने जान की बाजी लगाई थी। भारत में केन्द्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल की बागडोर भी महिलाएँ ने सम्भाली थी।

जब प्रधानमंत्री की कुर्सी इन्दिरा गाँधी के हाथ में आई तब एक सशक्त प्रधानमंत्री के रूप में महिला की ख्याति प्राप्त हुई। आज तो बालिकाओं ने देश की सेवा में सेनाओं के साथ भी डटकर खड़ी है। भारत में बालिका को लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा के रूप में भी जाना जाता है। लोग यह भूल रहे हैं कि समाज की आँखों में आँखें डालकर बालिकायें बता रही हैं कि मैं हर जगह परचम लहराऊँगी। इसलिए बुद्धिजीवीओं को सोचना पड़ेगा कि समाज को, जन जन को किसी तरह शिक्षित प्रशिक्षित किया जाय ताकि बलात्कार और हत्या जैसा जघन्य अपराध बंद हो सके। भारतीय बालिकायें किसी से कम नहीं है। उनके हाथों में जिसकी बागडोर थमाई जाय, वह बखूबी कुछ उत्कृष्ट करके दिखा देती हैं। आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहाँ स्त्री कार्यरत नहीं है। देश की आतंरिक सुरक्षा यानी पुलिस, बाह्य सुरक्षा यानि सेना सभी स्थान पर बालिकायें बखूबी काम सँभाल रही हैं।

> “तकनीकी युग में तकनीक हमें समृद्ध करने के लिए बनाई गई है, लेकिन हमलोग इसी तकनीक का दुरुपयोग कर बालिकाओं की संख्या कम करने में लगे है, इसलिए लगता है कि यह तकनीक विनाश का कारण बन गया है। भारत में जहाँ स्त्री को देवी का दर्जा दिया गया है वहीं उसे आज कई जगहों पर मात्र संतानोत्पत्ति का उपकरण माना जा रहा है।

बिहार के डाकघरों में मखाना की बिक्री शुरू

बिहार के मधुबनी प्रान्त का प्रसिद्ध मखाना अब आपके नजदीकी डाकघर में उपलब्ध हो गया हैकबिहार के डाकघरों में आज से मखाना के भिन्न उत्पादों की बिक्री का शुभारंभ अनिल कुमार, चीफ पोस्टमास्टर जनरल, बिहार सर्किल के द्वारा किया गया कबिहार के मिथिला के मखाना की मांग देखते हुए बिहार डाक परिमंडल ने बिहार प्रदेश के चुनिन्दा डाकघरों के माध्यम से मखाना उपलब्ध करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत बिहार डाक परिमंडल एवं मिथला नेचुरल्स, मधुबनी के बीच समझौता किया गया है।

चीफ पोस्टमास्टर जनरल, बिहार सर्किल अनिल कुमार ने बताया की मखाना को फॉक्स नट या कमल का बीज भी कहा जाता है। प्राचीन काल से मखाना को पर्वों में उपवास के समय खाया जाता है। मखाना से मिठाई, नमकीन और खीर भी बनाया जाता है । मखाना पौष्टिकता से भरपूर होता है, क्योंकि इसमें मैग्नेशियम, पोटाशियम, फाइबर, आयरन, जिंक आदि भरपूर मात्रा में होते हैं। इसे आर्गेनिक हर्बल भी कहते हैं, क्योंकि यह बिना किसी रासायनिक खाद या कीटनाशक के उपयोग से उगाया जाता है।

उन्होंने कहा कि सभी प्रकार के मखाना प्रोडक्ट्स जैसे मखाना खीर, मखाना इंस्टेंट मिल्क शेक ,फूल मखाना, मखाना लाबा इत्यादि, अंकित मूल्य से 10% की भारी छूट के साथ चुनिंदा डाकघरों में उपलब्ध कराए जा रहे हैं कये सारे प्रोडक्ट्स अब आप चुनिंदा डाकघरों से खरीद सकते हैं, साथ ही आप घर बैठे डाकिया के माध्यम से भी मंगवा सकते हैं।

मखाना का दुनिया भर में काफी मांग है और इस मांग को देखते हुए बिहार डाक परिमंडल एवं मिथला नेचुरल्स, मधुबनी के बीच एक समझौता हुआ है , जिसमे विभिन्न प्रकार के मखाना प्रोडक्ट्स जैसे मखाना खीर, मखाना इंस्टेंट मिल्क शेक ,फूल मखाना, मखाना लाबा इत्यादि और इसके साथ भिन्न प्रकार का आचार जैसे आम ,कटहल,मिर्चीं ,लहसुन,इमली इत्यादि का आचार भी बिक्री के लिए उपलब्ध करायें जाएँगे कये सारे प्रोडक्ट्स अब आप नजदीकी डाकघर से खरीद सकते है साथ ही आप घर बैठे डाकिया के माध्यम से भी मंगवा सकते है कमखाने में 9.7% आसानी से पचनेवाला प्रोटीन, 76% काबोर्हाईड्रेट, 12.8% नमी, 0.1% वसा, 0.5% खनिज लवण, 0.9% फॉस्फोरस एवं प्रति 100 ग्राम 1.4 मिलीग्राम लौह पदार्थ मौजूद होता है। डाकघरों में ये सारे प्रोडक्ट्स पर अंकित मूल्य पर दस प्रतिशत की छुट पर उपलब्ध होगा।

मखाना बिक्री के शुभारंभ के अवसर पर सचिदानन्द प्रसाद, जी०एम० (फाइनेंस), अनिल कुमार, पोस्टमास्टर जनरल, पूर्वी प्रक्षेत्र, भागलपुर, पंकज कुमार मिश्र, निदेशक डाक सेवाएं (मुख्यालय), बिहार परिमंडल, पटना, पवन कुमार, निदेशक, पूर्वी प्रक्षेत्र, भागलपुर, हम्माद जाफर, सतर्कता अधिकारी, बिहार परिमंडल, पटना, रास बिहारी राम, मुख्य डाकपाल, पटना जी०पी०ओ०, सत्य रंजन, सहायक निदेशक(बी०डी०) बिहार परिमंडल, पटना एवं मिथिला नेचुरल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष आनंद एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित थे।

“ मखाना का दुनिया भर में काफी मांग है और इस मांग को देखते हुए बिहार डाक परिमंडल एवं मिथला नेचुरल्स, मधुबनी के बीच एक समझौता हुआ है , जिसमे विभिन्न प्रकार के मखाना प्रोडक्ट्स जैसे मखाना खीर, मखाना इंस्टेंट मिल्क शेक ,फूल मखाना, मखाना लाबा इत्यादि और इसके साथ भिन्न प्रकार का आचार जैसे आम ,कटहल,मिर्चीं ,लहसुन,इमली इत्यादि का आचार भी बिक्री के लिए उपलब्ध करायें जाएँगे कये सारे प्रोडक्ट्स अब आप नजदीकी डाकघर से खरीद सकते है ।

गणतंत्र दिवस लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य करने की प्रेरणा देती है

जितेन्द्र कुमार सिन्हा

गणतंत्र दिवस हमें संविधान की रक्षा, देश की एकता, अखंडता, सम्प्रभुता, धर्मनिरपेक्षत एवं अन्य उच्च लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य करने की प्रेरणा देती है। आज का दिन हमें राष्ट्रीय नवनिर्माण में पारस्परिक शान्ति, साम्प्रदायिक सद्भाव के साथ राष्ट्र के विकास के लिए उत्प्रेरित करता है। 26 जनवरी, 1950 से लगातार गणतंत्र एवं गणतांत्रिक मूल्यों को प्रौढ़ बनाया गया है।, फिर भी अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए अभी भी लम्बी यात्रा तय करनी है।

महाभारत के अनुसार महाभारत संग्रामकाल में विशाल भूखण्ड पर राजतंत्रीय शासन व्यवस्था राज्यों के अतिरिक्त बहुत से गणतंत्री व्यवस्था वाले राज्य भी थे, जिसमें आग्रेय गणराज्य, मालव गणराज्य, यौधेय गणराज्य, कम्बोज गणराज्य, त्रिगत गणराज्य, प्रश्कन्व गणराज्य, गुरु गणराज्य, दक्ष गणराज्य, औदुम्बर गणराज्य, निसा गणराज्य, अम्बष्ठ गणराज्य, पांचाल गणराज्य, कुरु गणराज्य, शिवि (उसीनर) गणराज्य, मधमत गणराज्य, शूद्रक गणराज्य, हस्तिनायक गणराज्य, आशवायन गणराज्य, आसवकायन गणराज्य, अजुर्नायक गणराज्य, प्राज्रुन गणराज्य, खर्परिक गणराज्य, सनकनिक गणराज्य एवं काक गणराज्य प्रमुख हैं। ये सभी गणराज्य का अस्तित्व पश्चिमोत्तर भारत में बुद्धकाल के बाद तक ही नही, बल्कि ग्रीक मसेडोनियन राजा एलेक्जेंडर के आक्रमण काल तक था।

26 जनवरी को स्वाधीनता की ली गई प्रतिज्ञा व्यर्थ नहीं गई। 1930 से लेकर 1947 तक हर वर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है। स्वाधीनता के बाद 1950 में जब भारत एक सम्पूर्ण प्रभुतासम्पन्न गणराज्य बना तब उसके लिए भी 26 जनवरी का हीं दिन चुना गया। 26 जनवरी, 1950 को भारतीय गणतंत्र की स्थापना हुई और विशाल भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति डॉ राजेन्द्र प्रसाद बने थे। इस प्रकार 26 जनवरी, 1930 को लिए गए स्वाधीनता दिवस की प्रतिज्ञा 26 जनवरी, 1950 में पूरी हुई।

हमारे गणतंत्र में 8 संहित है, जिसमें सम्प्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, प्रजातंत्र, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा है।

इसके अतिरिक्त हमारे गणराज्य को समझने के लिए अधिक स्पष्ट, वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ एवं आनुभविक विवेचना भी किया गया है। देश के गणराज्य को अंग्रेजी में रिपब्लिक (फ्रद्धवइछक्क) कहते हैं। रिपब्लिक के प्रत्येक लेटर का अर्थ निम्न प्रकार है- फ रे ऑफ रेनआंसा (पुनर्जागरण की किरण), क इम्फेसीस ऑन एडुकेशन (शिक्षा पर जोर), ढ- पिलर ऑफ पौलिसी (नीति के स्तंभ), व- अरज फॉर यूनिटी (एकता के प्रति आग्रह), इ- बेस बाई बैलोट (मत का आधार), छ- लैम्प ऑफ लिबर्टी (स्वतंत्रता का चिराग), क आइडिया ऑफ इंडिव्यूडियलिटी (व्यक्तिकता की धारणा), उ- कन्सर्न फॉर कॉन्स्टिट्यूशन (संविधान का महत्व)।

देश के गणतंत्र के सम्बंध में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा है कि- "यदि गणतंत्र को विकृत न किया जाय तो वह संसार की सबसे अच्छी चीज बनी रहेगी।" 26 जनवरी हमारे राष्ट्र का एक पुनीत पर्व है। अनन्त बलिदानों, अवदानों की पावन स्मृति को लेकर यह दिन हमारे समक्ष सुरभित भाव से उपस्थित होता है।

“ 26 जनवरी को स्वाधीनता की ली गई प्रतिज्ञा व्यर्थ नहीं गई। 1930 से लेकर 1947 तक हर वर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है। स्वाधीनता के बाद 1950 में जब भारत एक सम्पूर्ण प्रभुतासम्पन्न गणराज्य बना तब उसके लिए भी 26 जनवरी का हीं दिन चुना गया। 26 जनवरी, 1950 को भारतीय गणतंत्र की स्थापना हुई ।

सबके बराबर, कम किसी से नहीं, सशस्त्र बलों में महिलाओं के लिए समान अवसर

डॉ. अजय कुमार

रक्षा सचिव

वैसे तो, भारतीय रक्षा बलों में महिलाओं का प्रवेश ब्रिटिश भारत के समय से ही अलग-अलग स्तर पर रहा है, उनकी भूमिका नर्सिंग और चिकित्सा अधिकारियों से संबंधित ज्यादा थी या तैनाती के दौरान सैनिकों, परिवार और जनता की देखभाल करने की जिम्मेदारी होती थी। हालांकि, शारीरिक विशेषताओं और मातृत्व को लेकर भारतीय सशस्त्र बलों के कुछ वर्गों की चिंताओं के कारण महिलाओं को समान अधिकारनहीं मिले थे।

सरकार ने महिलाओं को भारतीय रक्षा बलों के गौरवान्वित और आवश्यक सदस्यों के रूप में मान्यता दी है और सामर्थ्य, जो उनके भीतर मौजूद होती है। इस प्रकार से पिछले छह वर्षों में सरकार ने भारतीय रक्षा बलों में महिलाओं को ज्यादा अवसर देने के साथ-साथ महिलाओं और पुरुषों के लिए सेवा की शर्तों में समानता लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। आज भारतीय रक्षा बलों के भीतर महिलाएं काफी सशक्त हैं, चाहे वह भारतीय सेना हो, भारतीय नौसेना या भारतीय वायु सेना। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के शब्दों में सरकार का यह दृष्टिकोण स्पष्ट होता है, 'भारत सरकार हमारे सशस्त्र बलों में 'स्त्री शक्ति' को मजबूत करने के लिए काम कर रही है और हम इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं।'

स्वतंत्रता मिलने के बाद, 1992 में महिला विशेष प्रवेश योजना (डब्ल्यूएसईएस) के माध्यम से भारतीय सेना में महिला अधिकारियों की भर्ती शुरू हुई। फरवरी 2019 में, सेना ने आठ वर्गों में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन प्रदान किया, जो हैं सिग्नल्स इंजीनियर, आर्मी एविएशन, आर्मी एयर डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर, आर्मी सर्विस कोर, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर और इंटेलिजेंस। इससे पहले जेएजी और एईसी स्ट्रीमों के लिए 2008 में मंजूरी दी गई थी। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि महिलाओं अधिकारियों और उनके पुरुष समकक्षों के लिए सेवा की अलग-अलग शर्तें हटा दी जाएं। भारतीय सेना में महिलाएं आगे बढ़कर नेतृत्व कर रही हैं।

यहां तक कि भारतीय नौसना में, 2008 से ही शिक्षा शाखा, कानून और

> सरकार ने महिलाओं को भारतीय रक्षा बलों के गौरवान्वित और आवश्यक सदस्यों के रूप में मान्यता दी है और सामर्थ्य, जो उनके भीतर मौजूद होती है। इस प्रकार से पिछले छह वर्षों में सरकार ने भारतीय रक्षा बलों में महिलाओं को ज्यादा अवसर देने के साथ-साथ महिलाओं और पुरुषों के लिए सेवा की शर्तों में समानता लाने के लिए कई कदम उठाए हैं।

नौसेना कंस्ट्रक्टर्स कैडर्स में महिलाओं के लिए स्थायी आयोग को मंजूरी दे दी गई थी, पर अदालतों में कुछ मुकदमों के कारण इसे अक्टूबर 2020 में लागू किया जा सका। इसके परिणामस्वरूप, पहली बार 41 महिलाओं को योग्यता के आधार पर स्थायी कमीशन प्रदान किया गया है। वास्तव में, भारतीय नौसेना में स्थायी कमीशन अब व्यावहारिक रूप से सभी शाखाओं के लिए उपलब्ध है। न केवल स्थायी कमीशन बल्कि सरकार ने महिला अधिकारियों के लिए अवसरों को भी बढ़ाया है जैसे- दिसंबर 2019 में डोर्नियर एयरक्राफ्ट के लिए नौसेना पायलट के तौर पर पहली महिला अधिकारी का चयन हुआ, सितंबर 2020 में पहली बार सी किंग हेलिकॉप्टर्स में दो महिला पर्यवेक्षक अधिकारियों को शामिल किया गया, नौसना के जहाजों पर सेवा देने के लिए चार महिला अधिकारियों को तैनात किया गया, पहली बार रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट के लिए किसी महिला अधिकारी को नियुक्त किया गया और नविका सागर परिक्रमा, पहली ऐसी परियोजना, जिसमें भारतीय नौसेना की महिला अधिकारियों की एक टीम ने 2017-18 में भारत नौसेना की नौका आईएनएसवी तारिनी से दुनिया का भ्रमण किया। अभियान ने नौसेना में नारी शक्ति का प्रदर्शन किया।

भारतीय वायु सेना में महिला अधिकारियों का पहला बैच 1993 में शामिल किया गया था। परिवहन और हेलिकॉप्टर स्ट्रीमों में महिला पायलटों का पहला बैच दिसंबर 1994 में भर्ती किया गया।

हालांकि भारतीय वायु सेना ने महिलाओं के लिए सभी शाखाओं को 2016 में खोला। इसके परिणामस्वरूप, भारत को जून 2016 में पहली महिला फाइटर पायलट मिली। सितंबर 2020 तक भारतीय वायु सेना में 1875 महिला अधिकारी हैं, जिनमें 10 फाइटर पायलट और 18 नेविगेटर शामिल हैं।

भारतीय वायु सेना में कई महिलाओं ने अपनी उपलब्धियों से देश को गौरवान्वित किया है। 29 मई 2019 को फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कांत दिन और रात में ऑपरेशन करने वालीं पहली महिला फाइटर बनीं। सारंग फॉर्मेशन ऐरोबैटिक डिस्प्ले टीम में पहली महिला पायलट के तौर पर फ्लाइट लेफ्टिनेंट दीपिका मिश्रा शामिल हुईं।

मई 2019 में, फ्लाइट लेफ्टिनेंट पारुल भारद्वाज, फ्लाइंग ऑफिसर अमन निधि और फ्लाइट लेफ्टिनेंट हीना जायसवाल भारतीय वायु सेना का विमान उड़ाने वाली पहली 'सभी महिला' क्रू बनीं। फाइटर कंट्रोलर के तौर पर स्क्वाड्रन लीडर मिंटी अग्रवाल को 2019 में कश्मीर के आसमान में दुश्मन की हरकत को नाकाम करने के लिए युद्ध सेवा पदक प्रदान किया गया। विंग कमांडर आशा ज्योतिर्मय के पास देश में सबसे ज्यादा पैरा जंप का रिकॉर्ड है।

सरकार ने 2017 में सैनिक स्कूल में लड़कियों के लिए प्रवेश शुरू किया। सैनिक स्कूल, छिंगछिप मिजोरम पहला सैनिक स्कूल बना, जहां शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिए लड़कियों को प्रवेश दिया गया। बालिका कैडेटों ने सक्रिय रूप से सभी गतिविधियों में हिस्सा लिया, चाहे वह खेल हो या अकादमिक और उन्होंने सभी गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।

पांच अन्य स्कूलों, जिनमें सैनिक स्कूल बीजापुर और सैनिक स्कूल कोडागु, कर्नाटक में; महाराष्ट्र में सैनिक स्कूल चंद्रपुर; उत्तराखंड में सैनिक स्कूल घोड़ाखाल और आंध्र प्रदेश में सैनिक स्कूल कलिकिरी को शैक्षणिक सत्र 2020-21 और बाकी सैनिक स्कूलों को शैक्षणिक सत्र 2021-22 से लड़कियों को प्रवेश देने के लिए कहा गया था। सरकार के इन कदमों के परिणामस्वरूप, भारतीय रक्षा बलों में महिला अधिकारियों को लेकर लैंगिक पूर्वाग्रह समाप्त हो रहा है। आज ज्यादा महिलाएं रक्षा बलों में शामिल हो रही हैं और देश की सेवा कर रही हैं और देश को गौरवान्वित कर रही हैं।

ओटीए चेन्नई में नई महिला अधिकारी

सैनिक स्कूल छिंगछिप, मिजोरम में प्रवेश पाने वाली बालिका कैडेटों का पहला बैच।

फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कांत दिन और रात में उड़ान भरने वाली पहली महिला पायलट बनीं।

नविका सागर परिक्रमा

फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी, डोर्नियर एयरक्राफ्ट की पहली नेवल पायलट।

डोर्नियर एयरक्राफ्ट पायलटों का पहला बैच।

“नौसेना कंस्ट्रक्टर्स कैडर्स में महिलाओं के लिए स्थायी आयोग को मंजूरी दे दी गई थी, पर अदालतों में कुछ मुकदमों के कारण इसे अक्टूबर 2020 में लागू किया जा सका। इसके परिणामस्वरूप, पहली बार 41 महिलाओं को योग्यता के आधार पर स्थायी कमीशन प्रदान किया गया है। वास्तव में, भारतीय नौसेना में स्थायी कमीशन अब व्यावहारिक रूप से सभी शाखाओं के लिए उपलब्ध है।

नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता के एक महान तीर्थयात्री थे

जिनका सपना था भारत की आजादी : रत्नेश्वर मिश्रा

पराक्रम दिवस के अवसर पर एन इंडियन पिलग्रिम- नेताजी का जीवन और उनकी प्रासंगिकता विषय पर वेबिनार का किया गया आयोजन

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के रीजनल आउटरीच ब्यूरो (आरओबी), पटना द्वारा आज पराक्रम दिवस के अवसर पर ह्नएन इंडियन पिलग्रिमह्न- नेताजी का जीवन और उनकी प्रासंगिकता विषय पर वेबिनार का आयोजन किया गया।

वेबिनार की अध्यक्षता करते हुए पीआईबी तथा आरओबी के अपर महानिदेशक एसके मालवीय ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के योगदान को दो मुख्य रूपों में देखा जा सकता है- पहला, नेता जी द्वारा डोमिनियन स्टेट या अन्य किसी भी प्रकार के राजनीतिक समझौता की जगह पूर्ण स्वराज की मांग करना और दूसरा भारत के स्वतंत्रता संग्राम में तेजी लाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान। उन्होंने कहा कि हम लोगों को देश के महान विभूतियों को किसी जाति, धर्म, संप्रदाय या क्षेत्रवाद में नहीं बांधना चाहिए।

अतिथि वक्ता के रूप में शामिल जाने-माने इतिहासकार रत्नेश्वर मिश्रा ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता के एक महान तीर्थयात्री थें, जिनका सपना था भारत की आजादी। उन्होंने कहा कि नेताजी पर गीता के संदेशों का बहुत गहरा प्रभाव था और यही वजह है कि वह भारतीय आध्यात्मिकता के भी द्योतक कहे जाते हैं। नेताजी मूल रूप से दो विश्वासों को आत्मसात किए हुए थे- आध्यात्मिकता और राष्ट्रवाद। उन्होंने कहा कि केवल यह कहना कि गांधीजी और नेताजी में मतांतर था, यह पूरी तरह सत्य नहीं है। नेताजी ने ही गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। वहीं गांधी जी ने भी नेताजी को सबसे महान देशभक्त कहा था। उन्होंने कहा कि नेताजी हमेशा सोशलिज्म और फासिज्म में मेल कराना चाहते थे। उन्होंने कहा कि नेताजी ने बर्लिन में आजाद भारत केंद्र, आजाद भारत सेना और आजाद हिंद रेडियो की स्थापना की, जिसका दूरगामी प्रभाव भारत के स्वतंत्रता आंदोलन पर पड़ा।

अतिथि वक्ता के रूप में शामिल बिहार विधान परिषद्, पटना के परियोजना पदाधिकारी बी एल दास ने कहा कि नेताजी राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत थे। नेताजी का जीवन मुख्य रूप से तीन महान विभूतियों से प्रभावित था- पहला स्वामी विवेकानंद, दूसरा चितरंजन दास और तीसरा गुरु बेनीमाधव दास। नेताजी देशबंधु चितरंजन दास को अपना आदर्श गुरु मानकर ही भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए थे। नेताजी के राजनीतिक जीवन पर विस्तार से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि नेता जी सुभाष चंद्र बोस के भाषणों को अगर हम पढ़ें तो उनके विचार आज भी पूरी तरह प्रासंगिक नजर आएंगे। उनके विचारों को हम लोगों को अंगीकार करने की आवश्यकता है।

अतिथि वक्ता के रूप में शामिल दिल्ली विश्वविद्यालय में राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर एवं डेवलपिंग कंट्रीज रिसर्च सेंटर (डीडीआरसी), नई दिल्ली के निदेशक श्री सुनील कुमार चौधरी ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के दर्शन, विचारधारा और रणनीति के आधार पर उन्हें 'इंडियन अलेक्जेंडर' कहा जाता है। उन्होंने कहा कि नेताजी स्वामी परमहंस के आध्यात्मिक विचारों और स्वामी विवेकानंद के राष्ट्रवाद के विचारों से बहुत ज्यादा प्रेरित थे। चितरंजन दास से प्रभावित होने के कारण ही वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़े। उन्होंने कहा कि भगवत गीता नेताजी के प्रेरणा के स्रोत थे और उन्होंने इसे अपने विद्यार्थी जीवन में ही आत्मसात कर लिया था। नेताजी में भारतीय संस्कृति कूट-कूट कर भरी हुई थी। नेताजी राष्ट्रवादी समाजवाद के माध्यम से आजादी पाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि नेताजी की रणनीति उनकी लामबंदी, संगठन कार्य एवं क्रियान्वयन में था।

वेबिनार में विषय प्रवेश संबोधन के दौरान दूरदर्शन (समाचार), पटना के सहायक निदेशक सलमान हैदर ने कहा कि नेताजी और गांधीजी की विचार धाराएं भले ही समान न रहे हों लेकिन दोनों का ही लक्ष्य भारत की आजादी था।

उन्होंने कहा कि जहां एक ओर नेताजी युवाओं को आजादी के लिए प्रेरित करते थे, वही गांधीजी अहिंसा के मार्ग से भारत की आजादी चाहते थे।

वेबिनार में पीआईबी के निदेशक दिनेश कुमार तथा दूरदर्शन (समाचार), पटना एवं आरओबी के निदेशक विजय कुमार ने भी अपने विचार रखें।

वेबिनार का संचालन करते हुए पीआईबी, पटना के सहायक निदेशक संजय कुमार ने कहा कि ह्नतुम मुझे खून दो मैं तुम्हे आजादी दूँगा" यह सिर्फ नारा नहीं है बल्कि एक आन्दोलन था लोगों को गोलबंद करने का मन्त्र था। इस नारे को अँग्रेजी हुकूमत के खिलाफ दिया था भारत के स्वतन्त्रता संग्राम के अग्रणी योद्धा आजाद हिन्द फौज के संस्थापक सुभाष चन्द्र बोस जी नेक उन्हें पूरा विश्व नेता जी के नाम से संबोधित करते हुये सम्मान देता है । इस महान सपुत्र की 125 वीं जयन्ती पर पूरा राष्ट्र उन्हें नमन कर रहा है और उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को आत्मसात करने का संकल्प ले रहा है।

फील्ड आउटरीच ब्यूरो (एफओबी), सीतामढ़ी के क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी जावेद अख्तर अंसारी ने धन्यवाद ज्ञापन किया। वेबिनार में बिहार स्थित सभी एफओबी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों सहित अनेक श्रोताओं ने हिस्सा लिया।

> अतिथि वक्ता के रूप में शामिल बिहार विधान परिषद्, पटना के परियोजना पदाधिकारी बी एल दास ने कहा कि नेताजी राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत थे। नेताजी का जीवन मुख्य रूप से तीन महान विभूतियों से प्रभावित था- पहला स्वामी विवेकानंद, दूसरा चितरंजन दास और तीसरा गुरु बेनीमाधव दास। नेताजी देशबंधु चितरंजन दास को अपना आदर्श गुरु मानकर ही भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए थे।

रेरा रियल एस्टेट क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन

हरदीप एस पुरी

शहरी भारत और रियल एस्टे ट क्षेत्र का इतिहास हमेशा दो चरणों में याद किया जाएगा- रेरा पूर्व और रेरा के बाद उपभोक्ता संरक्षण मोदी सरकार के लिए विश्वास का एक विषय है। उपभोक्ता किसी भी उद्योग का आधार होते हैं, जिसके वृद्धि और विकास के केन्द्र में उसके हितों की रक्षा होती है।पदभार संभालने के डेढ़ साल के भीतर, मोदी सरकार ने मार्च 2016 में रेरा लागू किया, जो एक दशक से अधिक समय से तैयार होने में लगा हुआ था।

रेरा ने अब तक अनियंत्रित एक क्षेत्र में शासन प्रणाली को प्रभावित किया है। विमुद्रीकरण और वस्तु और सेवा कर कानूनों के साथ, इसने काफी हद तक रियल एस्ट्रेट क्षेत्र से काले धन का सफाया किया है।

रेरा में परिवर्तनकारी प्रावधान हैं, जो बड़ी ईमानदारी से उन लोगों पर निशाना साधते हैं जो लगातार रियल एस्टेट क्षेत्र को नुकसान पहुंचा रहे थे। इस कानून में प्रावधान किया गया है कि किसी भी परियोजना को सक्षम अधिकारी द्वारा मंजूर परियोजना के नक्शेप के बिना बेचान हीं जा सकता है और नियामक प्राधिकरण में पंजीकृत परियोजना को झूठे विज्ञापनों के आधार पर बेचने की प्रथा को समाप्त किया जा सकता है।

जिस काम के लिए ऋण स्वीकृत किया गया था, उनके अलावा अन्य उद्देश्यों / गतिविधियों के लिए धनराशि लगाने (फंड डायवर्जन) को रोकने के लिए प्रमोटरों को' परियोजना आधारित अलग बैंक खाता' रखना आवश्यक है।ह्यकारपेट एरियाह्ल के आधार पर यूनिट के आकार की अनिवार्य जानकारी देना चालबाजी और बेईमानी से उपभोक्ताय को नुकसान पहुंचाने वाली व्यह्लवस्थार की जड़ पर वार करती है। अगर प्रमोटर या खरीदार भुगतान नहीं कर पाता है तो ब्याज का समान दर पर भुगतान करने का प्रावधान है।कानून के अंतर्गत ऐसे कई अन्य प्रावधानों ने क्षेत्र में व्यातप्तश अधिकार की असमानता में सुधार करते हुए उपभोक्ताओं को अधिकार सम्पअन्नऐ बना दिया है।

इस कानून पर समझौता बातचीत के इतिहास का तकाजा है कि किसी उचित समय में, इस कानून को पटरी से उतारने और इसे बनाने के लिए किए गए सभी असफल निर्लज्जे प्रयासों को सूची बद्ध किया जाना चाहिए।

वर्षों के विचार-विमर्श के बाद, इस विधेयक को 2013 में यूपीए के कार्यकाल के दौरान राज्यसभा में पेश किया गया था। 2013 के विधेयक और 2016 के कानून के बीच के स्पाष्ट्य अंतर को उजागर करना आवश्यक है। इस से देश के घर खरीदारों के हितों की रक्षा में मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को समझने में मदद मिलेगी।

2013 के विधेयक में न तो 'चालू परियोजनाओं' और न ही 'वाणिज्यिकरियल एस्टेचट ' को शामिल किया गया था। परियोजनाओं के पंजीकरण की सीमा इतनी अधिक थी कि अधिकांश परियोजनाएं कानून के अंतर्गत आने से बच जाती थीं।इन अपवादों ने 2013 के विधेयक को निरर्थक बना दिया और यह वास्तव में घर खरीदारों के हितों के लिए अहितकर था।

वर्ष 2014 में मोदी सरकार के गठन के बाद, अनेक हितधारकों के बीच परामर्श के साथ-सा थ सम्पूजर्ण रूप से एक समीक्षा की गई और उसके बाद ह्यचालू परियोजनाओंह्ल और ह्यवाणिज्यिक परियोजनाओंह्ल दोनों को विधेयक में शामिल किया गया। अधिकतर परियोजनाओं को कानून के दायरे में लाने के लिए परियोजनाओं के पंजीकरण की सीमा को भी कम कर दिया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेन् द्र मोदी जी की दृढ़ता और धैर्य के बिना, रेरा कभी अस्तित्व में नहीं आ सकता था।

जब 2013 का विधेयक संसद में लंबित था, महाराष्ट्र राज्य में कांग्रेस सरकार

> “जिस काम के लिए ऋण स्वीकृत किया गया था, उनके अलावा अन्य उद्देश्यों / गतिविधियों के लिए धनराशि लगाने (फंड डायवर्जन) को रोकने के लिए प्रमोटरों को' परियोजना आधारित अलग बैंक खाता' रखना आवश्यक है।कारपेट एरिया के आधार पर यूनिट के आकार की अनिवार्य जानकारी देना चालबाजी और बेईमानी से उपभोक्ताय को नुकसान पहुंचाने वाली व्यवस्थार की जड़ पर वार करती है।

ने 2012 में विधान सभा में चुपचाप अपना कानून बना लिया था, वर्ष 2014 के आम चुनाव से सिर्फ 2 महीने पहले उसने फरवरी 2014 में संविधान के अनुच्छेद 254 के तहत राष्ट्रपति की सहमति ली। महाराष्ट्र में इसलिए रेरा लागू नहीं हुआ।

केन्द्र और महाराष्ट्र में कांग्रेस के कार्यों की निंदा का सार्थक और स्पेष्ट प्रभाव पड़ा और केन्द्र में तत्कालीन यूपीए सरकार की शासन कार्य प्रणाली की कड़ी निंदा हुई। संदेह उस समय और बढ़ गया जब दिखाई दिया कि राज्य कानून निश्चित रूप से उपभोक्ता के अनुकूल नहीं था।ऐसा इसलिए है क्योंकि यूपीए की रेरा को लागू करने की वास्तव में गंभीर इच्छा नहीं थी।

राजनीतिक लाभ के लिए, यूपीए ने संविधान के अनुच्छेद 254 के अंतर्गत मंजूरी देकर आम चुनावों से पहले, एक अधूरे और असम्बवद्ध कानून को लटका दिया। पार्टी का राज्यच विधेयक जिससे महाराष्ट्र के घर खरीदारों को स्थायी नुकसान हुआ होगा।

मोदी सरकार ने रेरा की धारा 92 के राज्य कानून को रद्द कर के इस विसंगति को ठीक किया।यह संविधान के उसी अनुच्छेद 254 के अंतर्गत नियम की सहायता लेकर किया गया था जो निरस्त करने की शक्तियाँ प्रदान करता है।यह इस तथ्य के बावजूद किया गया था कि महाराष्ट्र में अक्टूबर 2014 में सरकार बदल गई, जो अब भाजपा के नेतृत्व में थी।

रेरा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता मार्च, 2016 में संसद द्वारा कानून बनाने के साथ समाप्त नहीं हुई। हम ने रेरा की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली विभिन्न उच्चन्यायालयों में दायर रिट याचिकाओं की झड़ी का सामना किया।दिसंबर, 2017 में, लगभग 2 सप्ताह तक प्रतिदिन चलने वाली सुनवाई के बाद, माननीय बंबई उच्चन्यायालय ने कानून की संपूर्णता को बरकरार रखा, और रेरा की वैधता, आवश्यकता और महत्व के बारे में किसी भी दुविधा को समाप्तक कर दिया।

रेरा सहकारी संघवाद में एक अत्यबन्तम लाभदायक प्रयास है।हालांकि कानून का मार्ग दर्शन केन्द्र सरकार ने किया है, लेकिन नियमों को राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित किया जाना है, और नियामक प्राधिकरण और अपीलीय न्यायाधिकरण भी उनके द्वारा नियुक्त किए जाने हैं।दूसरी ओर, विनियामक प्राधिकरणों को विवादों का निपटारा और परियोजना की जानकारी देने के लिए सूचनाप्रद वेबसाइट चलाने सहित रोजमर्रा के कार्यों को देखना जरूरी है।

दूसरी तरफ, संवैधानिक अनुचित कार्य और खराब शासन के एक प्रत्यकक्ष उदाहरण में, पश्चिम बंगाल राज्य ने रेरा की अनदेखी करके और 2017 में अपना राज्य कानून झ वेस्ट बंगाल हाउसिंग इंडस्ट्री रेगुलेशनएक्ट (डब्यूंवै बीएचआईआरए) बना कर संसद के महत्वअ को रौंद दिया।

क्भारत सरकार के अनेक प्रयासों के बावजूद, पश्चिम बंगाल राज्य ने रेरा को लागू करने से इनकार कर दिया, जिससे पश्चिम बंगाल के घर खरीदारों को अपूरणीयक्षति हुई। यह जानते हुए कि इस विषय पर पहले से ही एक केन्द्रीय कानून मौजूद है, पश्चिम बंगाल सरकार ने 2017 में डब्यूरत बीएचआईआरए बनाया, और संविधान के अनुच्छेद 254 के तहत राज्य विधेयक के लिए भारत के माननीय राष्ट्रपति की मंजूरी की भी परवाह नहीं की।

पश्चिम बंगाल द्वारा संवैधानिक सिद्धांतों की इस अवहेलना को एक जनहित याचिका (पीआईएल) के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है।मुझे विश्वास है कि जल्द ही, डब्यूीआई बीएचआईआरए को असंवैधानिक बना दिया जाएगा और हमारे पास ह्यवन नेशन वनरेराह्ल होगा, जिससे पश्चिम बंगाल के घर खरीदारों को समान रूप से लाभ होगा।

चूंकि मई 2017 में रेरा पूरी तरह से लागू हो गया था, 34 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों ने नियमों को अधिसूचित किया, 30 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों ने रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरणों की स्थापना की और 26 ने अपीलीय न्यायाधिकरणों की स्थापना की है।परियोजना के सम्बान्धप में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करने और परियोजना की जानकारी के लिए एक वेब-पोर्टल का परिचालन किया गया है जो रेरा का सार है।

लगभग 60,000 रियल एस्टे।ट परियोजनाएं और 45,723 रियल एस्टेट एजेंटों को नियामक प्राधिकरणों के साथ पंजीकृत किया गया है, जो खरीदारों को जानकारी के साथ बढ़िया विकल्प चुनने का मंच प्रदान करता है।उपभोक्ता के विवादों का निवारण करने के लिए 22 स्वतंत्र न्यायिक अधिकारियों को एक फास्ट-ट्रैक व्यंवस्थान के रूप में नियुक्त किया गया है, जहां 59,649 शिकायतों का निपटान किया जा चुका है।इसने साथ-साथ उपभोक्ता अदालतों का बोझ हलका किया है। रेरा, रियल एस्टेट सेक्टर के लिए है, जैसे सेबी शेयर बाजार के लिए है, जिसके लागू होने से यह क्षेत्र सेक्टर नई ऊंचाइयों को देख रहा है।जैसा कि मैंने हमेशा कहा है, शहरी भारत और रियल एस्टेट क्षेत्र का इतिहास हमेशा दो चरणों में याद किया जाएगा, वह है 'रेरा पूर्व' और' रेरा के बाद'।

लेखक केन्द्री य मंत्रिपरिषद के सदस्या हैं

> मोदी सरकार ने रेरा की धारा 92 के राज्य कानून को रद्द कर के इस विसंगति को ठीक किया।यह संविधान के उसी अनुच्छेद 254 के अंतर्गत नियम की सहायता लेकर किया गया था जो निरस्त करने की शक्तियाँ प्रदान करता है।यह इस तथ्य के बावजूद किया गया था कि महाराष्ट्र में अक्टूबर 2014 में सरकार बदल गई, जो अब भाजपा के नेतृत्व में थी।

महिलाओं के खिलाफ अपराध के मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते हैं मुख्यमंत्री : महिला विकास मंच

महिला विकास मंच ने किया पार्टी बनाने का ऐलान

किशनगंज अध्यक्ष डॉक्टर तारा श्वेता आर्य को बनाया गया राष्ट्रीय महामंत्री

बिहार में महिलाओं पर बढ़ते अपराध को लेकर महिला विकास मंच ने आज बिहार के मुख्यमंत्री पर कड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि महिला विकास मंच ने महिलाओं के मुद्दे पर कई बार मुख्यमंत्री जी से बात करने का प्रयास किया, लेकिन वे सिर्फ सशक्तिकरण की बात कर अपनी जिम्मेदारियों की खानापूर्ति करते हैं. हकीकत ये है कि वे इस मुद्दे पर बात ही नहीं करना चाहते हैं. उक्त बातें आज महिला विकास मंच द्वारा आयोजित संवाददाता सम्मेलन में मंच की राष्ट्रीय संरक्षक वीणा मानवी ने कहीं. सरकार की उदासीनता को देखकर उन्होंने आने वाले दिनों में पार्टी बनाने का भी ऐलान किया.

उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए हमने गत 10 सालों से ना जाने कितने आवाज उठाई और मुख्यमंत्री जी से मांग किया कि जागरूकता अभियान चलाने के लिए हमारी टीम से मदद लें. सैकड़ों महिलाओं की फौज के साथ वह सरकार को मदद करने के लिए तैयार है. लेकिन उन्होंने कभी भी महिला विकास मंच को मिलने का समय नहीं दिया, जिससे महिलाएं काफी आक्रोशित और दुखी हैं. उन्होंने कहा कि कई केसेस बिहार के ऐसे हैं जहां वारंट निकलने के बाद भी मुजरिम की गिरफ्तारी है पुलिस नहीं कर पा रही है और मुजरिम अपने घर में आराम से बैठा है. लड़कियां आए दिन मार - जल - कट रही है. साथ ही साथ पुरुष प्रताड़ना पर भी महिला विकास मंच लगातार काम कर रही है. हाल में एक केस में उन्होंने बिहार के 4 लड़कों पर रेप केस का झूठा आरोप में मंच ने उनका भविष्य बचाया. इन चीजों को भी बारीकी से देखने की जरूरत है. इसके लिए हम मुख्यमंत्री जी से जल्द पुरुष आयोग बनाने की मांग करते हैं.

इससे पहले उन्होंने दूसरी ओर किशनगंज अध्यक्ष डॉक्टर तारा श्वेता आर्य के 3 साल का कार्यकाल समाप्त होने पर उनके कार्यों को देखते हुए उन्हें राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया. मंच की अध्यक्ष अरुणिमा ने उन्हें पगड़ी तलवार देखकर सम्मानित किया. उपाध्यक्ष फाहिमा खातून ने कहा कि अब हमारा मकसद हमारे काम की महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को रोकना भी होगा. चंपारण जिले के लगभग 100 से भी अधिक प्रताड़ना के केसेस को उन्होंने हल किया है. राष्ट्रीय प्रभारी अटल कुमार गुप्ता और राष्ट्रीय सचिव पंकज सिंह ने कहा कि व्यवसाय हत्या को लेकर हमारी टीम अलग से करेगी कार्य सरकार के किसी भी तरह कि कोई सहयोग ना होने के बावजूद भी हम लगातार समाज के प्रति अपनी जवाबदेही को निभा रहे हैं और निभाते रहेंगे.

अरुणिमा ने कहा बड़ा दुख होता यह देख कर की झारखंड बंगाल उत्तर प्रदेश हर जगह हमें सरकार से सहयोग मिलता है सिर्फ बिहार छोड़ के हमारे कार्यों की खुशबू पूरे देश में फैल रही है लेकिन फिर भी हमारे मुख्यमंत्री जी कभी महिलाओं के मुद्दों पर बात तक नहीं करना चाहते. मौके पर मौजूद प्रदेश महामंत्री पूनम सलूजा ने कहा अगर हमारी पार्टी बनी तो सभी जातियों के समीकरण के साथ बनेगी, क्योंकि बिहार में जाति की राजनीति को विशेष बढ़ावा दिया जाता है. टेकारी संयोजक सरिता देवी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की सोच को बदलने के लिए जागरूकता अभियान चलाना बहुत ही अनिवार्य है.

> “महिला सशक्तिकरण के लिए हमने गत 10 सालों से ना जाने कितने आवाज उठाई और मुख्यमंत्री जी से मांग किया कि जागरूकता अभियान चलाने के लिए हमारी टीम से मदद लें. सैकड़ों महिलाओं की फौज के साथ वह सरकार को मदद करने के लिए तैयार है. लेकिन उन्होंने कभी भी महिला विकास मंच को मिलने का समय नहीं दिया, जिससे महिलाएं काफी आक्रोशित और दुखी हैं.

अमर शहीद जगदेव प्रसाद को मिले भारतरत्न : अनिल कुमार

पूर्व केंद्रीय मंत्री सह भारत के लेनिन अमर शहीद जगदेव प्रसाद की 99वीं जयंती के अवसर पर उन्हें भारतरत्न देने की मांग जोर झ शोर से उठी। यं मांग उनकी जयंती के अवसर पर पटना के बेली रोड स्थित शहीद जगदीश स्मारक पर आयोजित समारोह में जनतांत्रिक विकास पार्टी के अध्यक्ष अनिल कुमार ने माल्यार्पण कर कही। उन्होंने कहा कि शहीद जगदेव बाबू सामाजिक संघर्षों एवं त्याग, बलिदान और शहादत के उनके संघर्षों की कहानी कहती है। उनके संघर्ष का ही नतीजा है कि आज देश के सर्वोच्च महत्वपूर्ण पद पर दलित समुदाय का व्यक्ति बैठा है। देश के प्रधानमंत्री सहित राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री पद पर दलित एवं पिछड़े समाज से पदासीन हैं।

अनिल कुमार ने कहा कि जगदेव बाबू की जयंती हम हर साल मनाते हैं, लेकिन उन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान भारतरत्न मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे चाहते थे शासन झ प्रशासन में सबों का बराबर का अधिकार हो। उनकी हत्या जिस वक्त में हुई थी, वो वक्त कितना दुर्भाग्यपूर्ण रहा होगा। मगर फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और संघर्ष का मिशाल पेश करते हुए बलिदान दिया। इसलिए उन हें भारतरत न मिलना चाहिए और हम सब लोग मिलकर इसके लिए संघर्ष करेंगे।

> “शहीद जगदेव बाबू सामाजिक संघर्षों एवं त्याग, बलिदान और शहादत के उनके संघर्षों की कहानी कहती है। उनके संघर्ष का ही नतीजा है कि आज देश के सर्वोच्च महत्वपूर्ण पद पर दलित समुदाय का व्यक्ति बैठा है। देश के प्रधानमंत्री सहित राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री पद पर दलित एवं पिछड़े समाज से पदासीन हैं।

राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री ने गाँधी घाट पर भारतीय स्वतंत्रता-संग्राम के हुतात्माओं को श्रद्धांजलि दी तथा समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की

महामहिम राज्यपाल श्री फागू चैहान एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने आज गाँधी घाट पर भारतीय स्वतंत्रता-संग्राम के हुतात्माओं को श्रद्धांजलि दी तथा समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए अपना नमन निवेदित किया।

राजकीय समारोह के इस कार्यक्रम में सशस्त्र पुलिस बल द्वारा शोक-सलामी दी गई तथा उपस्थित सभी व्यक्तियों ने मौन रखा। राज्यपाल श्री फागू चैहान एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा गाँधी घाट पर बने समाधि-स्थल पर पुष्पांजलि भी अर्पित की गई।

इस कार्यक्रम में सामाजिक-राजनीतिक संगठनों के पदाधिकारी/प्रतिनिधिगण, वरीय प्रशासनिक अधिकारीगण आदि ने भी भाग लिया एवं मौन रखते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। राजभवन, पटना में राज्यपाल के सचिव श्री रॉबर्ट एल॰ चोंग्थू, राज्यपाल सचिवालय के वरीय अधिकारियों तथा राजभवन कर्मियों ने भी भारतीय स्वतंत्रता-संग्राम में अपनी प्राणाहूति देनेवाले शहीदों को दो मिनट का मौन रखते हुए अपनी श्रद्धांजलि दी।

> इस कार्यक्रम में सामाजिक-राजनीतिक संगठनों के पदाधिकारी/प्रतिनिधिगण, वरीय प्रशासनिक अधिकारीगण आदि ने भी भाग लिया एवं मौन रखते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। राजभवन, पटना में राज्यपाल के सचिव श्री रॉबर्ट एल॰ चोंग्थू, राज्यपाल सचिवालय के वरीय अधिकारियों तथा राजभवन कर्मियों ने भी भारतीय स्वतंत्रता-संग्राम में अपनी प्राणाहूति देनेवाले शहीदों को दो मिनट का मौन रखते हुए अपनी श्रद्धांजलि दी।

घरेलू हिंसा की गहरी होती जड़े

कोरोना के संक्रमण पर काबू पाने के लिए लगाई गई पूर्णबंदी के दौर में व्यापक पैमाने पर लोगों को रोजगार और रोजी-रोटी से वंचित होना पड़ा और इसके साथ-साथ घर में कैद की स्थिति में असंतुलन, आक्रामकता एवं तनावपूर्ण रहने की नौबत आई। जाहिर है, यह दोतरफा दबाव की स्थिति थी, जिसने जीवन में अनेकानेक बदलावों के साथ व्यवहार में निराशा, हताशा और हिंसा की मानेवृत्ति को बढ़ाया। इस दौरान महिलाओं एवं बच्चों से मारपीट, उनकी प्रताड़ना, अपमान आदि की घटनाएं बढ़ी। पति-पत्नी और पूरा परिवार लम्बे समय तक घर के अंदर रहने को मजबूर हुआ, जिससे जीवन में ऊब, चिड़चिडापन एवं वैचारिक टकराव कुछ अधिक तीखे हुए और महिलाओं एवं बच्चों के साथ मारपीट की घटनाएं बढ़ीं।

इन नये बने त्रासद हालातों की पड़ताल करने के लिये राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की ओर से देश के बाईस राज्यों और केंद्र प्रदेशों में एक अध्ययन कराया गया जिसमें घरेलू हिंसा के बीच महिलाओं की मौजूदा स्थिति को लेकर जो तस्वीर उभरी है, वह चिंताजनक है और हमारे अब तक के सामाजिक विकास पर सवालिया निशान है। महिलाओं की आजादी छीनने की कोशिशें और उससे जुड़ी हिंसक एवं त्रासदीपूर्ण घटनाओं ने बार-बार हम सबको शर्मसार किया है। भारत के विकास की गाथा पर यह नया अध्ययन किसी तमाचे से कम नहीं है। इस व्यापक अध्ययन रिपोर्ट के मुताबिक कई राज्यों में तीस फीसद से ज्यादा महिलाएं अपने पति द्वारा शारीरिक और यौन हिंसा की शिकार हुई हैं। सबसे बुरी दशा कर्नाटक, असम, मिजोरम, तेलंगाना और बिहार में है। कर्नाटक में पीड़ित महिलाओं की तादाद करीब पैंतालीस फीसद और बिहार में चालीस फीसद है। दूसरे राज्यों में भी स्थिति इससे बहुत अलग नहीं है। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर ऐसी घटनाओं में तेज इजाफा होने की आशंकाएं भावी पारिवारिक संरचना के लिये चिन्ताजनक है। संयुक्त राष्ट्र भी कोरोना महाव्याधि के दौर में महिलाओं और लड़कियों के प्रति घरेलू हिंसा के मामलों में ह्यभयावह बढ़ोतरीह्ण दर्ज किये जाने पर चिंता जता चुका है। यह बेहद अफसोसजनक है कि जिस महामारी की चुनौतियों से उपजी परिस्थितियों से पुरुषों और महिलाओं को बराबर स्तर पर जूझना पड़ रहा है, उसमें महिलाओं को इसकी दोहरी मार झेलनी पड़ी है। कोरोना की पूर्णबंदी खुलने के बाद भी ऐसी घटनाएं चिंताजनक स्तर पर कायम रहना एक गंभीर स्थिति है।

इसका मुख्य कारण आर्थिक तंगी, रोजगार और कामकाज का बाधित होना या छिन जाना था। महानगरीय जीवन में तनाव और हिंसा की स्थितियां सामान्यतया देखी जाती हैं। इसकी वजहों के कई कारण हैं। आर्थिक तंगी की वजह से कई लोग अपने भीतर का तनाव परिवार के सदस्यों पर निकालते हैं। महिलाएं और बच्चे उनका आसानी से शिकार बनते हैं। इसके अलावा महात्वाकांक्षाएं भी एक वजह है, जिसके चलते महानगरीय चमकदमक में कई लोग सपने तो बड़े पाल लेते हैं, पर जब वे पूरे होते नहीं दिखते तो उसकी खीझ पत्नी और बच्चों पर निकालते हैं। पूर्णबंदी के दौरान बालविकास मंत्रालय ने घरेलू हिंसा रोकने के उद्देश्य से जागरूकता कार्यक्रमों को और बढ़ाने का प्रयास शुरू कर दिया है। लेकिन सरकारी प्रयासों के अलावा जन सोच को बदलना होगा।

एक टीस से मन में उठती है कि आखिर घरेलू हिंसा क्यों बढ़ रही है? नारी एवं मासूम बच्चों पर हिंसा का यह कहर क्यों बरपाया है? पतियों की हिंसा से बच भी जाये तो बलात्कार, छेड़खानी एवं सामाजिक विकृतियों की आग में वह भस्म होती है। हम भले ही समाज के अच्छे पहलुओं की चर्चा कर लें, लेकिन यह किसी से छिपा नहीं है कि महिलाओं के प्रति आम सामाजिक नजरिया बहुत सकारात्मक नहीं रहा है। बल्कि कई बार घरेलू हिंसा तक को कई बार सहज और सामाजिक चलन का हिस्सा मानकर इसकी अनदेखी करके परिवार के हित में महिलाओं को समझौता कर लेने की सलाह भी दी जाती है। ऐसे में घरों की चारदिवारी में पलती हिंसा एक संस्कृति के रूप में ठोस शक्ल अख्तियार कर लेती है। महिलाओं पर हो रहे इस तरह के अन्याय, अत्याचारों की एक लंबी सूची रोज बन सकती है। न मालूम कितनी महिलाएं, कब तक ऐसे जुल्मों का शिकार होती रहेंगी। कब तक अपनी मजबूरी का फायदा उठाने देती रहेंगी। दिन-प्रतिदिन देश के चेहरे पर लगती यह कालिख को कौन पोछेगा? कौन रोकेगा ऐसे लोगों को जो इस तरह के जघन्य अपराध करते हैं, नारी को अपमानित करते हैं, बच्चों को प्रताड़ित करते हैं। दरअसल, यह एक सामाजिक विकृति है, जिससे तत्काल दूर करने की जरूरत है। लेकिन यह तभी संभव है, जब सरकारों की नीतिगत प्राथमिकताओं में सामाजिक विकास और रूढ़ विचारों पर नजरिया और मानसिकता बदलने का काम शामिल हो। माना जाता है कि जिन समाजों में शिक्षा का प्रसार ठीक से नहीं हुआ है, उन्हीं में महिलाओं और बच्चों के साथ हिंसक व्यवहार अधिक होता है। मगर यह धारणा अनेक घटनाओं से गलत साबित हो चुकी है। पढ़े-लिखे और सभ्य कहे जाने वाले समाजों में भी महिलाएं न तो सुरक्षित हैं और न उन्हें अपेक्षित सम्मान हासिल है।

कोरोना संक्रमण के दौरान ही नहीं बल्कि भारत में पिछले कुछ सालों में घर से लेकर सड़क और कार्यस्थल तक महिलाओं के उत्पीड़न एवं हिंसा का मुद्दा राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बना है। मीटू आंदोलन ने इसे और ऊंचाई दी है और खासकर कामकाजी दायरे में यौन शोषण के मुद्दे को केंद्र में ला दिया है। लेकिन गौर करने की बात है कि अभी सारी बहस महिलाओं के सार्वजनिक जीवन को लेकर ही हो रही है। महिलाओं की घरेलू हिंसा के बारे में तो अभी बात शुरू भी नहीं हुई है कि घर के भीतर उन्हें कैसी त्रासद एवं हिंसक घटनाओं को झेलना पड़ रहा है। इस विषय पर चर्चा शायद इस लिए भी नहीं होती कि भारत में घर को एक पवित्र जगह के तौर पर देखा जाता है और इसके भीतरी माहौल को सार्वजनिक चर्चा के दायरे में लाना मयार्दा के खिलाफ समझा जाता है। पुरुष-प्रधान समाज को उन आदतों, वृत्तियों, महत्वाकांक्षाओं, वासनाओं एवं कट्टरताओं को अलविदा कहना ही होगा जिनका हाथ पकड़कर वे उस ढ़लान में उतर गये जहां रफ्तार तेज है और विवेक अनियंत्रित हैं जिसका परिणाम है नारी एवं बच्चों पर हो रही घरेलू हिंसा, नित-नये अपराध और अत्याचार। पुरुष-प्रधान समाज के प्रदूषित एवं विकृत हो चुके तौर-तरीके ही नहीं बदलने हैं बल्कि उन कारणों की जड़ों को भी उखाड़ फेंकना है जिनके कारण से बार-बार नारी को जहर के घूंट पीने को विवश होना पड़ता है। यही वजह है कि आज भी महिलाओं को घर से लेकर कामकाज तक के मामले में सार्वजनिक स्थानों पर कई तरह की वंचनाओं, विकृत सोच और भेदभावों का शिकार होना पड़ता है। यह रवैया आगे बढ़ कर हिंसा की अलग-अलग शक्ल में सामने आता है, जिसे समाज में अघोषित तौर पर सहज माना जाता है।

“ एक टीस से मन में उठती है कि आखिर घरेलू हिंसा क्यों बढ़ रही है? नारी एवं मासूम बच्चों पर हिंसा का यह कहर क्यों बरपाया है? पतियों की हिंसा से बच भी जाये तो बलात्कार, छेड़खानी एवं सामाजिक विकृतियों की आग में वह भस्म होती है। हम भले ही समाज के अच्छे पहलुओं की चर्चा कर लें, लेकिन यह किसी से छिपा नहीं है।

एसएसपी मनोज कुमार के आगे नहीं गलती है फिरकापरस्तों की दाल

पुलिस पाठशाला,शेरनी दल व मोटर साईकल पर हेलमेट लगाकर अंधेरी रात में विरान सड़कों पर खूद गश्ती करने को लेकर पुरे बिहार में हैं विशेष चर्चित

गौतम सुमन गर्जना

शहर की सूरत यदि कोई बिगाड़ने की कोशिश करता है या वहां की शांति-सद्भाव और सुरक्षा में कोई आग लगाने की मात्र प्रयास भर भी कर ले,तो चाहे वह कितना बड़ा आदमी क्यों न हो; उसे एसएसपी मनोज कुमार किसी भी स्थिति में बक्शते नहीं हैं क्योंकि इनके फर्ज व कानून के सामने ऐसे लोगों का कोई बजूद नहीं होता।

हम बात कर रहे हैं बिहार के सुपौल जिले के वर्तमान एसएसपी मनोज कुमार की,जो अपने कर्तब्य व फर्ज के कारण भागलपुर-दरभंगा-मुजफ्फरपुरव सुपौल जिले में अपनी अविस्मरणीय पहचान बनाते हुए काम करने के अपने खास अंदाज के लिए जाने-पहचाने जाते हैं। वे जहां भी रहे ओपन माइंड के साथ रहे। वहां शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में स्मार्ट पुलिसिंग व्यवस्था दिखने लगती है और वे वहां के स्थानीय थानों के संसाधनों को बढ़ाने का प्रयास करते रहे हैं।महत्वाकांक्षा पर खड़ा उतरना इनका पहला लक्ष्य है। वे जहां भी गए,वहां के युवाओं से वे सीधा संवाद करते हैं और शिक्षाविदों से मदद लेने में वे तनिक भी संकोच नहीं करते।यही कारण है कि स्थानांतरण के बाद भी लोग इन्हें भुलाए नहीं भूल पाते हैं। अपने कर्तब्य व फर्ज को पूरी ईमानदारी व पारदर्शिता के कारण ही वे बीएमपी-6 और बीएमपी-15 के अतिरिक्त प्रभार को भी निभा चुके हैं और यहां भी वे अपनी अनोखी छाप को छोड़ने में पीछे नहीं रहे। इनके कामों व अंदाज को देखकर लोगों का यहां तक मानना है कि बिहार में यदि ऐसे 10 एसएसपी हो जाएं तो बिहार से अपराध व अपराधियों का समूल सफाया तय हो जाएगा।

हमें आज भी स्मरण है जब एसएसपी मनोज कुमार भागलपुर में पदस्थापित थे,तब न केवल इनके द्वारा पुलिस-पब्लिक के समन्वय को सुदृढ़ करने के लिए भागलपुर के ऐतिहासिक सैंडिस कंपाऊंड में पुलिस-पब्लिक के बीच फुटबॉल टुनार्मेंट मैच कराया गया था बल्कि ईस्टर्न बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स के निर्वतमान सचिव संजीव कुमार उर्फ लालू शर्मा के आग्रह पर भागलपुर शहर के हृदय स्थल खलीफाबाग चौंक पर मुक्ताकाश में पुलिस-पब्लिक के बीच वृहद बैठक की और फिर पैदल मार्च करते हुए शहर को अतिक्रमण से इन्होंने मुक्त कराया था। इसी कड़ी में हमें भागलपुर का वह काला दिन भी याद आ रहा है,जब धर्म व आस्था की आड़ में कुछ लोग सक्रिय होकर एक बार फिर इस भागलपुर को कलंकित करने के लिए पूरी तन्मयता के साथ एकजूट हुए थे।तब इसी एसएसपी मनोज कुमार ने अपनी सुझ-बुझ व कानूनी दांव-पेंच से न केवल ऐसे लोगों के मंसूबे पर पानी फेरा था बल्कि तब इन्होंने इस भागलपुर को जलने से भी बचा लिया था।बात यूं था कि जब धर्म-मजहब और आस्था की आड़ में पवित्र रामनवमी के मौकेंपर चंपानगर में हुड़दंगियों द्वारा रोड़ेवाजी कर सांप्रदायिक तनाव फैला रहे थे,तब एसएसपी मनोज कुमार को यह सूचना कहलगांव में आयोजित विक्रमशीला महोत्सव से वापसी के दौरान मिली थी।सूचना मिलते ही वे सीधे सदल-बल के साथ तेज रफ्तार से घटना स्थल पर पहूंच गये और फैले तनाव पर काबू पाने की पूरी कोशिश की।इसी दरमियान उनके एक पुलिस कर्मी के बांह में गोली लग गई और सीटी डीएसपी के सुरक्षा गार्ड के सिर पर चोटें लगी। ऐसी हालात में वे चाहते तो कुछ और भी बड़ा एक्शन ले सकते थे लेकिन इससे हालात और माहौल दोनों बिगड़ने की संभावनाएं थी,जिसे भांपकर उन्होंने भीड़ को बचाने और सांप्रदायिक आग को भड़कने से रोकने की संकल्प ले ली।इसके लिए उन्होंने युक्ति सोच सड़क पर उतरकर मोर्चे की कमान खुद संभाल ली और इस शहर में अमन-

चैन,शांति-सद्भाव और भाईचारगी की मिशाल कायम रखने के लिए इसे एक चुनौती के रुप में स्वीकार कर अपनी जां की भी परवाह छोड़ दी। तब एसएसपी मनोज कुमार के इस कर्तब्यनिष्ठ दिलेरी को देखकर भागलपुर के विवेकशील शांति प्रहरियों ने भी महत्ती भूमिका थी,जिनके साथ मिलकर एसएसपी मनोज कुमार ने सर्वप्रथम ऐसे तत्वों को हटाने का काम किया,जिससे वहां खतरा बढ़ने की संभावनाएं थी।

इस मामले में हिन्दू नव वर्ष के मौके पर बिना अनुमति के वे एक जुलूस का नेतृत्व कर रहे

मंत्री पुत्र सह भाजपा नेता अर्जित शाश्वत चौबे एवं अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के संदर्भ में उन्होंने अलग से टीम और टास्क फोर्स गठन करने के बाद एसआईटी तक का गठन कर दिया। इन आरोपितों के छिपे होने की जहां खबर मिलती थी,वहां ताबड़तोड़ छापेमारी हुई।जिस दिन आखिरी जुलूस निकलनी थी,उसी दिन उन्होंने श्री चौबे के विरुद्ध न्यायालय से गिरफ्तारी वारेंट लिया और इश्तेहार व कुर्की की कार्रवाई भी करने का निर्णय लेकर उन्होंने कोर्ट में अर्जी दे दी। एसएसपी मनोज कुमार का मानना है कि कानून व न्यायालय से बड़ा कोई नहीं है और वे इस तरह सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने वालों को किसी भी सूरत में नहीं वक्सते। कोर्ट से अग्रिम जमानत रद्द होने और एसएसपी मनोज कुमार के तेवर व कोर्ट में इनके द्वारा दिये गए कुर्की की अर्जी देखकर श्री चौबे कानूनी शिकंजे से घिर चुके थे और तब आखिरकार पटना व भागलपुर पुलिस के संयुक्त टीम के प्रयास से श्री चौबे को पटना में गिरफ्तार कर उन्हें मुख्य न्यायिक

दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया और फिर उन्हें जेल की सलाखों के पीछे धकेला गया,जिसे देख शेष आरोपितों की रुह कांप गई और वे सभी भी न्यायालय में आत्म समर्पण कर दिये।

इस तरह उपद्रव और मामले उत्पन्न होने में सबसे बड़ी समस्या के सवाल पर उनका मानना है कि ऐसे में अफवाह सबसे बड़ी बाधाएं पैदा करती हैं।लोगों को ऐसी स्थिति-परिस्थिति में अफवाह फैलाने व अफवाहों में आने दोनों से परहेज करना चाहिए।कई भगौड़े अपराधियों की समय पर गिरफ्तारी नहीं होने या इसके लिए पुलिस कर्मियों को काफी जद्दोजहद करने के संबंध में वे बताते हैं कि हमारी छापेमारी लगातार चलती रहती है लेकिन,एक कारणवश अभियुक्तों की गिरफ्तारी मुश्किल हो जाती है,कि उनके पास न तो अपना घर होता है,न कोई ठिकाना और न ही उनकी कोई आईडेन्टी है। कभी-कभी तो ऐसे लोगों की तस्वीर तक दुर्लभ हो जाती है और कई बार उसके आस-पड़ोस भी भय व लालचवश उन्हें संरक्षण दे देते हैं और फिर ऐसे लोगों को न्यायिक व राजनीतिक संरक्षण मिलना तो जगजाहिर है। पत्रकारों पर हो रहे हमले पर दुख प्रकट करते हुए इनके सुरक्षा की बाबत एसएसपी मनोज कुमार ने कहा कि पुलिसिंग व पत्रकारिता दोनों जोखिम भरा कार्य है और आज कई कारणों से दोनों का वजूद खतरे में है।वे बताते हैं कि पत्रकार हमारी टीम की तरह है,जो कि हम पुलिसवालों से भी तेज चलती है।उनका सूचनातंत्र अधिक मजबूत होता है और उनसे हम पुलिसवालों को कई तरह की मदद मिलती है। पुलिस व पत्रकारों को अपने कामों में ज्यादा से ज्यादा सफलता मिले,इसके लिए हर समाज को पूरी तत्परता के साथ आगे आने की जरुरत है। यदि अपराधी व आपराधिक कृत्यों की जानकारी यदि भनक लगते ही लोग दे दें तो हमें अपराधियों तक पहुंचने में सुविधा होगी।

वर्तमान में सीधे-सादे परिवार के सदस्य,जिसकी अपराधिक गतिविधियों में ज्यादा हिस्सेदारी हो गई है; पर लगाम लगाने को लेकर एसएसपी मनोज कुमार ने कहा कि पहले परिवार का मुखिया अपने घर के एक-एक सदस्यों की कारस्तानी पर नजर रखते थे और उसे नियंत्रित भी किया करते थे लेकिन, आज घर का मुखिया अपने बच्चों को नियंत्रित करने में परहेज कर रहा है। मुखिया या गार्जियन को बच्चों की ऐसी कारस्तानी से कोई संबंध या सरोकार नहीं रह गया है, जिससे समाज का अनिष्ट हो रहा है। उन्होंने कहा कि बच्चे आज स्कूल-कॉलेज को भी अखाड़े की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस कारणवश उनमें संस्कार का अभाव हो गया है। ऐसे लोगों को शिक्षा-दीक्षा से कोई मतलब नहीं रह गया है। अगर बच्चे कुछ उल्टा-सीधा करके घर आते हैं तो उस उसके मनोबल को तोड़ने की बजाय गार्जियन या मुखिया के द्वारा उसका हौसला आफजाई किया जाता है, जिससे सामाजिक ताना-बाना बिगड़ रहा है और आपराधिक कृतियों में वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा कि अगर वक्त रहते मां-बाप सचेत हो जाएं तो बच्चे बिगड़ेंगे नहीं और वे समाज की खुशहाली में अपना योगदान दे सकेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि अपराधियों पर शिकंजा कसने का एकमात्र तरीका कानून है और कानून से बड़ा कुछ भी नहीं है।

देश के इतिहास में पहली बार भौतिकवादी युग में गरीब मेधावी छात्र-छात्राओं के सपनों में उड़ान भरने को लेकर और उनके सर्वांगीण विकास को लेकर भागलपुर के तत्कालीन सीनियर एसपी मनोज कुमार की पहल पर निःशुल्क पुलिस पाठशाला की शुरूआत 2016 ई. में भागलपुर में की गई थी,जिसमें पुलिस पाठशाला के द्वारा छात्र छात्राओं को लिखित परीक्षा के साथ-साथ फिजिकल परीक्षा की तैयारी की कराई जाती थी, और अब तक सैकड़ों छात्र-छात्रायें कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत प्रारंभ किए गए पुलिस की पाठशाला से अलग-अलग क्षेत्र में सफलता भी हासिल कर चुके हैं। यह आज भी भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड मैदान में जिले के साथ-साथ आसपास के जिलों के सैकड़ों छात्र-छात्राएं सुबह कडाके के ठंड में भी दौड, लोंग जंप, हाई जंप, डिस्कस थ्रो सहित फिजिकल के अलग-अलग विद्याओं का अभ्यास करते देखे जा सकते हैं। इस दौरान एक और जहां छात्र-छात्राएं मनोज कुमार की पहल पर पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे पुलिस की पाठशाला की जमकर तारीफ करते दिखते हैं,वहीं स्टैटिक्स यूनियन के सचिव नसर आलम भी खुद को इस अभियान का हिस्सा बताकर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और कहते हैं कि पिछले वर्ष पुलिस की पाठशाला से 82 छात्र-छात्राओं ने दरोगा,सिपाही और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए थे और इस वर्ष अलग-अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले छात्र-छात्राओं की संख्या और ज्यादा होगी। एक और जहां खाकी मुट्ठी भर चंद लोगों के कारण बदनाम हो रही है, वहीं आईपीएस मनोज कुमार की पहल पर

शान की सवारी बुलेट पर खुद ही निकल पड़े गश्ती पर

शुरू किए गए पुलिस की पाठशाला ने लोगों के मन में इसके प्रति एक अलग ही भाव जागृत कर रखा है।

वर्तमान में बिहार के सुपौल में पदस्थापित वरीय पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि वे जहां भी रहे या हैं,वहां अमन-चैन,शांति-सद्भाव कायम रखने की असीम संभावनाओं को साकार करने में वे सदैव समर्पित रहे हैं। वे बताते हैं कि वे अपने वरीय अधिकारियों के दिशा निर्देश पर ही हम इस अभूतपूर्व कार्य हेतु सबसे पहले अपनी टीम बनाते हैं,जिसमें विधि व्यवस्था के प्रति समर्पित तेज तर्रार पुलिसकर्मियों का चयन करते हैं और वे पुलिस पब्लिक-समन्वय को कायम रखकर न केवल अपराध व अपराधियों पर नकेल कसते हैं,बल्कि वहां पर विधि-व्यवस्था की मिशाल कायम रख शांति-सद्भाव व भाईचारे को बनाए रखने में हमेशा की तरह कामयाब होते रहे हैं।

कहते हैं न कि जिनके पास ईमानदारी व पारदर्शिता के साथ जोश-जज्बा होता है,उनका कोई बाल-बांका नहीं कर सकता है। ऐसा ही एक वाक्या स्मरण आ रहा है-जब वे दरभंगा में थे,तब एक बार वे पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे कि अचानक एसएसपी कार्यालय का फॉल्स सीलिंग का सेड टूटकर गिर गया।शेड टूटकर गिरने की आवाज इतनी तेज थी कि वहां अफरा-थपरी व हड़कंप मच गया और सारे लोग वहां से भाग निकले लेकिन एसएसपी मनोज कुमार बगैर कोई हतोत्साहित हुए ठीक उसी तरह डटे रहे,जैसे वे अपनी डियूटी व फर्ज पर डटे रहते हैं। उन्होंने न केवल वहां से सभी को निकाला बल्कि तुरंत वहां पर साफ-सफाई कर-करवाकर वहां पर स्थिति को यथावत कर दिया। इनके द्वारा गठित शेरनी दल के कारनामें आज देश भर के लिये एक सबक बना हुआ है। स्पोर्ट्स बाईक पर हेलमेट लगाकर अंधेरी रात व विरान सड़कों पर खूद से गश्ती पर निकल जाने और स्थानीय थाने व पुलिस कर्मियों की मॉनरीटिंग करने के भय से चुश्त-दुरुस्त होकर पुलिसवालों की गश्ती इनकी कर्तब्यशीलता का जीता-जागता उदाहरण है।

बहरहाल,आईपीएस मनोज कुमार एक ऐसा नाम हो चुका है,जिससे न केवल अपराध -अपराधी भयभीत व आशंकित रहते हैं बल्कि असामाजिक तत्व व मनचले युवक भी इनकी नजरों से खुद को दूर कर गुमनामी की चादर ओढ़ लेते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वे किसी गलत लोगों पर रहम नहीं करते,इस बात को पूरा बिहार जानता है। भागलपुर,दरभंगा व मुजफ्फरपुर जिला में अपराध व अपराधियों पर नकेल कसने के बाद एसएसपी मनोज कुमार अपने पुराने अंदाज व तेवर के साथ अभी वर्तमान में सुपौल जिला में अपनी स्मार्ट पुलिसिंग के जज्बों से अपराध व अपराधियों का सफाया करने में जुटे हुए हैं,जो शीघ्र ही नई जिम्मेदारी के साथ अपने इसी पुराने तेवर व अंदाज में बिहार पुलिस की सेवा को बरकरार रख कानून व विधि व्यवस्था की सेवा करते नजर आएंगे।

सफलता का मार्ग शार्टकट नहीं

मृत्युंजय कुमार सिंह

अध्यक्ष बिहार पुलिस एसोएिशन

दुनिया में सफलता पाने के लिए जरूरी नहीं कि लंबी लंबी छ्लांग ही लगाई जाए।जीवन में छोटे-छोटे कदमों से निरंतरता के साथ भी सफलता के मंजिल पर पहुंचा जा सकता है। कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करने पर सफलता के लिए एक बहुमूल्य खजाना प्राप्त होता हैं जिसका नाम है आत्मबल जिसे आप स्वयं के अंदर हमेशा जीवंत रखे। सफलता क्या है? हर इंसान के सफलता की परिभाषा दूसरों से भिन्न होती है। इसलिए हर किसी की सफलता की व्याख्या अलग - अलग होती है। कुछ के लिए यह मन की एक अवस्था है, कुछ के लिए भौतिक सुख, तो कुछ के लिए एक निश्चित पद को पाना और कुछ के लिए समाज में कुछ बड़ा करके नाम और शोहरत पाना। मेरे विचार से सफलता कभी पूर्ण नहीं होती है बल्कि यह सापेक्ष होती है। यह सिर्फ एक अल्पविराम है, पूर्णविराम नहीं। यह अंत न होकर जीवन की यात्रा का सिर्फ एक मोड़ है। इससे जीवन में कभी संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता है। असल में सफलता हमेशा बेहतर करने और आगे बढ़ने का संदेश देती है। मुझे अपने जीवन में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला है जो अपनी सफलता से संतुष्ट हो, चाहे वह शीर्ष राजनीतिज्ञ या नामचीन व्यक्ति हो , सफल व्यापारी हो या एक सफल खिलाड़ी हो। मैंने हमेशा इन सभी को दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए ही पाया है। यह शाश्वत सत्य है कि दूसरों की सफलता को देखते हुए एक व्यक्ति अपनी सफलता का आनंद ही नहीं ले पाता है। एक शहर में असाधारण प्रतिभा के धनी व्यक्ति को बहुत छोटी उम्र में इस बात का अहसास हो गया था कि सफल होने के लिये व्यक्ति को जीवन की कई अच्छी चीजों का बलिदान करना पड़ता है और उसे अपने जीवन का उद्देश्य मिल गया। वह महानतमों से भी महानतम बनने के प्रयासों में लग गया। लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं होता है।कई उतार - चढ़ाव से गुजरना पड़ता है।

मै बिहार के भोजपुर जिला के खननी कलाँ गाँव के किसान परिवार से निकल कर संघर्ष के रास्ते से गुजर कर पुलिस विभाग में नौकरी पाया।जीवन में हर संघर्ष अपने पीछे सफलता लेकर आती है और कहती है कि मुझसे लड़ो संघर्ष करो और मुझे पराजित करके अपनी सफलता को प्राप्त करो। नौकरी में गुजरते समय के साथ बिहार पुलिस एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष पर चुनाव लड़ा और लगातार तीन बार सफलता पाया। जब भी मैं युवाओं से मिलता हूँ तो वो मुझसे सफल होने के तरीकों के बारे में पूछते हैं। मैं हमेशा उनसे जीवन में एक उद्देश्य खोजने के लिये कहता हूँ और खुद को पहचानकर उसी के अनुसार अपना करियर चुनने की राय देता हूँ। कभी भी दूसरों को देखकर अपने जीवन के बारे में निर्णय न लो। आप खुद तय करो और अपने प्रति ईमानदार रहते हुए कभी खुद को धोखा देने का प्रयास मत करो। क्रिकेट के खेल में अगर कोई बल्लेबाजी के लिये अनुकूल है तो वह क्यों एक गेंदबाज बनने पर जोर दे?। मैंने योजना के अभाव में कई अच्छी - अच्छी प्रतिभाओं को बीच भंवर में भटकते हुए देखा है, क्योंकि वे अपनी प्रतिभा को पहचान नहीं सके और वे उसके साथ न्याय नहीं कर पाए। वे खुद को भूलकर दूसरों के साथ स्पर्धा में लग गए। मेरा भी ऐसा ही एक मित्र था जो शायद कई क्षेत्र में मुझसे अधिक प्रतिभाशाली था।आज वो कहीं नहीं है क्योंकि उसके जीवन में कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं था। वह अपनी गलतियों को स्वीकार करने

> “मै बिहार के भोजपुर जिला के खननी कलाँ गाँव के किसान परिवार से निकल कर संघर्ष के रास्ते से गुजर कर पुलिस विभाग में नौकरी पाया।जीवन में हर संघर्ष अपने पीछे सफलता लेकर आती है और कहती है कि मुझसे लड़ो संघर्ष करो और मुझे पराजित करके अपनी सफलता को प्राप्त करो। नौकरी में गुजरते समय के साथ बिहार पुलिस एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष पर चुनाव लड़ा ।

को तैयार नहीं था और साथ ही वह कभी यह स्वीकार करने को भी तैयार नहीं था कि कुछ ऐसी कार्य हैं जो दोस्त उससे बेहतर कर सकते हैं। उसने हमेशा दूसरों की नकल करने की कोशिश करता रहा। एक समय ऐसा आया जब वह अपनी खुद की पहचान ही भूल गया और मौलिकता को खोकर दूसरों की नकल के लायक भी नहीं रहा और संसार से उसका नाम ही खत्म हो गया। इसका सबसे दुखद पहलू यह है कि वह अब भी अपनी विफलताओं के लिये खुद को दोषी नहीं मानता है और उसने अपनी विफलताओं और दूसरों की सफलताओं के लिए कुछ षड्यंत्रों और बहानों को सृजन कर लिया है। इस तरह से वह स्वयं को धोखा ही दे रहा है। वह स्वयं के प्रति ईमानदार नहीं है। 20वीं सदी के प्रारम्भ की एक मशहूर रूसी बैले नर्तकी अन्ना पावलोवा ने कभी कितना सही कहा था कि :- जैसे कला की सभी शाखाओं में सफलता बहुत हद तक व्यक्तिगत पहल और सही कोशिश पर निर्भर करती है। इसे सिर्फ कड़ी मेहनत के बल पर हासिल नहीं किया जा सकता।पिकासो स्पेन में जन्में एक बहुत मशहूर चित्रकार थे। उनकी पेंटिंग दुनिया भर में करोड़ों और अरबों रुपयों में बिका करती थीं। एक दिन रास्ते से गुजरते वक्त एक महिला की नजर पिकासो पर पड़ी और संयोग से उस महिला ने उन्हें पहचान भी लिया। वो दौड़ी - दौढी उनके पास आयी और बोली सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आपकी पेंटिंग्स मुझे बहुत ज्यादा पसंद हैं। क्या आप मेरे लिए भी एक पेंटिंग बनायेंगे।पिकासो मुस्कुराते हुए बोले मैं यहाँ खाली हाथ हूँ मेरे पास कुछ नहीं है मैं फिर कभी आपके लिए पेंटिंग बना दूंगा।लेकिन उस महिला ने भी जिद पकड़ ली कि मुझे अभी एक पेंटिंग बना के चाहिए बाद में पता नहीं आपसे मिल पाऊँगी या नहीं।अंततः पिकासो ने जेब से एक छोटा सा कागज निकाला और अपने पेन से उसपे कुछ बनाने लगे। करीब 10 सेकेण्ड के अंदर पिकासो ने पेंटिंग बनायीं और कहा ये लो ये मिलियन डॉलर की पेंटिंग है। उस लड़की को बड़ा अजीब लगा कि पिकासो ने बस 10 सेकेण्ड में जल्दी से एक काम चलाऊ पेंटिंग बना दी और बोल रहे हैं कि मिलियन डॉलर की पेंटिंग है। उस औरत ने वो पेंटिंग ली और बिना कुछ बोले अपने घर आ गयी। उसको लगा पिकासो उसको मुर्ख बना रहा है, इसलिए वो मार्किट जाकर उस पेंटिंग की कीमत पता किया तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो पेंटिंग वास्तव में मिलियन डॉलर की हैं। वह भागी - भागी एक बार फिर पिकासो के पास आयी और बोली सर आपने बिलकुल सही कहा था ये तो वाकई मिलियन डॉलर की ही पेंटिंग है।पिकासो ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैंने तो आपसे पहले ही कहा था। वो महिला बोली झ सर आप मुझे अपनी स्टूडेंट बना लीजिये और मुझे भी पेंटिंग बनानी सीखा दीजिये। जैसे आपने 10 सेकेण्ड में मिलियन डॉलर की पेंटिंग बना दी, वैसे मैं भी 10 सेकेण्ड में ना सही 10 घंटे में ही अच्छी पेंटिंग बना सकूँ। मुझे ऐसा बना दीजिये। पिकासो ने हँसते हुए कहा झ ये जो मैंने 10 सेकेण्ड में पेंटिंग बनायीं है इसे सीखने में मुझे 30 साल का समय लगा। मैंने अपने जीवन के 30 साल सीखने में दिए तुम भी दो सीख जाओगी।

वो महिला अवाक निःशब्द होकर पिकासो को देखती रह गयी। संसार में जब हम दूसरों को सफल होता देखते हैं तो हमें ये सब बड़ा आसान लगता है। हमको लगता है कि ये इंसान को बड़ी जल्दी और बड़ी आसानी से सफल हो गया। लेकिन मेरे दोस्त उस एक सफलता के पीछे ना जाने कितने सालों की मेहनत छिपी है ये कोई नहीं देख पाता।

सफलता तो बड़ी आसानी से मिल जाती है लेकिन सफलता की तैयारी में अपना जीवन कुर्बान करना होता है। जो लोग खुद को कष्ट झेल कर, तपाकर, संघर्ष करके अनुभव हासिल करते हैं वो कामयाब हो जाते हैं और दूसरों को लगता है कि वह कितनी आसानी से सफल हो गया। मेरे दोस्त परीक्षा तो केवल तीन घंटे का होता है लेकिन उस तीन घण्टे के लिए पूरी साल नियमित तैयारी करनी पड़ती है। तो जीवन में फिर आप रातों रात सफल होने का सपना कैसे देख सकते है। सफलता अनुभव और संघर्ष मांगती है और अगर आप देने को तैयार हैं तो आपको आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता ।आखिर में क्या मैं आप सभी से पूछ सकता हूं कि सफलता का मतलब क्या है? क्या यह कठिन परिश्रम है या व्यक्तिगत पहल है या यह असाधारण प्रतिभा है। आगे आने वाले दिनो में करियर के चरम पर एक आकर्षक नौकरी छोड़ने के बाद मैं निश्चिंतता के साथ कह सकता हूँ कि सफलता कुछ और नहीं बल्कि संपूर्णता की एक भावना है। यह एक ऐसी मरीचिका है जिसका हम सब पीछा तो करते हैं लेकिन पाने में नाकामयाब रहते हैं क्योंकि हम खुद से स्पर्धा करने की जगह दूसरों के साथ स्पर्धा में अपना वक्त और ऊर्जा लगाते हैं। सही मायनों में सफल होने के लिये पहले हम खुद को पहचानें और फिर अपनी अंतरात्मा के साथ स्पर्धा करें।जीवन में सफल होने के लिए कोहरे से एक अच्छी बात सीखने को मिली कि जब जीवन में कोई रास्ता न दिखाई दे रहा हो तो, बहुत दूर तक देखने की कोशिश व्यर्थ है धीरे धीरे एक एक कदम चले रास्ता दिखता जायेगा।अंत में सभी से कहूँगाः- दुनिया के सफर में सब छोड़ दो पर सफलता की उम्मीद कभी मत छोड़ो क्योंकि जिस संसार की नींव ही आशा हो तो उसमे निराशा का क्या काम हैं।

“ एक समय ऐसा आया जब वह अपनी खुद की पहचान ही भूल गया और मौलिकता को खोकर दूसरों की नकल के लायक भी नहीं रहा और संसार से उसका नाम ही खत्म हो गया। इसका सबसे दुखद पहलू यह है कि वह अब भी अपनी विफलताओं के लिये खुद को दोषी नहीं मानता है और उसने अपनी विफलताओं और दूसरों की सफलताओं के लिए कुछ षड्यंत्रों और बहानों को सृजन कर लिया है। इस तरह से वह स्वयं को धोखा ही दे रहा है। वह स्वयं के प्रति ईमानदार नहीं है।

भारत में पनप रहे स्टार्ट-अप अब बहुराष्ट्रीय कम्पनियां बनने की ओर अग्रसर

भारत के लिए यह दशक भारतीय स्टार्ट-अप कम्पनियों को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों (एमएनसी) में परिवर्तित करने का है। भारत में पिछले केलेंडर वर्ष 2020 में 11 स्टार्ट-अप कम्पनियां, यूनीकॉर्न कम्पनियों में परिवर्तित हुई हैं। यूनिकॉर्न कम्पनी उस स्टार्ट-अप कम्पनी को कहा जाता है जिसका बाजार मूल्यांकन 100 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक का हो गया हो। भारत में इन कम्पनियों में निवेश तेज रफ़्तार से बढ़ा है। ये स्टार्ट-अप कम्पनियां अभी तक भारत के बाजार पर अधिक ध्यान देकर चल रही हैं परंतु इन्हें अब भारत के बाहर भी पैर फैलाने चाहिए और अपने आप को बहुराष्ट्रीय कम्पनी में परिवर्तित करना चाहिए। भारतीय कम्पनियां विदेशी बाजारों में अपना स्थान बनायें, इससे भारतीय ब्राण्ड विकसित होगा इसलिए इन कम्पनियों के लिए अपने उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय स्तर का रखना अब बहुत जरूरी हो गया है। भारत में स्टार्ट-अप कम्पनियां अब केवल भारतीय बाजार के लिए नहीं बल्कि वैश्विक वैल्यू चैन को भी ध्यान में रखकर बनाई जानी चाहिए। अभी हाल ही के समय में भारतीय कम्पनियां विदेशों में भी कई कम्पनियों को खरीद रही हैं, विशेष रूप से दवा एवं सूचना प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में।

केंद्र सरकार द्वारा बनायी गयी सरकारी नीतियों के चलते ही स्टार्ट-अप कम्पनियों को भारत में अपना व्यवसाय प्रारम्भ करने में आसानी हो रही है। ईज ओफ डूइंग बिजनेस के विभिन्न मदों में हुए सुधार के चलते भी स्टार्ट-अप कम्पनियों की बहुत मदद हो रही है एवं इसके कारण विदेशी निवेश के साथ साथ अब भारतीय कम्पनियां भी इन स्टार्ट-अप में निवेश करने लगी हैं। आज भारत, स्टार्ट-अप की दृष्टि से, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। इस क्षेत्र में अब विदेशी निवेश भी तेजी से बढ़ रहा है। इससे अन्य देशों का भारतीय बाजार पर विश्वास झलकता है।

वर्ष 2020 में तो कोरोना वायरस की महामारी के चलते भी भारत में 1200 सौदों के माध्यम से स्टार्ट-अप कम्पनियों में 1014 करोड़ अमेरिकी डॉलर का निवेश हुआ है। हालांकि यह निवेश वर्ष 2019 में हुए 1450 करोड़ अमेरिकी डॉलर से कम है परंतु सौदों की संख्या में वर्ष 2020 के दौरान 20 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। भारत आज 130 करोड़ से अधिक की जनसंख्या एवं तेज गति से आगे बढ़ रही भारतीय अर्थव्यवस्था के सहारे काफी अधिक संख्या में स्टार्ट-अप कम्पनियों को आकर्षित कर रहा है।

1 मार्च 2020 को भारत में 28,979 स्टार्ट अप में 3.37 लाख लोग कार्यरत थे। भारत की 50 प्रतिशत आबादी 27 वर्ष के नीचे है अतः भारत एक युवा देश है जिसका पूरा पूरा फायदा भारत को नए स्टार्ट-अप के रूप में मिल रहा है। अब इन नए नए क्षेत्रों में प्रारम्भ हो रहे स्टार्ट अप के चलते भारत विश्व में होने वाली नई औद्योगिक क्रांति में अपनी विशेष भूमिका निभा सकता है। न केवल विदेशी निवेश बढ़ रहा है बल्कि नवोन्मेष भी हो रहा है। मेक इन इंडिया भी स्टार्ट अप के विकास में महती भूमिका निभा रहा है।

भारत में तेजी से आगे बढ़ रहे स्टार्ट-अप में शामिल हैं, फ्लिपकार्ट (वर्ष 2007 में स्थापित, 25000 से अधिक रोजगार के अवसर एवं वर्ष 2019 में 43,615 करोड़ रुपए की आय), पेटीएम (वर्ष 2010 में स्थापित, 9000 से अधिक रोजगार के अवसर एवं वर्ष 2019 में 3,579 करोड़ रुपए की आय), ओयो (वर्ष 2013 में स्थापित), ओला (वर्ष 2010 में स्थापित) पॉलिसी बाजार (वर्ष 2008 में स्थापित), सविग्गी (वर्ष 2014 में स्थापित), जोमाटो (वर्ष 2008 में स्थापित) एवं रिविगो (वर्ष 2014 में स्थापित), आदि।

भारत में वर्ष 2020 के दौरान स्टार्ट-अप के क्षेत्र में हुए कुल निवेश का 90 प्रतिशत हिस्सा बैंगलोर, दिल्ली एवं मुम्बई में स्थापित किए गए स्टार्ट-अप कम्पनियों में हुआ है। जबकि आज आवश्यकता इस बात की है कि देश में टायर-2 एवं टायर-3 शहरों में भी स्टार्ट-अप कम्पनियां प्रारम्भ की जायें क्योंकि देश में टैलेंट की कोई कमी नहीं है परंतु इन छोटे छोटे शहरों में बस रहे टैलेंट पर भी

ध्यान देने की जरूरत है।

वर्ष 2020 के दौरान स्टार्ट-अप कम्पनियों में सबसे अधिक निवेश ई-कामर्स क्षेत्र के स्टार्ट-अप कम्पनियों में हुआ है। द्वितीय स्थान पर वित्तीय तकनीक से सम्बंधित स्टार्ट-अप कम्पनियां एवं तृतीय स्थान पर एड तकनीक से सम्बंधित स्टार्ट-अप कम्पनियां रही हैं। आज जबकि आवश्यकता इस बात की है कि कृषि क्षेत्र, टुरिजम, लोजिस्टिक, ट्रांसपोर्ट, ट्रैवल, शिक्षा आदि क्षेत्रों में अधिक से अधिक स्टार्ट-अप प्रारम्भ होने चाहिए क्योंकि इन क्षेत्रों में रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उत्पन्न किए जा सकते हैं।

यूनिकॉर्न कम्पनियों के व्यवसाय करने की सारी व्यवस्था पर हमारे देश में अभी भी ध्यान देने की बहुत जरूरत है। यूनिकॉर्न कम्पनियों की ओर यदि देखा जाय तो पता चलता है कि ये निजी निवेश अथवा विदेशी निवेश के दम पर ही आगे बढ़ रहे हैं कोई भारतीय बैंक अथवा देशी निवेश इनकी सहायता में बहुत कम ही आगे आ पा रहे हैं। इस तरह की कमियों को दुरुस्त करने की आज आवश्यकता है। करों की दर भी तुलनात्मक रूप से भारत में अधिक है इसलिए ये कम्पनियां बनती तो भारत में है लेकिन अपने आप को रजिस्टर विदेशों में, विशेष रूप से सिंगापुर में, कराती हैं। हमारे देश में न्याय व्यवस्था में भी सुधार करने की बहुत जरूरत है। एक बार कोई केस कोर्ट में जाता है तो इसके निपटान में बहुत समय लगता है, यह बात विशेष रूप से विदेशी निवेशकों को बहुत अखरती है। अतः देश में न्यायिक प्रक्रिया को सरल बनाए जाने की भी अत्यधिक आवश्यकता है।

“ भारत में तेजी से आगे बढ़ रहे स्टार्ट-अप में शामिल हैं, फ्लिपकार्ट (वर्ष 2007 में स्थापित, 25000 से अधिक रोजगार के अवसर एवं वर्ष 2019 में 43,615 करोड़ रुपए की आय), पेटीएम (वर्ष 2010 में स्थापित, 9000 से अधिक रोजगार के अवसर एवं वर्ष 2019 में 3,579 करोड़ रुपए की आय), ओयो (वर्ष 2013 में स्थापित), ओला (वर्ष 2010 में स्थापित) पॉलिसी बाजार (वर्ष 2008 में स्थापित), सविग्गी (वर्ष 2014 में स्थापित), जोमाटो (वर्ष 2008 में स्थापित) एवं रिविगो (वर्ष 2014 में स्थापित), आदि।

लगातार हो रहे वैश्य व्यवसायी वर्ग पर हमले हत्या लूट और अपहरण के खिलाफ राष्ट्रीय वैश्य महासभा करेगा चरणबद्ध आन्दोलन

उचित प्रतिनिधित्व के लिए जिला से लेकर पंचायत तक किया जाएगा संगठन निर्माण

राष्ट्रीय वैश्य महासभा बिहार प्रदेश की आयोजित एक दिवसीय चिंतन बैठक पटना के कंकड़बाग स्थित राजेन्द्र नगर टर्मिनल के सामने होटल एस भी आर के सभागार में प्रदेश कार्यकारिणी सहित विभिन्न जिलों के अध्यक्षों एवं प्रखंड अध्यक्षों के साथ सम्पन्न हुई. बैठक की अध्यक्षता विधायक और महासभा के प्रदेश अध्यक्ष समीर महासेठ संचालन कार्यकारी अध्यक्ष पीके चौधरी एवं आगत अतिथियों का स्वागत युवाध्यक्ष मंजीत आनन्द साहू ने एवं प्रस्ताव प्रदेश मुख्य प्रवक्ता शिवशंकर विक्रांत ने पढकर सर्वसम्मति से पारित कराया । प्रदेश भर में वैश्य - व्यवसायी वर्ग के ऊपर लगातार बढ़ते जा रहे हमले हत्या, लूट, फिरौती अपहरण, बलात्कार जैसी गम्भीर घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विधायक विजेंद्र चौधरी एवं प्रदेश अध्यक्ष विधायक समीर महासेठ ने संयुक्त रूप से कहा की राज्य सरकार की लचर कानून व्यवस्था के कारण आज हर शहर हर बाजार के भीतर डर और आतंक का माहौल है।

एक तरफ गुंडे और अपराधी तो दूसरे तरफ सरकारी नीतियां और अफशरशाही वैश्य - व्यवसायियों का जीना मुहाल कर रखा है। आज भी चाहे बड़ा हो या छोटा एवं मध्यम व्यापारी वर्ग सभी लॉक डाउन, नोटबन्दी जैसी काले कारनामों के कारण अपना व्यापार पटरी पर नहीं ला पाया है इसके लिए सरकारी स्तर पर किसी भी प्रकार की सहायता योजना नहीं होना जाहिर करता है कि चाहे राज्य सरकार हो केंद्र की सरकार किसी को रत्ती भर भी वैश्य व्यवसायियों की चिंता नहीं है। बैठक में सर्व सम्मति राज्य सरकार से मांग किया गया है कि कलवार, सूड़ी, रौनियार,पोद्दार, स्वर्णकार, वर्णवाल जातियों को अतिपिछड़ी जातियों में शामिल करने एवं अतिपिछड़े वर्ग को मिलने वाले आरक्षण के कोटे को बढ़ाने एवं व्यावसायिक आयोग गठन करने की मांग किया है। मांग किया गया है कि व्यवसायियो को अपने जान माल की रक्षा हेतु उन्हें हथियार का लाइसेंस बिना कोई बाधा के प्रदान किया जाय। राजधानी पटना में शहीद बृजबिहारी प्रसाद, दुःखन राम, एवं सीता राम केसरी जी की आदमकद प्रतिमा स्थापित किया जाय। महासभा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष पी.के.चौधरी ने कहा कि राष्ट्रीय वैश्य महासभा वैश्य - व्यवसायियों की रक्षा सुरक्षा के साथ - साथ राजनीति में समुचित प्रतिनिधित्व को लेकर बेहद गम्भीर है। इसी को लेकर फरवरी माह से महासभा का महाअभियान शहर से लेकर पंचायत तक संगठन निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है जिसके तहत वैश्य - व्यवसायियों एवं अतिपिछड़े वर्ग को संगठित कर उन्हें मुकम्मल रक्षा - सुरक्षा एवं समुचित प्रतिनिधित्व हाशिल हो इसके लिए लगातार एक कार्ययोजना पर काम करेगी।

प्रदेश मुख्य प्रवक्ता शिवशंकर विक्रांत ने कहा कि लोकसभा चुनाव एवं विधानसभा चुनाव में वैश्य व्यवसायी एवं अतिपिछड़े वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करने पर भी केन्द्रित होगा। ष्ट्रीय उपाध्यक्ष सतीश गुप्ता ने कहा कि सर्वाधिक आबादी के बावजूद वैश्य - अतिपिछड़े वर्ग के लोगों का उचित संख्या में लोकसभा, राज्यसभा ,विधानसभा एवं विधानपरिषद में नहीं होना संविधान और लोकतंत्र की बुनियादी ढांचे के विरुद्ध है। आजादी के 7 दशक बाद भी सामाजिक और राजनैतिक असंतुलन का होना सामाजिक राजनैतिक भेदभाव को जग जाहिर करता है। बैठक में राष्ट्रीय महासचिव डॉ प्रेम कुमार गुप्ता, डॉ मुनीलाल गुप्ता, प्रदेश महासचिव डॉ प्रकाश चंद्रा, प्रदेश मुख्य प्रवक्ता शिवशंकर विक्रांत, विजय प्रसाद, जयप्रकाश चौधरी, सोनू मुखिया, मोहन साह,धर्मेन्द्र साह, बबलू गुप्ता, अर्जुन चौधरी, कन्हैया पोद्दार, चंदन बागची, नरेश जायसवाल, शत्रुघ्न चौधरी, सुरेन्द्र महतो, राधेश्याम प्रसाद, कामता प्रसाद, जितेन्द्र साहू, राधेश्याम प्रसाद, विनय गुड्डू, निरंजन चौरसिया, राजगौरव टाईगर, राजकुमार गुप्ता, संजय जायसवाल, पंकज जायसवाल, राजेन्द्र कुमार राजू वियाहुत, प्रमोद गुप्ता, रामाधार प्रसाद, मुन्ना जायसवाल, राजीव रंजन, दिवाकर गुप्ता, जयकृष्ण भगत,अमित भगत, गणेश चौधरी, राजेश केशरी, संतोष केशरी, राकेश जायसवाल, उदय शंकर साह, मधुसूदन जायसवाल, दिलीप सर्राफ आदि उपस्थित थे।

> “ एक तरफ गुंडे और अपराधी तो दूसरे तरफ सरकारी नीतियां और अफशरशाही वैश्य - व्यवसायियों का जीना मुहाल कर रखा है। आज भी चाहे बड़ा हो या छोटा एवं मध्यम व्यापारी वर्ग सभी लॉक डाउन, नोटबन्दी जैसी काले कारनामों के कारण अपना व्यापार पटरी पर नहीं ला पाया है।

गणतंत्र संवैधानिक बनाम लोकतांत्रिक

आजादी से तुरन्त पहले भारत में ब्रितानी ताज का राज था। उससे पहले मुगलिया सल्तनतों समेत अनेक छत्रों के तले संचालित व्यवस्थायें भी राजतांत्रिक ही थीं। राजतंत्र बुरा होता है, गणतांत्रिक व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ। यही सोचकर हमने आजाद भारत का संविधान बनाया। 26 जनवरी, 1950 को भारत, संसदीय गणतंत्र हो गया। आज हम भारत को दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र बताते हुए गौरव का अनुभव करते हैं। प्रश्न है कि यदि गणतंत्र, सचमुच गण यानी लोगों की, लोगों के द्वारा, लोगों के हित में संचालित व्यवस्था है, तो फिर दुनिया के तमाम गणतांत्रिक देशों के नागरिकों को अपने साझा हकूक व हितों के लिए आंदोलन क्यों करने पड़ रहे हैं ? आंदोलित नागरिकों को पीटा क्यों जा रहा है ? नागरिकों को उनके मौलिक कर्तव्य क्यों याद दिलाने पड़ रहे हैं ? नागरिक कौन होगा; कौन नहीं ? यह तय करना, स्वयं नागरिकों के हाथों में क्यों नहीं है ? दूसरी तरफ, यदि राजतंत्र इतना ही बुरा था, तो सुशासन के नाम पर हम आज भी रामराज्य की परिकल्पना को साकार करने का सपना क्यों लेते हैं ? आज भी राजा-रानी वाला देश भूटान, खुशहाली सूचकांक में दुनिया का नंबर वन क्यों है ? आखिरकार, हम ऐसी किसी व्यवस्था को अच्छा या बुरा कैसे बता सकते हैं, जो संचालन भूमिका में अच्छे या बुरे इंसान के आ जाने के कारण क्रमशः अच्छे अथवा बुरे परिणाम देती हो ?

यूं एक गणतंत्र के रूप में भारत सात दशक पूरा कर चुका। किंतु इससे पूर्व नागरिकता प्रकरण व जम्मू-कश्मीर के हालात को आईना मानकर लोकतांत्रिक सूचकांक में भारत की रैंकिग 10 पायदान नीचे आ गई है। 22 दिसम्बर झ्र प्रख्यात पर्यावरणविद् स्वर्गीय श्री अनुपम मिश्र जयंती के मौके पर स्वराज और गांधीजी विषय व्याख्यान में नामी पत्रकार बनवारी जी द्वारा उठाए ऐसे प्रश्नों और जवाब में पेश उद्धहरण व तर्क गणतंत्र के वर्तमान ढांचे पर पुनर्विचार के लिए भी विवश करते हैं। आधुनिक इतिहास में ग्रीक को दुनिया का पहला गणतंत्र माना जाता है। गणतांत्रिक मूल्यों के आधार पर हुए आकलन में दुनिया के 195 देशों में मात्र 75 देश ही गणतांत्रिक राह के राही करार दिए गए हैं। मात्र 20 को ही पूर्णतया गणतांत्रिक मूल्यों के देश माना गया है। इनमें 14 देश यूरोप के हैं। शेष 55 को त्रुटिपूर्ण गणतांत्रिक चेतना का देश माना गया है। इनमें भारत भी एक है। भारत में शासकीय कार्यप्रणाली और राजनीतिक संस्कृति में बेहतरी की आवश्यकता बताई गई है। अतः विचार तो करना ही होगा कि हम कैसा गणतंत्र हैं और हमें कैसा गणतंत्र हो जाना है ?

राजतंत्र जैसा गणतंत्र हम

राजतंत्र में राज्य, राजा की संपत्ति होता था। एक राजा द्वारा दूसरे राजा को जीत लिए जाने की स्थिति में, राज्य दूसरे राजा की संपत्ति हो जाता था। गणतंत्र में राष्ट्र, सार्वजनिक महत्व व जवाबदेही का विषय बताया जाता है, किंतु क्या आज सत्ता में आरुढ़ दल, देश को अपनी मनचाही दशा और दिशा में ले जाने की जिद्द में लगे नहीं दिखते; जैसे देश सिर्फ उन्ही की संपत्ति हो ? क्या सत्ता, सार्वजनिक महत्व की संपत्तियों को भी अपने मनचाहे निजी हाथों को सौंपती नहीं रही ?

राजतंत्र में निर्णय लेने, योजना-कानून बनाने और कर तय करने का काम राजा और उसका मंत्रिमण्डल करता था। लोकतंत्र में भी तो यही हो रहा है। दल आधारित राजनीति में विल्प तो नेतृत्व ही जारी करता है; बाकी लोग तो संसद में बस, अपने-अपने दल द्वारा तय पक्ष्ा-विपक्ष में हाथ ही उठाते हैं। तय निर्णयों-

> “आज हम भारत को दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र बताते हुए गौरव का अनुभव करते हैं। प्रश्न है कि यदि गणतंत्र, सचमुच गण यानी लोगों की, लोगों के द्वारा, लोगों के हित में संचालित व्यवस्था है, तो फिर दुनिया के तमाम गणतांत्रिक देशों के नागरिकों को अपने साझा हकूक व हितों के लिए आंदोलन क्यों करने पड़ रहे हैं ?

नीतियों को जमीन पर उतारने का काम राजतंत्र में भी कार्यपालिका करती थी। गणतंत्र में भी वही कर रही है। न्याय पहले भी राजा व उसके मंत्रिमण्डल के हाथ था; अब भी न्यायाधीश, लोकपाल आदि की नियुक्ति जनता के हाथ में नहीं है। लोगों के जीवन-मृत्यु का अधिकार भी लोगों के पास नहीं है। बलात्कारी को यदि मृत्युदण्ड देना है, तो न्यायालय देगा। उसे जीवन या मृत्यु देने का अधिकार आज भी पीड़िता के हाथ में नहीं है। यदि आत्मरक्षा के प्रयासों के दौरान पीड़िता के हाथों बलात्कारी की मृत्यु हो जाए, तो पीड़िता को कानूनन सजा भुगतनी पड़ती है। तो फिर राजतंत्र और लोकतंत्र में फर्क क्या है, सिवाय चुनाव के ? तिस पर भी चुनाव के कायदे, प्रक्रिया, चुनाव घोषणापत्र से लेकर उम्मीदवार तक कौन होगा; कुछ भी लोगों के हाथ में नहीं।

दुनिया के 36 देशों में संसदीय व्यवस्था है। लोकसभा, लोकप्रतिनिधियों की सभा है। लोकप्रतिनिधियों द्वारा चुनी सभा होने के कारण, राज्यसभा लोकप्रतिनिधियों की उच्चसभा है। तद्नुसार, हमारे सांसदों को संसद में लोकप्रतिनिधि की तरह व्यवहार करना चाहिए। किंतु वे तो दल के प्रतिनिधि अथवा सत्ता के पक्ष-विपक्ष की तरह व्यवहार करते हैं। जहां सत्ता है, वहां गणतंत्रता कहां ? यह तो राजतंत्र ही हो गया न ? संभवतः जिस गणतंत्र को हमने राजंतत्र का विकल्प समझा था, वह असल में राजतंत्र का ही नया संस्करण है। अंग्रेजी में गणतंत्र को रिपब्लिक और लोकतंत्र को डेमोक्रेसी कहा जाता है। अतः निष्कर्ष रूप में यह भी कहा जा सकता है कि हम संवैधानिक गणतंत्र तो हैं, किंतु लोकतांत्रिक गणतंत्र होने के लिए हमें अपनी चाल, चरित्र और व्यवहार में अभी बहुत कुछ बेहतर करना बाकी है। क्या करें?

एक सपना आसमानी से जमीनी होते जाने का

गौर करें कि संसदीय गणतंत्र, एक छतरी की तरह है। समय-समय पर आने वाली बरखा रूपी जनाकांक्षा की बूंदें, जिसके धारक प्रतिनिधियों को स्पर्श करती भी हों, तो भिगोती नहीं। सिर्फ इतना नहीं, बल्कि धारक प्रतिनिधि इस बात के लिए ज्यादा सतर्क रहते हैं कि वे किसी भी तरह भीगने न पाएं। हम, भारत विविध भूगोल, संस्कृति व जीवन शैलियों का देश हैं। एकसमान योजना-परियोजना-तौर-तरीका-तकनीक को सभी पर लागू करना; सभी के लिए हितकरी सिद्ध हो; भारत में यह जरूरी नहीं। अतः भारत को एक ऐसे विशाल हृदया निर्मल तालाब की प्रकृति का गणतंत्र होने की जरूरत हो; जिसमें दूर-दूर से आये जल रूपी विविध विचार और समृद्धि प्रयास समा सके; कई रंग के कमल, मछलियां और अन्य जीव-जन्तु न सिर्फ आवास पा सकें, बल्कि उसकी सुन्दरता व गतिविधियों में योगदान दें। संभवतः इसीलिए राष्ट्रपिता गांधी ने भारत को संवैधानिक तौर पर संसदीय की बजाय, पंचायती गणतंत्र बनाने का दस्तावेज संविधान सभा को सौंपा था। पंचायतीराज विधेयक को संसद में पेश करते वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भारत के लोगों को अधिकतम लोकतंत्र, अधिकतम सत्ता सुपुर्द कर, सत्ता के दलालों का खात्मा करने की मंशा इभी इसीलिए जाहिर की थी। उन्होने याद दिलाया था झ जब हम पंचायतों को वही दर्जा देंगे, जो संसद और विधानसभाओं को प्राप्त है; तो हम लोकतांत्रिक भागीदारी के लिए दरवाजे.खोल देंगे। सत्ता के दलालों ने इस तंत्र पर कब्जा कर लिया है। सत्ता के दलालों के हित में इस तंत्र का संचालन हो रहा है।सत्ता के दलालों के नाशपाश को तोड़ने का एक ही तरीका है और वह यह है जो जगह उन्होने घेर रखी है, उसे लोकतंत्र की प्रक्रियाओं द्वारा भरा जाए। सत्ता के गलियारों से सत्ता के दलालों को निकाल कर, पंचायतें जनता को सौंपकर, हम जनता के प्रतिनिधियों पर और ज़िम्मेदारी डाल रहे हैं कि वे सबसे पहले उन लोगों की तरफ ध्यान दें, जो सबसे करीब हैं; सबसे वंचित हैं; सबसे जरूरतमंद हैं।. हमें जनता में भरोसा है। जनता को ही अपनी किस्मत तय करनी है।

73वें-74वें संविधान संशोधन ने पारित होकर दर्जा भी दिया और ज़िम्मेदारी भी डाली। मोदी सरकार द्वारा शुरू ग्राम पंचायत विकास योजना ने भी एक खिड़की खोली है। संसदीय मतलब आसमानी, पंचायती मतलब जमीनी गणतंत्र; किंतु हम, भारत के नागरिक आज भी यह फर्क हासिल करने को प्रेरित नहीं दिखाई दे रहे। हम, आज भी आसमानी गणतांत्रिक व्यवस्था की ओर ही ताक रहे हैं। हमें हर जरूरत की पूर्ति के लिए सरकार के समक्ष मांग का कटोरा लेकर ताकने की आदत जो डाल दी गई है। पंचायती गणतंत्र के सपने को जमीन पर उतारने से हिचकिचाहट, आज भी राज्यों के पंचायतीराज अधिनियम में साफ दिखाई दे रही है। एक ओर तारीख-पे-तारीख के खेल में खिंचते मुकदमों से हैरान-परेशान अवाम; दूसरी ओर अनेक ने न्याय पंचायती व्यवस्था को लागू नहीं किया; एक प्रदेश की विधायिका ने लागू को ही मिटा दिया! सत्ता पाकर गांव का प्रधान, पंच और ग्रामसभा में बंट जाना। इस सत्ता-चरित्र से उबरे बगैर पंचायती गणतंत्रता की ओर बढ़ना असंभव है और आर्थिक साम्राज्यवाद के खतरों से अंतिम जन को बचाना भी।

पंचायती मतलब न सत्ता, न प्रजा

गौर करें कि यहां पंचायती का मतलब यह नहीं कि प्रभाव तो गांव में होना है; सोचने, योजना बनाने और क्रियान्वयन के तरीके कहीं औरकेन्द्र में तय हों। इस पर भी घोषणा और अपेक्षा की लोगों को सहभागी बनाना है। यह तो सिद्धांततः उलट बात है। यही तो हमारे संसदीय गणतंत्र में कमी है। हमें एकमत होना होगा कि पंचायती का मतलब, केन्द्र से सोची और उतारी गई योजनाओं को क्रियान्वित करने वाली एजेन्सी हो जाना नहीं है। पंचायती मतलब सत्ता का प्रधान-पंच के हाथ में आ जाना भी नहीं।

आइए, हम इससे आगे सोचें। अतीत में झांकें

पंचायती का मतलब परंपरागत पंचायती; जहां कोई सत्ता नहीं, कोई प्रजा नहीं। कार्य विशेष के लिए बैठी सभा, कार्य सम्पन्न होने के साथ ही विसर्जित हो गई। गांव की आय में किसका कितना अंश गांव के पुरोहित-कारीगर का कितना; व्यवस्था संचालकों को कितना ? सब कुछ परम्परा से तय था। अंश प्राप्तकर्ता को मांगने नहीं आना पड़ता था। अंश को एकत्र करना; उसके प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना भी गांव द्वारा तय ग्रामणी का काम। नेतृत्व से लेकर निर्णय तक सभी कुछ सामिलात, सर्वसम्मत, सम्भावी, स्वावलम्बी, न्यायप्रिय।

पंचायती लोकतंत्र का मतलब, अपने बारे में खुद सोचने, खुद नियोजित करने और खुद ही उसका क्रियान्वयन करने वाली व्यवस्था। क्रियान्वयन करने वाले हाथ, जवाबदेही, संसाधन भी उसी स्थान के हों, जिस भूगोल पर उसका सीधे-सीधे प्रभाव होना है; चाहे फिर वह गांव हो या नगर। यही तो असली आजादी थी; असली स्वराज। आखिरकार, यही तो वह व्यवस्था थी, जिसे भारत की सुख, समृद्धि और स्वतंत्रता का अधिकतर श्रेय देते हुए ब्रिटिश गर्वनर चार्ल्स मेटकाफ ने लिखा था झ ये गांव समाज छोटे-छोटे ऐसे प्रजातंत्र हैं, जिन्हे अपनी आवश्यकता की लगभग हर वस्तु अपने ही भीतर मिल जाती है; जो विदेशी संबंधों से लगभग स्वतंत्र होते हैं। ये ऐसी परिस्थितियों में भी टिके रहते हैं, जिनमें दूसरी हर वस्तु का अस्तित्व मिट जाता है।

> 73वें-74वें संविधान संशोधन ने पारित होकर दर्जा भी दिया और ज़िम्मेदारी भी डाली। मोदी सरकार द्वारा शुरू ग्राम पंचायत विकास योजना ने भी एक खिड़की खोली है। संसदीय मतलब आसमानी, पंचायती मतलब जमीनी गणतंत्र; किंतु हम, भारत के नागरिक आज भी यह फर्क हासिल करने को प्रेरित नहीं दिखाई दे रहे। हम, आज भी आसमानी गणतांत्रिक व्यवस्था की ओर ही ताक रहे हैं।

आइका बिहार कार्यकारिणी की प्रथम बैठक संपन्न

पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता आदरणीय श्री उपेन्द्र बाबू एवं अधिवक्ता आदरणीया वीणा जी के आवास परिसर में आइका बिहार कार्यकारिणी की प्रथम बैठक उल्लासपूर्ण वातावरण में सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ।

बैठक की अध्यक्षता आइका के अध्यक्ष आदरणीय श्री अशोक कुमार चौधरी जी ने की जबकि संचालन आइक बिहार के महासचिव आदरणीय श्री राजेश रौशन जी ने की ।केन्द्रीय पर्यवेक्षक के रूप आइका बिहार प्रदेश प्रभारी आदरणीय श्री जय कृष्ण भगत कलवार उपस्थित थे। कार्यक्रम का शुभारंभ आइका बिहार की उपाध्यक्ष सह पटना उच्च न्यायालय की माननीय अधिवक्ता श्रीमती सुप्रिया भगत जी के नेतृत्व में गायत्री मंत्र एवं महामृत्युंजय जाप से शुरूआत किया गया। बैठक में कार्यकारिणी के लगभग सभी साथी, प्रथम संरक्षक और समाज के लिये समर्पित इंस्पेक्टर आदरणीय श्री संजीव साहिल जी, अन्तर्राष्ट्रीय वैश्य महासभा के कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय श्री पी के चौधरी जी, आइका के संस्थापक सदस्य एवं कलवार अधिकार महासम्मेलन के संयोजक आदरणीय श्री शिव शंकर विक्रांत जी, समाज के लिये समर्पित दवा व्यवसायी एवं अभिभावक स्वरूप आदरणीय श्री दिवाकर बाबू, समाज के लिये समर्पित संवेदक आदरणीय श्री अखिलेश जयसवाल जी, तन मन धन से सहयोग करने वाले कोयला व्यवसायी आदरणीय श्री ओम प्रकाश बाबू , बाराबंकी लखनऊ से चलकर आये आदरणीय श्री सुधीर कुमार चौधरी जी, झारखंड प्रदेश के महासचिव आदरणीय श्री गणेश प्रसाद गुप्ता जी की गरिमामय उपस्थिति कार्यक्रम में चार चाँद लगा गये।

कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुये आइका बिहार के प्रदेश उपाध्यक्ष गायत्री मंत्र एवं महामृत्यन्जय से सभागार को गुंजायमान किया। तत्पश्चात सभी उपस्थित साथियों ने बारी बारी से देवताद्वय श्री सहस्त्रार्जुन जी एवं श्री बलभद्र जी को श्रद्धासुमन अर्पित किया। कला एवं सांस्कृतिक मंच की संयोजिका श्रीमती शालिनी जयसवाल जी के अगुवाई में श्रीमती सुप्रिया भगत, केन्द्रीय टीम के महिला मंच बिहार के प्रभारी श्रीमती पूनम जयसवाल जी ने कलवार गान से सभी का स्वागत किया । तत्पश्चात दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया।

आइका बिहार के महासचिव आदरणीय श्री राजेश रौशन जी ने विषय आइका बिहार के विस्तार एवं सशक्त बनाने पर विचार विमर्श प्रवेश कराते हुये इसकी महत्ता पर प्रकाश डाला। सभी उपस्थित साथियों ने अपना परिचय देते हुये विषयवस्तु पर अपनी राय रखी। परिचय सत्र के उपरांत सभी साथियों को पुष्प माला और अंगवस्त्र से सम्मानित किया गया । अपने उदबोधन में आदरणीय महासचिव ने सभी संयोजकों और जिला अध्यक्ष से अपील की कि मार्च तक प्रखण्ड स्तर तक सांगाठनिक ढांचा खड़ा कर लिया जाय। अध्यक्षीय सम्बोधन में आदरणीय अशोक बाबू ने सभी आगंतुकों स्वागत करते हुये विगत छह महीने में संगठन द्वारा समाज हित में किये गये कार्य का उल्लेख किया और सभी उपस्थित साथियों की सहमति से भावी संकल्प भी लिया कि

1. कलवार समाज को अतिपिछड़ा में शामिल करने के लिये 11 सदस्यीय टीम का गठन
2. अपने समाज के किसी भी क्षेत्र प्रतिभावान बच्चे को वर्ष में एक बार सम्मानित करना।
3. अपने समाज के पुरोधा डॉक्टर काशी प्रसाद जी एवं ई.बृज बिहारी प्रसाद जी की जयंती समारोह वर्ष में एक बार करना।
4. उन्होंने अपील की कि किसी भी स्तर के चुनाव में हरहाल में अपने स्वजाति को ही वोट दें जिससे हमारी मजबूती का एहसास होगा।
5. उन्होंने घोषणा की कि स्वयं द्वारा संचालित श्याम हॉस्पीटल में अपने समाज को 25% की छूट दी जायेगी और समाजबंधुओं से भी अपील की कि वे भी समाजहित में इस तरह का लाभ देने पर गंभीरता से विचार करें।

सुप्रिया भगत जी ने सभी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक के समापन की घोषणा की और स्वादिष्ट भोजन के आमंत्रित किया। भोजनोपरान्त सभी साथी अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान किया। बैठक में उपरोक्त साथियों के अलावा मुख्य रूप से आइका बिहार कार्यकारी अध्यक्ष श्री विशाल कुमार गप्पू जी , सर्वश्री गंगोत्री बाबू , राधेश्याम प्रसाद जी, राजेन्द्र प्रसाद राजू जी, जगत नारायण कलवार, दीनदयाल कुमार अधिवक्ता, महादेव चौधरी जी, कृष्ण कुमार चौधरी जी, प्रकाश चौधरी जी, धर्मेंद्र कुमार चौधरी जी, पटना जिला के नवनियुक्त अध्यक्ष राजीव रंजन जी, कृष्णा चौधरी जी, उमेश प्रसाद जी, अरविंद कुमार जी, मनोज कुमार जयसवाल जी, सोनू कुमार भगत जी, नरेश जयसवाल जी, रवि कुमार जयसवाल, दिलीप कुमार शाह जी, संतोष कुमार व्याहुत जी, मधुसूदन जयसवाल जी, त्रिपुरारी कुमार भारती जी, पवन कुमार चौधरी जी, अजय कुमार चौधरी जी, नन्द किशोर प्रसाद जी, अमित भगत जी, अमरजीत रवि जी, अभिषेक कुमार जी , सतीश कुमार जयसवाल जी, जय मंगल चौधरी जी, शैलेश कुमार गुप्ता जी, एम के जयसवाल जी , रवि कुमार जयसवाल जी , मुकेश कुमार चौधरी जी एवं अन्य साथी उपस्थित थे।

सादगी परम विशेषज्ञता है

सादगी एक महान गुण है जो व्यक्ति जीवन में पालन कर सकता है। हमें बुद्धिमानों द्वारा सरल जीवन और उच्च विचार में विश्वास करने के लिए सही सलाह दी जाती है। सादगी एक ऐसा गुण है जो हमें कुछ समझने या करने में आसान बनाता है। दूसरी ओर समाजवाद, सभ्य प्रकृति, लालित्य और / या जीवन और चीजों के प्रति एक परिष्कृत दृष्टिकोण को दर्शाता है। एक गुणवत्ता के रूप में सादगी, विचार, उपस्थिति और जीवन शैली पर भी लागू हो सकती है। महापुरुष हमेशा सरल पुरुष होते हैं। विश्व के अधिकांश महान नेताओं ने सादा जीवन व्यतीत किया और अपनी सादगी से बहुत कुछ हासिल किया।

सरलता हमारे जीवन को सरल बनाना गैर-जरूरी चीजों को खत्म करने, अनावश्यक अराजकता को दूर करने और एक ऐसा जीवन बनाने के बारे में है जो जीवन की प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करता है और उन चीजों को करता है जो संतुष्टि देते हैं। सरलता लाना कोई सरल प्रक्रिया नहीं है। यह एक यात्रा है खुशी और शोधन की. सादगी एक महान गुण है जिसका महान नेताओं और हमारे पूर्वजों ने हमेशा अनावश्यक चिंताओं से मुक्त करने के लिए सरल जीवन जीने पर जोर दिया। सादगी एक ऐसा गुण है जो समझने में कुछ आसान बनाता है। दूसरी ओर, परिष्कार चीजों और जीवन की ओर परिष्कृत रूप दिखाता है। सादगी का विचार, जीवन शैली, उपस्थिति, शिक्षाओं आदि पर लागू किया जा सकता है।

हृदय की पवित्रता, मानसिक सरलता और आंतरिक संवेदनशीलता हमारी यात्रा के अंतिम साधन बन सकते हैं। मौलिक रूप से, सादगी एक मानसिक स्थिति को इंगित करती है, जिसे फिर जीवन के भौतिक पहलुओं पर अनुमानित किया जाता है। जब गांधी का निधन हुआ, तो उनके पास दस से भी कम वस्तुएँ थीं, और उनके पास अपना घर नहीं था। गांधी एक समृद्ध परिवार में पले-बढ़े, लेकिन भौतिक भटकाव से नहीं चूके, क्योंकि वे गैर-आधिपत्य के व्यक्ति थे।

सिद्धार्थ गौतम, जो बाद में बुद्ध बने, ने भी एक सरल और आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए एक राजा के भौतिक गुणों को दूर कर दिया। लेकिन हमें सरल होने के लिए ऐसे न्यूनतम जीवन जीने की आवश्यकता नहीं है। हमें भी सरल होने के लिए सांसारिक अर्थों में अनभिज्ञ होने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिए, गांधी ने खुद इंग्लैंड में कानून का अध्ययन किया था और एक शिक्षित व्यक्ति थे, और सिद्धार्थ गौतम एक राजकुमार थे और महल और इसकी सुख-सुविधाओं के दायरे में काफी संरक्षित थे।

इतिहास हमें सरल व्यक्तित्व जैसे महात्मा गांधी, मदर थेरेसा, स्वामी विवेकानंद इत्यादि के कई उदाहरण प्रदान करता है। अगर हम उनके जीवन पर गौर करें तो यह स्पष्ट है कि वे एक साधारण जीवन जीते थे। महात्मा गांधी ने हमेशा स्वदेशी पर जोर दिया और ऐसा होने के लिए उन्होंने स्वयं केवल लुंगी पहनी और विभिन्न सत्याग्रह और अन्य बैठकों के दौरान देश की यात्रा की। ठीक उसी तरह मदर थेरेसा ने भी सादा जीवन व्यतीत किया और जीवन भर कई रोगियों की मदद की। स्वामी विवेकानंद एक अन्य महान आध्यात्मिक नेता थे जिन्होंने लाखों युवाओं को अपनी बुद्धिमत्ता और सादगी से प्रेरित किया।

सादा जीवन हमेशा मानसिक शांति देता है, दूसरी ओर जो पैसे के लालच में पीछे चलता है, वह कई मनोवैज्ञानिक मुद्दों का अनुभव करता है जैसे कि अवसाद, जीवन में किसी भी चीज पर एकाग्रता की कमी, असंतोष और कभी-कभी कई अन्य बड़ी समस्याएं भी। सरल जीवन के साथ हम भौतिकवादी संपत्ति के लिए कोई इच्छा नहीं रखेंगे और एक शांतिपूर्ण दिमाग रखने में सक्षम होंगे। यही बातें गौतम बुद्ध ने सिखाई हैं और वे अपनी सरल विचार प्रक्रिया से भी अंगुली मां की विचार प्रक्रिया को बदल सकते हैं। सादगी पैसे के अश्लील प्रदर्शन के बजाय परिष्कार का सामना करती है। साधारण उपस्थिति एक मानवीय स्तर पर अधिक लोगों से जुड़ने का एक तरीका है, क्योंकि साधारण उपस्थिति लगभग मन को मन से संदेश भेजती है। सरल उपस्थिति भौतिकवादी लाभ पर एक जुनून के बजाय जीवन के प्रति एक परिष्कृत दृष्टिकोण दिखाती है। दूसरी ओर, हाल के दिनों में एक व्यक्ति महामारी के समय एक सोने का मुखौटा लाया, जो स्पष्ट रूप से धन शक्ति के अपने अशिष्ट प्रदर्शन को दर्शाता है। आइए हम राजनीति और राजनीतिक जीवन में लोगों के डोमेन पर ध्यान दें। ऐसे कई लोग हैं जिन्हें कई भ्रष्टाचार घोटालों में दोषी ठहराया गया है और उसी के लिए जेल में डाल दिया गया है। दूसरी ओर, तेलंगाना राज्य के पूर्व राज्य विधान सदस्य गुम्मदी नरसैया जैसे कुछ लोग हैं जिन्होंने एक साधारण जीवन व्यतीत किया और लोक कल्याण के लिए समर्पित रहे।

भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्ट्र एपीजे अब्दुल कलाम एक सादा जीवन दिखाने और लोगों का दिल जीतने के लिए एक उत्कृष्ट उदाहरण हैं। यहां तक कि उन्होंने अपने आधिकारिक वाहन का इस्तेमाल निजी उद्देश्यों के लिए भी नहीं किया था, साथ ही उन्होंने अपने परिवार के किसी भी सदस्य के लाभ के लिए अपनी शक्ति और अधिकार का उपयोग नहीं किया था, जो उनके भाई के सरल जीवन से भी स्पष्ट है। साथ ही पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा सादा जीवन प्रदर्शित करने के लिए एक उदाहरण हैं। वह अपनी सादगी के साथ लाखों अमेरिकियों के साथ-साथ अन्य नेताओं के दिलों में भी जगह बना सके।

> “हृदय की पवित्रता, मानसिक सरलता और आंतरिक संवेदनशीलता हमारी यात्रा के अंतिम साधन बन सकते हैं। मौलिक रूप से, सादगी एक मानसिक स्थिति को इंगित करती है, जिसे फिर जीवन के भौतिक पहलुओं पर अनुमानित किया जाता है। जब गांधी का निधन हुआ, तो उनके पास दस से भी कम वस्तुएँ थीं, और उनके पास अपना घर नहीं था।

मनुष्य की मृत्यु का कारण पुनर्जन्म लेकर कर्मफल प्राप्त करना है

मनुष्य अपनी माता से इस संसार में जन्म लेता है। आरम्भ में शैशव अवस्था होती है। समय के साथ उसके शरीर व ज्ञान में वृद्धि होती है। वह माता की बोली को सुनकर उसे समझने लगता है व कुछ समय बाद बोलने भी लगता है। शैशव अवस्था बीतने पर किशोर व कुमार अवस्था आरम्भ होती है। समय के साथ यह भी बीतती है। इस अवस्था में शरीर और बड़ा व बलवान हो जाता है। उसका ज्ञान भी अपनी माता व आचार्यों की शिक्षा से वृद्धि को प्राप्त होता है। इसके बाद युवावस्था आती है और मनुष्य इस अवस्था में रहते हुए अपनी शिक्षा व विद्या पूरी करता है। शरीर यौवनावस्था में पूर्ण वृद्धि को प्राप्त हो जाता है। इसके बाद शरीर की वृद्धि प्रायः नहीं होती। इस अवस्था में वह विवाह कर सृष्टि क्रम को जारी रखने में सहायक बनता है। जैसे उसके माता-पिता ने उसे जन्म दिया था, उसी प्रकार वह भी संसार में विद्यमान आत्माओं को अपनी धर्मपत्नी के द्वारा जन्म देकर उनका पालन व पोषण करता है। अपना पोषण करते हुए तथा माता-पिता एवं सन्तानों के पोषण के साथ वह वृद्धावस्था को प्राप्त होता है। वृद्धावस्था मुनष्य जीवन की अन्तिम अवस्था कही जाती है। इस अवस्था में दिन प्रतिदिन उसके शरीर में बल की न्यूनता होती जाती है। वह युवावस्था की तरह से काम नहीं कर सकता। अधिक आयु होने पर उसे कुछ रोग भी हो जाते हैं। उनका उपचार कराना होता है। 60 से 80 या 85 वर्ष की आयु के मध्य अधिकांश स्त्री व पुरुषों की मृत्यु हो जाती है। परिवार के लोग व इष्ट-मित्र अपने स्वजन व मित्र आदि की मृत्यु पर दुःख व्यक्त करते हैं और कुछ दिनों बाद स्थिति सामान्य हो जाती है।

हमने यह एक मनुष्य के जीवन का संक्षिप्त वर्णन किया है। मनुष्य की मृत्यु क्यों होती है? यह प्रश्न प्रायः सभी के मन में उठता है। लोग इस प्रश्न को टाल जाते हैं और इस पर विचार करना निरर्थक माना जाता है। हमारे देश में ऋषि दयानन्द हुए जिन्होंने अपने घर में अपनी बड़ी बहिन व चाचा की मृत्यु देखी तो उन्हें वैराग्य हो गया था। मृत्यु के भय से वह इतने व्याकुल हुए थे कि मृत्यु की औषधि की तलाश करने के लिये वह अपनी आयु के 22 वें वर्ष में घर से चले गये और साधु, सन्तो, योगियों व विद्वानों की सगति कर ईश्वर के सच्चे स्वरूप और मृत्यु की औषधि की खोज करते रहे। उनसे पूर्व महात्मा बुद्ध को वृद्धावस्था की समस्याओं व मृत्यु की घटना देखकर वैराग्य हुआ था और उन्होंने भी अपना घर त्याग दिया था तथा ज्ञान की प्राप्ति के लिये वह वनों में चले गये थे।

मृत्यु क्यों होती है, इसका उत्तर महाभारत के एक अंग गीता नामक ग्रन्थ में मिलता है। गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण द्वारा दिया गया यह ज्ञान वेद व योग आदि ग्रन्थों में उपलब्ध है एवं इससे जन्म व मृत्यु पर प्रकाश पड़ता है। मृत्यु का मुख्य कारण मनुष्य का अपना जन्म होता है। यदि जन्म न हुआ होता तो उसकी मृत्यु भी न होती। जन्म क्यों होता है? इसका उत्तर है कि क्योंकि मनुष्य की उसके जन्म से पूर्व कहीं मृत्यु हुई होती है। मृत्यु से पूर्व भी मनुष्य अनेक प्राणी योनियों में से किसी एक योनि में जीवन निर्वाह कर रहा होता है। वहां भी उसे शैशव, किशोर, युवा, प्रौढ़ तथा वृद्ध अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। वृद्धावस्था में वह युवावस्था की भांति कर्म करने में वह स्वतन्त्रता नहीं पाता जिसकी उसे आवश्यकता होती है। वृद्ध शरीर प्रायः रोगों का घर भी बन जाता है। अतः जीवात्मा को अपने पूर्व व वर्तमान जन्म के कर्मों का भोग कराने के लिये परमात्मा नया जीवन प्रदान करते हैं जिसके लिए उसे मृत्यु की प्रक्रिया से गुजर कर जन्म प्राप्त होता है। जन्म प्राप्त होने पर वह अपने पूर्वजन्म के संस्कारों के आधार पर जीवन आरम्भ कर अपने परिवेश के अनुसार ज्ञान प्राप्त कर अपना जीवन व्यतीत करता है। मृत्यु का कारण जन्म और जन्म का कारण कर्म वा पाप-पुण्य हुआ करते हैं। यह जन्म मरण का चक्र अनादि काल से चल रहा है और अनन्त काल तक इसी प्रकार चलता रहेगा। परमात्मा अनादि काल से बार-बार इसी निमित्त प्रकृति से इस सृष्टि का निर्माण करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। सृष्टि 4.32 अरब वर्षों की अपनी आयु तक कार्यरत रहने के बाद प्रलय को प्राप्त होगी। 4.32 अरब वर्ष की प्रलय वा रात्रि

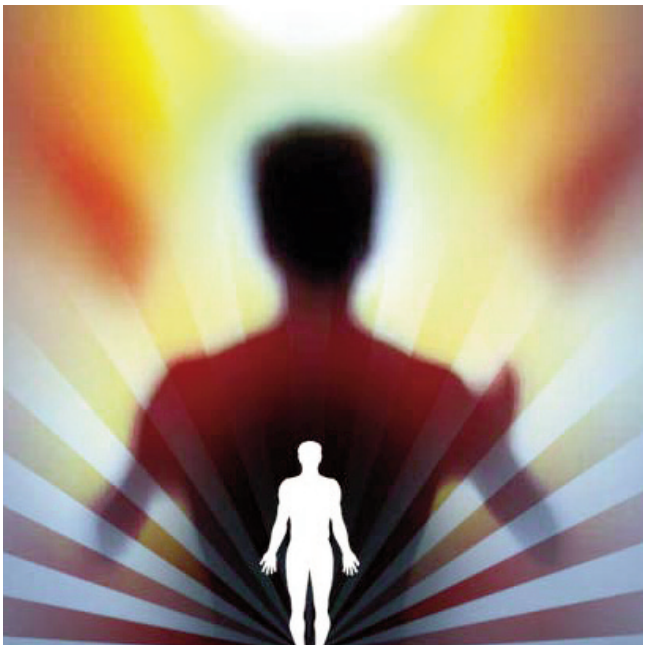

होगी जिसके बाद ईश्वर पुनः सृष्टि की रचना करेंगे और यह जन्म व मरण अथवा बन्धन व मोक्ष का चक्र अनन्त काल तक चलता रहेगा अर्थात इसका अन्त कभी नहीं होगा। अतः मृत्यु का कारण जन्म होता है, यह वेद, दर्शन, उपनिषद व गीता आदि ग्रन्थों से समझ में आ जाता है।

मनुष्य की आत्मा चेतन तत्व है। यह अनादि, अनन्त, अविनाशी, सूक्ष्म, अल्पज्ञ, ससीम, निराकार एवं एकदेशी है। यह सुख व दुःख का अनुभव करती है। सुख का मुख्य कारण मनुष्य के शुभ व श्रेष्ठ कर्म हुआ करते हैं और दुःख का कारण मनुष्य के पाप कर्म वा अशुभ कर्म हुआ करते हैं। शास्त्रों का अध्ययन, ऋषि-मुनियों व सच्चे ज्ञानियों की संगति से सुख व दुःख के कारण वा बन्धन-मोक्ष के सिद्धान्त को समझ लेने पर मनुष्य पाप करने से स्वयं को रोकता है। वह ईश्वरोपासना, अग्निहोत्र-यज्ञ एवं परोपकार आदि शुभ व पुण्य कर्मों को करता है जिससे उसे सुख प्राप्त होने सहित परजन्म में भी उत्तम मनुष्य योनि प्राप्त होती है। मनुष्य योनि जीवात्मा को मिलने वाले जन्म की सभी योनियों में उत्तम व श्रेष्ठ है। यह मोक्ष अर्थात स्वर्ग तथा दुःखरूपी नरक का द्वार भी है।

“ हमने यह एक मनुष्य के जीवन का संक्षिप्त वर्णन किया है। मनुष्य की मृत्यु क्यों होती है? यह प्रश्न प्रायः सभी के मन में उठता है। लोग इस प्रश्न को टाल जाते हैं और इस पर विचार करना निरर्थक माना जाता है। हमारे देश में ऋषि दयानन्द हुए जिन्होंने अपने घर में अपनी बड़ी बहिन व चाचा की मृत्यु देखी तो उन्हें वैराग्य हो गया था। मृत्यु के भय से वह इतने व्याकुल हुए थे कि मृत्यु की औषधि की तलाश करने के लिये वह अपनी आयु के 22 वें वर्ष में घर से चले गये और साधु, सन्तो, योगियों व विद्वानों की सगति कर ईश्वर के सच्चे स्वरूप और मृत्यु की औषधि की खोज करते रहे।

बीहड़ में स्त्री स्वाभिमान की जागरूकता

भारतीय समाज में आज भी बड़ी संख्या में महिलाएं पीरियड्स को लेकर कई मिथकों और संकोचों में अपना जीवन गुजार रही हैं। ह्मपीरियड्सह्न महिलाओं की जिंदगी से जुड़ा एक अहम विषय है, जिस पर खुलकर बात नहीं होती है। देश के बड़े शहरों में हालात जरूर थोड़े बदले हैं, लेकिन गांव और कस्बों में अभी भी ये चुप्पी का मुद्दा है, जिसे शर्म और संकोच की नजर से देखा जाता है। गांव की महिलाएं इस पर चर्चा न घर में कर पाती हैं और न ही अपनी किशोर बेटियों को इस बारे विस्तार से बता पाती हैं, जिस कारण साफ-सफाई के अभाव में गंभीर बीमारियों से संक्रमित होने का खतरा उनमें लगातार बना रहता है। स्वास्थ्य विभाग के तमाम जागरूकता अभियानों के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति जस की तस है। टीवी-अखबारों में सैनिटरी पैड्स के विज्ञापनों की गूंज गांवों तक तो है, परंतु उपयोग नही के बराबर है। आज भी ग्रामीण महिलाएं और किशोरियां के लिए घर के फटे-पुराने कपडे.ही पीरियड्स के लिए एकमात्र उपाय हैं, नतीजा उन्हें संक्रमण के रूप में झेलना पड़ता है। हालांकि अब इसमें धीरे धीरे बदलाव आ रहा है और ग्रामीण महिलाएं भी न केवल पैड्स का इस्तेमाल करने लगी हैं बल्कि ग्रामीण स्तर पर इसे तैयार भी किया जा रहा है।

ऐसी ही जागरूकता छत्तीसगढ़ के कांकेर जिला स्थित दुगूर्कोदल ब्लॉक मुख्यालय के करीब ग्राम खुटगांव में देखने को मिली है। जहां कुछ शिक्षित गृहिणी व नौकरीपेशा महिलाएं अपने क्षेत्र की ग्रामीण महिलाओं को पीरियड्स के दौरान कपड़े का उपयोग और उससे होने वाली समस्याओं को विगत कई सालों से देखती आ रही थीं, जिसके बाद उन्होंने स्वयं क्षेत्र में जागरूकता लाने की पहल की। इसके लिए उन्होंने शक्ति स्व-सहायता समूह का गठन कर सेनेट्री नैपकिन बनाने का काम शुरू किया। इस समूह में दस महिलाएं संगठित होकर गांव में ही स्त्री स्वाभिमान नाम से सैनिटरी पैड का निर्माण कर रही हैं, ताकि अपने क्षेत्र की लड़कियों और महिलाओं को पीरियड्स के दौरान सैनिटरी पैड्स उपयोग करने के लिए जागरूक कर सकें। केन्द्र सरकार के स्त्री स्वाभिमान योजना के तहत सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) के माध्यम से समूह ने स्वयं से पैसे एकत्रित कर मशीन और रॉ-मटेरियल खरीदा है। समूह की महिलाएं कामकाजी होने के कारण उन्होंने गांव व आस-पास की अन्य महिलाओं को रोजगार दिया है, जो रोजाना पैड बनाने का कार्य करती हैं। तैयार सैनिटरी पैड्स को समूह के सदस्य गांव व आस-पास की महिलाओं को सस्ते दामों पर उपलब्ध करवा रही हैं ताकि उन्हें महंगे दामों पर बाजार में मिलने वाले सैनिटरी पैड्स नहीं खरीदना पडे। पेशे से स्कूल शिक्षिका और समूह की सदस्या उतरा वस्त्रकार ने बताया कि शुरूआत में पैड बनाने के लिए हमें प्रशिक्षण दिया गया। एक सैनिटरी पैड को पूरी तरह तैयार करने में तकरीबन चार घंटे का समय लगता है, जिसमें सबसे पहले उसके रॉ-मटेरियल को मशीन की सहायता से काटकर, जेल पेपर व अलग-अलग शीट को गोंद की सहायता से चिपकाया जाता है, फिर हम उसे सूखने के लिए छोड़ देते हैं। पूरी तरह सूखने के बाद उसे मशीन के माध्यम से डिसइंफेक्शन किया जाता है, फिर अंत में रैपर में पैकिंग होती है। अपने पैड की गुणवत्ता पर बात करते हुए उन्होंने बताया कि बनाने के बाद सबसे पहले हमने स्वयं इसे उपयोग करके देखा है उसके बाद अब हम इसे दूसरी महिलाओं को उपयोग करने की सलाह दे रहे हैं।

शक्ति स्व-सहायता समूह की अध्यक्षा एवं गांव की सरंपच सगनी तुलावी कहती हैं कि इस कार्य के पीछे हमारा उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को सैनिटरी पैड उपयोग करने के लिए जागरूक करना है, ताकि उन्हें विभिन्न बिमारियों से सुरक्षित रखा जा सके। उन्होंने बताया कि उनके गांव में 70 परिवार हैं, आज सभी परिवारों की लड़कियां और महिलाएं सैनिटरी पैड्स का ही उपयोग करती हैं। इसके लिए वह समय-समय पर महिलाओं से मिलकर बातचीत भी करती रहती हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और समूह की सदस्या रीता वस्त्रकार बताती हैं कि जब वह इस क्षेत्र में रहने आई थी तो यहां की महिलाएं साफ-सफाई का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती थीं। माहवारी के दौरान गंदा कपड़ा ही उनके द्वारा उपयोग किया जाता था। ज्यादातर महिलाओं को पीरियड्स और इस दौरान रखने वाली साफ सफाई के बारे में उचित जानकारी भी नहीं थी। लेकिन समय के साथ अब इनमें थोड़ा बदलाव आ रहा है। यह सब देखकर ही हमारे मन में हमेशा से यह ख्याल रहा कि इन महिलाओं के लिए कुछ करना चाहिए। इस संबंध में दुगूर्कोदल क्षेत्र के ब्लॉक मेडिकल ऑफि सर मनोज किशोर ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा हर छह महीने में स्कूलों व अन्य जगहों पर जागरूकता शिविर लगाया जाता है, जहां महिलाओं को माहवारी और उनके स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियां दी जाती हैं।

“ऐसी ही जागरूकता छत्तीसगढ़ के कांकेर जिला स्थित दुगूर्कोदल ब्लॉक मुख्यालय के करीब ग्राम खुटगांव में देखने को मिली है। जहां कुछ शिक्षित गृहिणी व नौकरीपेशा महिलाएं अपने क्षेत्र की ग्रामीण महिलाओं को पीरियड्स के दौरान कपड़े का उपयोग और उससे होने वाली समस्याओं को विगत कई सालों से देखती आ रही थीं।

बाल अपराध की हिंसक होती प्रवृत्ति

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक छात्र कि हरकत ने समाज को स्तब्ध कर दिया। 14 साल के स्कूली छात्र ने अपने ही सहपाठी को इसलिए गोली मार दी कि स्कूल में बैठने को लेकर उसका और सहपाठी का आपस में झगड़ा हुआ था। इसका बदला लेने के लिए घटना के दूसरे दिन अपनी स्कूल बैग में चाचा कि लाइसेंसी पिस्तौल लेकर आए छात्र ने सहपाठी को गोली मार दिया। हालाँकि बाद में स्कूल स्टॉप की तत्परता से उसकी गिरफ्तारी हो गई। लेकिन समाज में बढ़ते बाल अपराध के मनोविज्ञान ने हमें चौका दिया है।

सामाजिक बदलाव और तकनीकी विकास का मानव जीवन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा है। सीखने और समझने की क्षमता भी अधिक बढ़ी है। जिसका नतीजा है अपराध का ग्राफ भी तेजी से बढ़ा है। भारत में बाल अपराध के आंकड़ों की गति भी हाल के सालों में कई गुना बढ़ी है। जिस अपराध की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं उस कार्य को नाबालिक किशोरों ने कर समाज और व्यवस्था को सोचने पर मजबूर कर दिया है।

निर्भया कांड में भी एक बाल अपराधी की भूमिका अहम रही थीं। बाद में जुवेनाइल अदालत से वह छूट गया था। संयुक्तराष्ट्र 18 साल के कम उम्र के किशोरों को नाबालिग मानता है। जबकि भारत समेत दुनिया भर में बढ़ते बाल अपराध की घटना ने सोचने पर मजबूर किया है। जिसकी वजह है कि दुनिया के कई देशों ने नाबालिग की उम्र घटा दिया है। कई देशों में बाल अपराध की सजा बड़ों जैसी है। भारतवर्ष में किसी बच्चे को बाल अपराधी घोषित करने की उम्र 14 वर्ष तथा अधिकतम 18 वर्ष है। इसी तरह मिश्र में 7 वर्ष से 15 वर्ष, ब्रिटेन में 11 से 16 वर्ष तथा ईरान में 11 से 18 वर्ष है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार हाल के सालों में बाल अपराध की घटनाएँ तेजी से बढ़ी हैं।

समाज में इस तरह की घटनाएँ हमारे लिए चिंता का विषय हैं। इसे हम नजरंदाज नहीं कर सकते हैं। अमेरिका जैसे देश में इस तरह की अनगिनत घटनाएँ हैं, लेकिन भारतीय परिप्रेक्ष्य में यह बड़ी बात है। यह घटना साफ तौर पर इंगित करती है हम किस सामजिक बदलाव की तरफ बढ़ रहें हैं। हम असहिष्णु समाज का निर्माण करना चाहते हैं। आने वाली पीढ़ी में संवाद, संयम और सहनशीलता, धैर्य, क्षमा का अभाव दिखने लगा है। 14 साल की उम्र भरतीय समाज में विशेष रुप से सीखने की होती उस उम्र के किशोर प्रयोगवादी कहाँ से हो गए हैं। हम समाज और आने वाली पीढ़ी को कौन सा महौल देना चाहते हैं। 14 साल की उम्र का नाबालिग किशोर पिस्तौल में गोली भरना और ट्रिगर दबाना कैसे सिख गया ? यह सब तकनीकी विकास और पारिवारिक महौल पर बहुत कुछ निर्भर करता है।

संवेदनशील आग्नेयास्त्र बच्चों कि पहुँच तक घर में कैसे सुलभ हो गए। इस तरह के शस्त्र क्या बच्चों की पहुँच से छुपा कर रखने की वस्तु नहीं हैं। फिर इस शस्त्र को घर में इतनी गैर जिम्मेदारी से क्यों रखा गया था। नाबालिग किशोर उस आग्नेयास्त्र तक कैसे पहुँच गया। छात्र के बैग में टिफिन रखते वक्त क्या माँ ने उसका स्कूल बैग चेक नहीं किया। जिस चाचा की पिस्तौल लेकर वह किशोर स्कूल गया था वह सेना में कार्यरत बताया गया है। अवकाश पर घर आया था, फिर क्या यह उनकी खुद की जिम्मेदारी नहीं बनती थीं कि इस तरह के शस्त्रों को बच्चों की पहुँच से दूर रखा जाय।

निश्चित रुप से हम समाज में जिस महौल को पैदा कर रहें हैं वह हमारे लिए बेहद दुखदायी है। इंसान खुद को टाइम मशीन बना लिया है। वह बच्चों, परिवार, समाज और समूह पर अपना ध्यान ही केंद्रित नहीं कर पा रह है। अगर थोड़ी सी सतर्कता बरती जाती तो सम्भवतः इस तरह के हादसे को टाला जा सकता था। अगर उस शस्त्र को बच्चों की पहुँच से सुरक्षित स्थान पर किसी लाकर में रखा जाता तो इस तरह की घटना नहीं होती। इस घटना से सबक लेते हुए स्कूल प्रबंधन

“ नर्भया कांड में भी एक बाल अपराधी की भूमिका अहम रही थीं। बाद में जुवेनाइल अदालत से वह छूट गया था। संयुक्तराष्ट्र 18 साल के कम उम्र के किशोरों को नाबालिग मानता है। जबकि भारत समेत दुनिया भर में बढ़ते बाल अपराध की घटना ने सोचने पर मजबूर किया है। जिसकी वजह है कि दुनिया के कई देशों ने नाबालिग की उम्र घटा दिया है। कई देशों में बाल अपराध की सजा बड़ों जैसी है।

को भी चाहिए की बच्चे की स्कूल गेट पर हर छात्र की तलाशी ली जाय, क्योंकि अपराध किसी चेहरे नहीं लिखा है। स्कूलों में मेटल डिटेक्टर भी लगाए जाने चाहिए।

हमने मासूम बच्चों पर स्कूली किताबों का बोझ अधिक लाद दिया है। पढ़ाई और प्रतिस्पर्धा की होड़ में किशोरवय अल्हड़ता को छीन लिया है। आधुनिक जीवन शैली ने सामाजिक परिवेश को जरूरत से अधिक बदल दिया है। हम प्रतिस्पर्धी जीवन में बच्चों और परिवार पर समय देना बंद कर दिया है। जिसकी वजह से बच्चों में एकांकीपन बढ़ रहा है। बच्चों में चिड़चिड़ापन आता है। परिवार नाम की संस्था और नैतिकमूल्य की उनमें समझ नहीं पैदा होती। उन्हें समाज, परिवार जैसे संस्कार ही नहीं मिल पाते। शहरों में माँ- बाप के कामकाजी होने से यह समस्या और बड़ी और गहरी बन जाती है। क्योंकि इस तरह के परिवार में बच्चों के लिए समय ही नहीं बचता है। स्कूल से आने के बाद बच्चों पर ट्यूशन और होमवर्क का बोझ बढ़ रहा है। माँ- बाप बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं। दादा- दादी का तो वक्त खत्म हो चला है, नहीं तो कम से कम शिक्षाप्रद कहानियों के माध्यम से बच्चों का मार्गदर्शन होता था।

मनोचिकित्सक मानते हैं कि किशोरों में बढ़ती हिंसक प्रवृत्ति के पीछे अभिभावकों भी हैं। क्योंकि बच्चों पर वे उचित ध्यान नहीं दे पाते हैं। दूसरी वजह कई परिवारों में माता-पिता में आपसी संबंध सही न होने से बच्चों को समुचित समय नहीं मिल पाता है। किशोरों द्वारा हिंसक वीडियो गेम खेलने से भी उनके मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जिसकी वजह से उनमें हिंसक प्रवृति बढ़ती है। किशोरों में सांवेगिक नियंत्रण की कमी होती है और वे फैसले अपने संवेग के आधार पर लेते हैं। डा.तिवारी के अनुसार किशोरवय के साथ हम क्रोध के बजाय मित्रवत व्यवहार करें। उनके साथ साथ खेलें और बातचीत करें। उन्हें अधिक समय तक मोबाइल एवं टेलीविजन के साथ अकेले न छोड़े। बच्चों को अकेले बहुत अधिक समय व्यतीत न करने दें। बच्चे के व्यवहार में किसी भी तरह के असामान्य परिवर्तन होने पर उसके कारणों को जानने का प्रयास करें और संभव हो तो मनोवैज्ञानिक परामर्श लें।

हालाँकि कोरोना काल में स्थितियां बदली हैं। वर्क फ्रॉम होम और स्कूली की तालाबंदी होने से अभिभावकों ने बच्चों को काफी वक्त दिया है। कोविड- 19 से वैश्विक अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका भले लगा हो, लेकिन परिवार नाम की संस्था का मतलब लोगों के समझ में आ गया है। इसके पूर्व शहरी जीवन में बच्चों को बड़ी मुश्किल से रविवार उपलब्ध हो पाता था। जिसमें माँ- बाप बच्चों के लिए समय निकाल पाते थे, लेकिन कोरोना परिवार नामक संस्था को मजबूत किया है। बुलंदशहर की घटना हमारे लिए बड़ा सबक है। हमें बच्चों के लिए समय निकालना होगा। किताबी ज्ञान के इतर हमें पारिवारिक और सामाजिक शिक्षा भी बच्चों देनी होगी।

किशोर उम्र बेहद नाजुक होती है यह अपनी दिशा तेजी से तय करती है। आपका बच्चा स्कूल और कालेज जा रहा है तो वहाँ क्या कर रहा है उसकी निगरानी भी आपको करनी है। बच्चे से मित्रवत व्यवहार रखें। बच्चों की स्कूल बैग टिफिन के बहाने देखें। स्कूल बैग में अगर कोई भी ऐसी वस्तु तो नहीं रखी है जिससे उसके बुरे व्यवहार का पता चलता हो। बच्चों को समय दें और शाम को स्कूली दिनचर्या के बारे में जानकारी लें। स्कूल और ट्यूशन शिक्षक से भी सम्पर्क बनाएं रखें। इन सब बातों से आप उसकी गतिविधियों पर नजर रख कर माँ- बाप के रुप में एक नैतिक शिक्षक आप खुद बन सकते हैं और बच्चों में बढ़ते अपराध की प्रविति को नियंत्रित कर सकते हैं।

“मनोचिकित्सक मानते हैं कि किशोरों में बढ़ती हिंसक प्रवृत्ति के पीछे अभिभावकों भी हैं। क्योंकि बच्चों पर वे उचित ध्यान नहीं दे पाते हैं। दूसरी वजह कई परिवारों में माता-पिता में आपसी संबंध सही न होने से बच्चों को समुचित समय नहीं मिल पाता है। किशोरों द्वारा हिंसक वीडियो गेम खेलने से भी उनके मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जिसकी वजह से उनमें हिंसक प्रवृति बढ़ती है।

महामारी के सबक को सीख बनाना होगा

भारत में कोरोना संक्रमण के कहर को झेल रही जिन्दगी बड़े कठोर दौर के बाद अब सामान्य होने की कगार पर दिखाई दे रही है। वैज्ञानिकों की नेशनल सुपर मॉडल समिति ने लगभग चार माह पहले ही दावा किया था कि देश में कोरोना का चरम सितम्बर में ही आ चुका था और फरवरी 2021 में कोरोना का वायरस फ्लैट हो जाएगा। ऐसा ही होते हुए दिख रहा है। इस महामारी से ध्वस्त हुई अर्थ-व्यवस्था को पटरी पर लाने एवं भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने की दृष्टि से बजट-2021 में अनेक प्रावधान किये गये हैं। कोरोना महामारी ने आर्थिक पीड़ाओं के साथ-साथ व्यक्तिगत, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरण के सबक दिये हैं। उन्नत भारत का निर्माण करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए हमें इन सबक को सीख बनाना होगा।

सबसे जरूरी सीख यही है कि हमें अब प्रकृति के निर्मम शोषण पर नियंत्रण करना होगा। जलवायु संकट, लगातार पिघलते ग्लेशियर, अनियमित मौसम, बढ़ता प्रदूषण, एवं वायु, भूमि व पहाड़ों पर असीमित दोहन ने देश और दुनिया को एक खतरनाक मुहाने पर ला खड़ा कर दिया है। ये सभी गंभीर संकट में हैं। कोरोना के संक्रमण दौर में यह देखना अद्भुत एवं सुखद अनुभव रहा कि लॉकडाउन ने प्रकृति को फिर से संवारने एवं स्वच्छ करने का काम किया है। इस अवधि में हमने कई दशकों के बाद फिर से नीला आसमान देखा, नदियों-तालाबों का जल स्वच्छ एवं साफ-सुथरा देखा, प्रदूषण का स्तर नीचे गिरा और जीवों, पक्षियों व कीटों की कई प्रजातियों को नवजीवन मिला। अब हमें लगातार प्रयास करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि ये सकारात्मक बदलाव निरंतर कायम रहें।

मनुष्य के लोभ एवं संवेदनहीनता त्रासदी की हद तक बढ़ते जाने के ही परिणाम हैं, जो वन्यजीवों, पक्षियों, प्रकृति एवं पर्यावरण के असंतुलन एवं विनाश के बड़े सबब बने हैं। मनुष्य के कार्य-व्यवहार से ऐसा मालूम होने लगा है, जैसे इस धरती पर जितना अधिकार उसका है, उतना किसी ओर का नहीं-न वृक्षों का, न पशुओं का, न पक्षियों का, न नदियों-पहाड़ों-तालाबों का। दरअसल हमारे यहां बड़े जीवों के संरक्षण पर तो ध्यान दिया जाता है, पर पक्षियों के संरक्षण पर उतना नहीं। कोरोना संकटकाल में हम प्रकृति के नजदीक गये, पक्षियों के साथ कुछ पल बिताये। जीवन के अनेकानेक सुख, संतोष एवं रोमांच में से एक यह भी है कि हम कुछ समय पक्षियों के साथ बिताने में लगाए, भविष्य में भी हम ऐसा क्यों नहीं कर पाएंगे? क्यों हमारी सोच एवं जीवनशैली का प्रकृति-प्रेम कोरोना संकट के समय ही सामने आया? मनुष्य के हाथों से रचे कृत्रिम संसार की परिधि में प्रकृति, पर्यावरण, वन्यजीव-जंगल एवं पक्षियों का कलरव एवं जीवन-ऊर्जा का लगातार खत्म होते जाना जीवन से मृत्यु की ओर बढ़ने का संकेत है। यह बात कोरोना महामारी ने हमें भली-भांति समझायी है, इस समझ को सीख बनाना होगा।

वृक्षारोपण, जैविक खेती को बढ़ाकर तथा माइक्रोवेव प्रदूषण पर अंकुश लगाकर पक्षियों को विलुप्त होने से बचाया जा सकता है। अब भी यदि हम जैव विविधता को बचाने का सामूहिक प्रयास न करें, तो बहुत देर हो जाएगी। लॉकडाउन के दौरान वन्यजीवों, पक्षियों, एवं प्रकृति के जीवन में भी अनेक प्रकार के सकारात्मक बदलाव देखने को मिले, जो मानव जीवन के लिये बहुत उपयोगी हैं। लेकिन क्या इन बदलावों को आगे भी जारी रखने के लिये हम अपनी जीवनशैली में बदलाव के लिये तैयार है?

कोरोना महामारी ने हमें पारिवारिक रिश्तों के महत्व को समझाया है। हमने इस दौरान रिश्तों की अहमियत को गहराई से समझा। लॉकडाउन ने रिश्तों को फिर से बनाने और विशेषकर बुजुर्गों के साथ स्नेह व सहयोग बढ़ाने को प्रेरित किया है। भले ही लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा की बढ़ी घटनाएं परेशान कर रही हैं। महिलाओं, बच्चों या बुजुर्गों के प्रति किसी भी तरह का अनुचित व्यवहार अस्वीकार्य है। यह भारतीय संस्कृति के सिद्धांतों के विपरीत भी है। कोविड-19 संकट ने हमें निजी जीवनशैली को भी इस कदर बदलने के लिए मजबूर किया है कि विलासिता की वस्तुओं पर अनावश्यक खर्च कम से कम हो। हममें से

> **“ कोरोना के संक्रमण दौर में यह देखना अद्भुत एवं सुखद अनुभव रहा कि लॉकडाउन ने प्रकृति को फिर से संवारने एवं स्वच्छ करने का काम किया है। इस अवधि में हमने कई दशकों के बाद फिर से नीला आसमान देखा, नदियों-तालाबों का जल स्वच्छ एवं साफ-सुथरा देखा, प्रदूषण का स्तर नीचे गिरा और जीवों, पक्षियों व कीटों की कई प्रजातियों को नवजीवन मिला।**

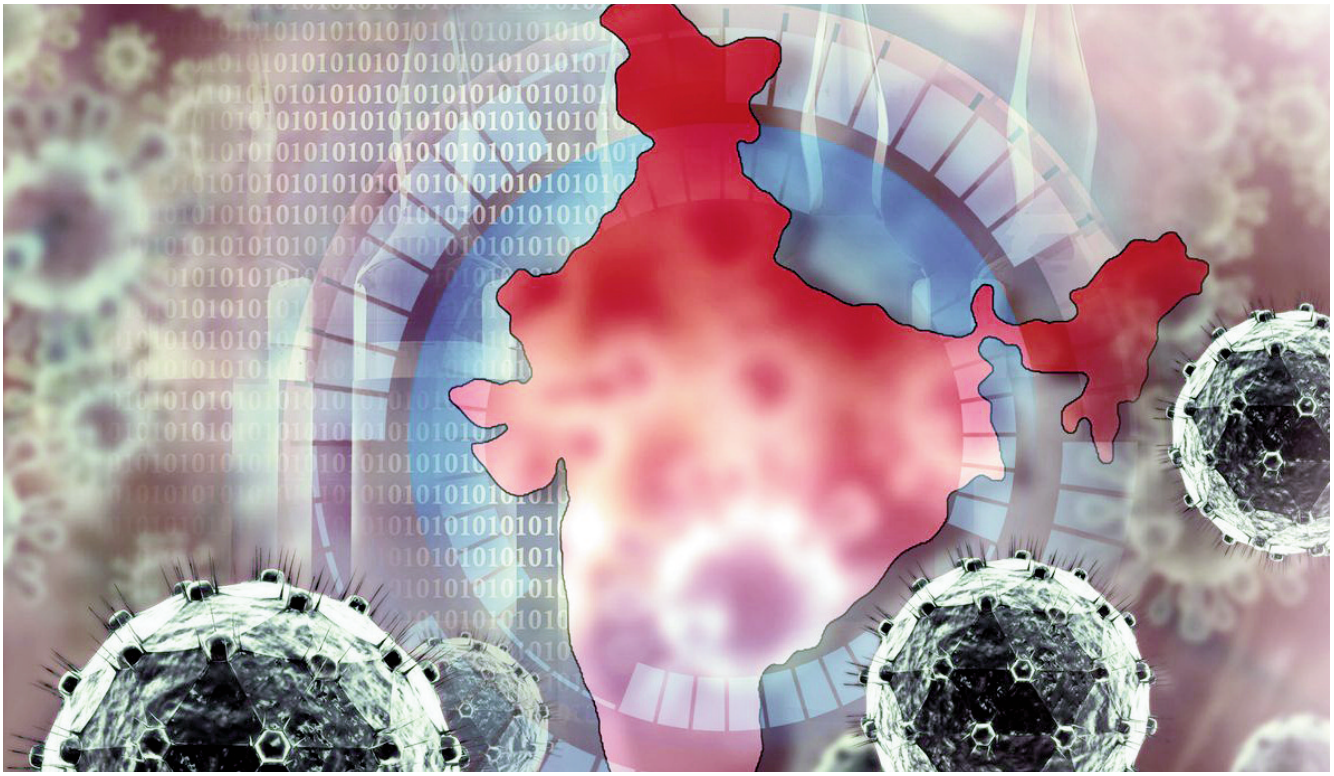

कुछ बेशक काफी ज्यादा खर्च कर सकने में सक्षम हैं, लेकिन इससे अनावश्यक खर्च का औचित्य साबित नहीं हो जाता। बाकायदा कानून द्वारा सगाई और विवाह समारोहों में पैसों का होने वाला अश्लील एवं अतिश्योक्तिपूर्ण प्रदर्शन रोका जाना चाहिए, और अनगिनत मेहमानों का आना नियंत्रित किया जाना चाहिए। ऐसे आयोजनों में अधिकतम 50 अतिथि शामिल होने की कोरोना सीख को आगे भी जारी रखा जाना चाहिए। ऐसे देश में, जहां लाखों लोगों को दिन भर में संतुलित भोजन तक न मिल पाता हो, वहां चंद लोगों पर बेहिसाब पैसे खर्च करना किसी अपराध से कम नहीं है।

हम मनुष्य जीवन की मूल्यवत्ता और उसके तात्पर्य को समझें। वह केवल पदार्थ भोग और सुविधा भोग के लिए नहीं बल्कि संयममय कर्म करते रहने के लिये है। मनुष्य जन्म तो किन्हीं महान उद्देश्यों के लिए हुआ है। हम अपना मूल्य कभी कम न होने दें। प्रयत्न यही रहे कि मूल्य बढ़ता जाए। लेकिन यह बात सदा ध्यान में रहे कि मूल्य जुड़ा हुआ है जीवनमूल्यों के साथ। अच्छी सोच एवं अच्छे उद्देश्यों के साथ। हायमैन रिकओवर ने कहा कि अच्छे विचारों को स्वतः ही नहीं अपनाया जाता है। उन्हें पराक्रमयुक्त धैर्य के साथ व्यवहार में लाया जाना चाहिए।

आत्मनिर्भर भारत एवं सशक्त भारत के निर्माण के लिये हमें अपनी विकास योजनाओं को नए सिरे से गढ़ना होगा, जिनमें स्वास्थ्य और शिक्षा के मद में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का एक निश्चित प्रतिशत आवंटन अनिवार्य होना चाहिए। इस दृष्टि से बजट-2021 में ध्यान दिया गया है, क्योंकि अगर भारत इन क्षेत्रों को मजबूत नहीं करता है, तो वैश्विक ताकत बनने की सारी उम्मीदें बिखर जाएंगी। हमारी बहत्तर वर्ष की राष्ट्रीय विफलता रही है कि आजादी के बाद से अब तक हमने इन पर इस कदर ध्यान नहीं दिया है। स्वास्थ्य की मद में दूरगामी सोच के साथ जो प्रावधान किये गये हैं, उनसे निश्चित ही भविष्य में कोरोना जैसी महामारियों से लड़ने में हम अधिक सक्षम हो सकेंगे।

कोरोना संकट से जुड़ी मुश्किलों से पार पाने के लिए विश्व स्तर पर एक दूसरे के प्रति सहयोग, संवेदना एवं समभाव अनिवार्य है। हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अनेक देशों को राहत सामग्री, दवाओं व व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों (पीपीई किट) भेजी, सहयोग किया। भारत ने वैक्सीन भी तत्परता से तैयार की और अनेक देशों को उपलब्ध करा रहा है। ह्यवसुधैव कुटुंबकमह्ल की हमारी प्राचीन अवधारणा कोरोना के कारण एक बार फिर बलवती हुई। कोई भी राष्ट्र, फिर चाहे वह कितना भी महान एवं सक्षम क्यों न हो, कोरोना जैसे संकटों से पार पाने के लिये उसे भी सहयोग अपेक्षित होता है। यह बात हमने कोरोना महामारी के दौरान देखी, अनेक शक्तिसम्पन्न देश इस संकट से लड़ने में अक्षम पाये गये। कोरोना महामारी ने एक बड़ा सबक दिया है कि मानव जाति अंततः एक साथ ही डूबेगी या फिर उबरेगी। हमारे पास दुनिया के कुछ सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक, आध्यात्मिक महामनीषी और शोधकर्ता हैं, और भारत की कई प्रयोगशालाएं कोरोना वायरस के खिलाफ टीका बनाने के लिए दिन-रात काम करके नया कीर्तिमान स्थापित किया है।

कोरोना महामारी ने हमारे जीने के तौर-तरीके को अस्तव्यस्त कर दिया है। हमारे द्वारा यह कामना करना अस्वाभाविक नहीं थी कि हमारे नष्ट हो गये आदर्श एवं संतुलित जीवन के गौरव को हम फिर से प्राप्त करेंगे और फिर एक बार हमारी जीवन-शैली में पूर्ण भारतीयता का सामंजस्य एवं संतुलन स्थापित होगा। किंतु कोरोना के जटिल ग्यारह माह के बीतने पर हालात का जायजा लें, तो हमारे सामाजिक, पारिवारिक और वैयक्तिक जीवन में जीवन-मूल्य एवं कार्यक्षमताएं को संगठित करने के लिये हमें व्यापक प्रयत्न करने होंगे। हर व्यक्ति जीवन को उन्नत बनाना चाहता है, लेकिन उन्नति उस दिन अवरुद्ध होनी शुरू हो जाती है जिस दिन हम अपनी कमियों एवं त्रुटियों पर ध्यान देना बन्द कर देते हैं। यह स्थिति आदमी से ऐसे-ऐसे काम करवाती है, जो आगे चलकर उसी के लिए हानिकारक सिद्ध होते हैं। रही-सही कसर पूरी कर देती है हमारी त्रुटिपूर्ण जीवनशैली। असंतुलित जीवन है तो आदमी सकारात्मक चिंतन कर नहीं सकता। महामात्य चाणक्य को राजनीति का द्रोणाचार्य माना जाता है। उनका दिया हुआ सूत्र है- शासन को इन्द्रियजयी होना चाहिए। बात शासन से पहले व्यक्ति की है। व्यक्ति का जीवन ही राष्ट्र का निर्माण है। इसलिये प्रयास वहीं से शुरू होने चाहिए।

“हम मनुष्य जीवन की मूल्यवत्ता और उसके तात्पर्य को समझें। वह केवल पदार्थ भोग और सुविधा भोग के लिए नहीं बल्कि संयममय कर्म करते रहने के लिये है। मनुष्य जन्म तो किन्हीं महान उद्देश्यों के लिए हुआ है। हम अपना मूल्य कभी कम न होने दें। प्रयत्न यही रहे कि मूल्य बढ़ता जाए। लेकिन यह बात सदा ध्यान में रहे कि मूल्य जुड़ा हुआ है जीवनमूल्यों के साथ। अच्छी सोच एवं अच्छे उद्देश्यों के साथ।

गंगा से खिलवाड़ का दुष्फल

गंगा की अविरलता-निर्मलता के समक्ष हम नित नई चुनौतियां पेश करने में लगे हैं। अविरलता-निर्मलता के नाम पर खुद को धोखा देने में लगे हैं। घाट विकास, तट विकास, तट पर औषधि उद्यान, सतही सफाई, खुले में शौच मुक्ति के लिए गंगा ग्रामों में बने शौच गड्ढे-खुद को धोखा देने जैसे ही काम हैं। अधिक उत्पादन के लिए रासायनिक उर्वरक, खरपतवारनाशक व कीटनाशाकों का बेलगाम प्रयोग भी इसी श्रेणी में आता है। तकलीफदेह तथ्य यह है कि ऐसा करते हुए हम उन कहानी, शोध, निष्कष व आंखों देखी तकलीफों की लगातार अनदेखी कर रहे हैं, जो प्रमाण हैं कि चुनौती तो हम खुद अपने लिए पेश कर रहे हैं।

पत्रकार अभय मिश्र ने वेंटिलेटर पर ज़िन्दा एक महान नदी की कहानी लिखी है। वह महान नदी, हमारी गंगा है। हकीकत में माटी मानुष चून उपन्यास, गंगा के वेंटिलेटर पर जाने की कहानी नहीं है; यदि भारत की नदियों की अनदेखी हुई तो 2075 आते-आते, यह पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के हम इंसानों के वेंटिलेटर पर आश्रित हो जाने की कहानी होगी। नेशनल एकेडमी ऑफ साइन्सेस जर्नल, अमेरिका की ताजा रिपोर्ट भी यही कह रही है। जिस रफ्तार से समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है, इस सदी के अंत तक गंगा, मेघना और ब्रपुत्र पर समुद्र का जल स्तर 1.4 मीटर बढ़ जायेगी। इससे एक-तिहाई बांग्ला देश और पूर्वी भारत का एक बड़ा हिस्सा स्थाई बाढ़ व दलदली क्षेत्र के रूप में तब्दील हो जाएगा। परिणामस्वरूप, इस इलाके में बसी करीब 20 करोड़ की आबादी वेंटिलेटर पर होगी।

विज्ञान पर्यावरण केन्द्र से लेकर स्वयं सरकार के केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तक के अब तक की रिपोतार्ज गंगा गुणवत्ता की बेहतरी की खबर नहीं दे रहे। गंगा बेहतरी के नाम पर उत्तर प्रदेश की शासकीय गंगा यात्रा भले ही जारी हो; प्रयागराज में माघ मेले के इस समय में भी गंगा-यमुना में जा रहे नाले के सोशल मीडिया पर जारी ताजा वीडियो के दृश्य कुछ और ही कह रहे हैं। गंगा, डुबकी लगा रहे लाखों लोगों को पाप मुक्त करके भेज रही है या नई बीमारियां देकर ? इसका एक उत्तर स्वयं प्रधानमंत्री जी के प्रतिनिधित्व वाले अस्सी नाले और वरुणा नदी से सीधे रुबरु होकर पाया जा सकता है। दूसरा उत्तर, डॉक्टर सूरज द्वारा गत दो वर्षों के दौरान गंगातटीय 2500 मरीजों पर किए गए ताजा शोध ने पेश किया है। डॉक्टर सूरज, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के सर सुन्दरलाल अस्पताल में न्यूरोलॉजी विभाग के शोधार्थी हैं।

शोध कहता है कि, प्रयागराज से लेकर मिजार्पुर, भदोही, बनारस, चंदोली, बलिया, बक्सर तक की 300 किलोमीटर लम्बी गंगा तटवर्ती पट्टी में गंजेटिक पर्किसन और गंजेटिक डिमेंशिया के रोगी बढे.हैं। मोटर नूरान नामक जो बीमारी, इस पट्टी के लोगों को तेजी से अपना शिकार बना रही है, उसका एक कारण गंगा में मौजूद धात्विक प्रदूषण है।

यह बीमारी अंगों में कसाव के साथ फड़फड़ाहट जैसे लक्षण लेकर आती है। खेती में प्रयोग होने वाले इंडोसल्फान ऑग्नोफास्फोरस, डीडीटी, लिन्डेन, एन्ड्रिन जैसे रसायनों के रिसकर गंगा में मिलने से इन इलाकों में पेट व पित्ताश्य की थैली के कैंसर रोगी बढे.हैं। शोधकर्ता आशंकित है कि गंगा प्रदूषण, अनुवांशिक दुष्प्रभाव भी डाल सकता है। इसके लिए फिलहाल, गंगा के जलीय जीवों पर अनुवांशिक प्रभावों का अध्ययन भी शुरू किया गया है। बावजूद इसके हमारे आत्मघाती कदम पर निगाह डालिए कि रिवर फ्रंट के नाम पर हमने गोमती नदी के साथ धोखा किया। उत्तर प्रदेश के पिछले शासनकाल में हिंडन की नदी भूमि पर कब्जे की एक योजना चुपके-चुपके बनाई गई। गोमती व हिंडन, क्रमशः गंगा व यमुना की सहायक धारा है।

“शोध कहता है कि, प्रयागराज से लेकर मिजार्पुर, भदोही, बनारस, चंदोली, बलिया, बक्सर तक की 300 किलोमीटर लम्बी गंगा तटवर्ती पट्टी में गंजेटिक पर्किसन और गंजेटिक डिमेंशिया के रोगी बढे.हैं। मोटर नूरान नामक जो बीमारी, इस पट्टी के लोगों को तेजी से अपना शिकार बना रही है, उसका एक कारण गंगा में मौजूद धात्विक प्रदूषण है। यह बीमारी अंगों में कसाव के साथ फड़फड़ाहट जैसे लक्षण लेकर आती है।

कोराना काल में याद आती हैं बच्चों की शरारतें

अपने स्टूडेंस की एक झलक पाने को बेताब हुई शिक्षिका

कोविड-19 के कारण पिछले लंबे समय से अध्यापक या तो घर बैठे हैं और अगर स्कूल जा भी रहे हैं तो सिर्फ स्टाफ से संबंधित काम निपटाकर घर लौट आते हैं। ऐसे में वे गत लगभग छह माह से बच्चों से रू-ब-रू होकर स्कूल में कक्षा नहीं ले पा रहे हैं। भले ही ऑनलाइन शिक्षण कार्य चल रहा है लेकिन क्लास रूम में अध्यापक बच्चों को जिन शरारतों के लिए डांटा करके थे और जिनसे अध्यापक परेशान भी होते थे बच्चों की वही शरारतें अब अध्यापकों को सताने लगी है। इतना ही नहीं कोरोना के कारण घर पर ही रहने के कारण अध्यापकों का सुबह जल्दी उठकर समय पर तैयार होने का रुटीन भी गड़बड़ा चुका है। इसके चलते अध्यापक वर्ग बड़े स्तर पर फिर से बच्चों से स्कूल में रू-ब-रू होने के लिए आतुर हैं।

मगर, वर्तमान में जिस तरह से जिले सहित प्रदेश में महामारी का प्रकोप बढ़ रहा है, उससे निकट भविष्य में ऐसा होना संभव नहीं दिख रहा है। ऐसे में अध्यापकों को ऑनलाइन ही बच्चों को पढ़ाकर अपने को संतुष्ट करना पड़ रहा है, जबकि वे बच्चों से आमने-सामने मिलने को आतुर हैं। इस महामारी ने स्वच्छंद आसमान में उड़ने वाले बच्चों के तो जैसे पंख ही छीन लिए।

चहारदीवारी रूपी पिजड़े में कैद चकहते बच्चों का जीवन कैदी की तरह गुजर रहा है। बच्चे व शिक्षक हर दिन अपने स्कूल को मिस कर रहे हैं। अपनी टीचर को याद कर हर दिन रोते हैं बच्चे। टीचर भी हर पल उन्हें मिस करते हैं। खासकर उन बच्चों को जो अपनी पढ़ाई और शैतानियों की वजह से टीचर के एकदम नजदीक रहते थे। उन्हें डांटना और दुलारना दोनों ही टीचर को याद आ रहे हैं।

घंटी की आवाज भी बना स्वप्न

अध्यापिका साधना सिंह का कहना है कि कोरोना कहर से प्रभावित सभी का जीवन उस शून्य की तरह हो गया है। जिसमें उम्मीद की किरण की प्रतीक्षा समाज का हर व्यक्ति कर रहा है कि फिर वही दिन आएंगे। लॉकडाउन से पहले रोजाना स्कूल जाने के लिए कुछ नया पहनना आदि अब अलमारी का श्रृंगार बन कर रह गए है। सहेलियों संग हंसना, गाना मुस्कराना बहुत याद आता है। प्रिसिपल का डांटना, घंटी की आवाज से अपनी कक्षा में बच्चों को पढ़ाने दौड़ना आदि एक स्वप्न बनकर रह गया है।

दोस्ताना माहौल की कमी खल रही

साधना सिंह का कहना है कि कोविड -19 के कारण सभी अध्यापक घर से ही बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं। मगर, स्कूल के शिक्षक और विद्यार्थी दोस्ताना माहौल मिस कर रहे हैं। पढ़ाई के साथ-साथ बच्चों के साथ हंसना, गेम खेलने का एक अलग ही मजा होता था। जो कोरोना महामारी के कारण अब सिर्फ याद ही बनता जा रहा है।

जिंदगी का तरीका ही बदल गया

अध्यापिका साधना सिंह का कहना है कि आज लगभग छह माह हो गए हैं कोरोना तथा लॉकडाउन का दौर चल रहा है। ऐसे लगता है जैसे जिदगी जीने का ढंग ही बदल गया हो। इन दिनों में यह सब क्रियाएं तथा पढ़ाई जो अब एक साधन चला रहा है वह है मोबाइल फोन। खैर पहले जैसा तो अब कुछ नहीं मोबाइल फोन ने विद्यार्थी तथा अध्यापक को इस मुश्किल घड़ी में जोड़कर जरूर रखा है। आस है कि कोरोना काल जल्द खत्म होगा और अध्यापक बच्चों के साथ मिलकर कक्षा के माहौल को महकाएंगे।

बच्चों की नादानियां आती हैं याद

शिक्षिका के अनुसार हर समय स्कूल के बच्चों की ही याद आती है। उनके साथ स्कूल में सात घंटे बिताते थे। स्कूल लगने से पहले ही सभी स्कूल पहुंच जाते थे। बच्चों की छोटी-छोटी बातों पर कितना हम मुस्कुराते थे। उनकी नादानियों पर कितना उनको समझाते थे। हमारा हर त्योहार स्कूल में बच्चों के साथ होता था। दुआ करती हूं कि यह दौर जल्दी से खत्म हो और स्कूल में कक्षा में बच्चों से मेरी मुलाकात हो।

एक दूसरे से मिल भाव विभोर हुए गुरु-शिष्य

अपनी टीचर से एक छोटी सी मुलाकात के लिए बच्चे उतारु हो गए थे और टीचर भी उनसे मिलने के लिए दिनभर की लंबी थकान के बावजूद साधन न होते हुए भी किसी तरह अपने स्टूडेंस से मिलने पहुंचीं। अपनी टीचर को देख बच्चे उनसे लिपट गए। टीचर ने उन्हें बहुत प्यार किया और कई पुरानी यादों को साझा किया। टीचर ने बच्चों को कोरोना से सेफ रहने के टिप्स दिए और उनकी उज्जवल भविष्य की कामना की।

> “अध्यापिका साधना सिंह का कहना है कि कोरोना कहर से प्रभावित सभी का जीवन उस शून्य की तरह हो गया है। जिसमें उम्मीद की किरण की प्रतीक्षा समाज का हर व्यक्ति कर रहा है कि फिर वही दिन आएंगे। लॉकडाउन से पहले रोजाना स्कूल जाने के लिए कुछ नया पहनना आदि अब अलमारी का श्रृंगार बन कर रह गए है। सहेलियों संग हंसना, गाना मुस्कराना बहुत याद आता है।

दीपक मिश्रा

ज्योतिष साधक

9334096060

9717857012

मेष गुरु की कृपा से भाग्य की बृद्धि होगी।कर्म स्थान का शनि मेहनत के बाद ही सफलता देगा।शनिबार की संध्या में लड्डू गरीबों में बांटे।सेहत का ध्यान रखें।भगवान श्री सूर्यनारायण को अर्ध्य प्रदान करें। शुभ अंक 1 और शुभ रंग लाल है।

बृषभ मन खिन्न रहेगा।बहुत मेहनत के बाद सफलता मिलेगी।जीवन में आनंद का वातावरण बनाने के लिए दुर्गासप्तशती का पाठ करें।विद्यार्थी के लिए और प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अनुकूल अवसर हैं। शुभ अंक 2 और शुभ रंग सफेद या ऑफ वाइट।

मिथुन स्वास्थ्य का ध्यान रखें।प्रतिष्ठा तो मिलेगी।लेकिन धनागमन में थोड़ी परेशानी होगी।अष्टम शनि के लिए चांदी का टुकड़ा अपने पास रखें।दशम सूर्य आपके जीवन में विशेष कृपा बनाएगा।मा के महालक्ष्मी रूप की पूजा करें। शुभ अंक 3 रंग हरा और लाल।

कर्क सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है।घर के स्त्री पक्ष का सेहत चिंता का कारण बनेगा।प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अनुकूल समय है।हनुमान जी की आराधना करें।बजरंगबाण का पाठ करें। शुभ अंक 7। शुभ रंग- गुलाबी

सिंह मत्र के वेश में छुपे शत्रु से सावधानी की जरूरत है।श्री लुक्ष्मी नारायण की पूजा से धन लाभ होगा।संध्या प्रहर घी का चतुर्मुख दीपक अपने घर के मुख्यद्वार पर प्रतिदिन जलाए।उत्सव और मांगलिक कार्य की बातें करने का उपयुक्त समय है। शुभ रंग नीला। शुभ अंक 8।

कन्या पंचम शनि करियर के क्षेत्र में अच्छे अवसर देंगे।विद्या व बुद्धि से सफलता प्राप्त होंगे।गुरु के प्रभाव से लीवर या पेट की समस्या रहेगी। महामृत्युंजय मंत्र का जाप या श्रवण करें। शुभ रंग पीला। शुभ अंक 3।

बृश्चिक आपके आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा से धन आगमन का योग है।भाई के लिए समय अनुकूल नही है।बाएं सुर बाले पीले गणपति का तस्बीर घर में रखें।प्रतिष्ठा व सम्मान का योग है। शुभ रंग सफेद। शुभ अंक 5।

तुला भाग्य का राहु राजनीतिक व सामाजिक क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करेंगे।गुरु की कृपा से शत्रु व रोग का नाश होगा।शनि माता के स्वास्थ्य के लिए ठीक नही है।चांदी के पात्र से गाय का कच्चा दूध नदी में बहाएं।अनुकूलता बनी रहेगी। शुभ रंग लाल। शुभ अंक 4।

मकर जिद्द छोड़ना होगा।बाएं हाथ की कलाई में पीला धागा बांधने सेनुक्सान कम होगा।राहु अचानक व विचित्र परिणाम दे सकता है।कालभैरव जी की पूजा करें। शुभ रंग सफेद। शुभ अंक 7।

कुम्भ झूठ से नफरत होगी।झूठे लोगों से सामना होगा।लाभ होंगे लेकिन मन के अनुकूल नही।लेकिन मान सम्मान बढेगा।मंगल कार्य के लिए आगे बढ़े।आवश्यकता को कम करें।चोट चपेट से बचना होगा।हल्दी का गांठ अपने पर्स में रखें।ॐ नमो नारायणाय का जाप करें। शुभ रंग-गुलाबी। शुभ अंक 8।

धनु धन का आगमन होगा।लेकिन सूर्यास्त के बाद दूध व दही का सेवन नही करें।आत्मभिमान से बचना होगा।अहंकार को हावी नही होने दे।हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक 6। शुभ रंग हरा।

मीन सूर्य की कृपा से पद व प्रतिष्ठा की बृद्धि होगी।गुस्सा पर नियंत्रण रखें।दुश्मन से सचेत जरूरी है।नजर बचना होगा।घर की शांति राहु के कारण नियंत्रण में नही रहेगा। सफेद कपड़े में सिंधा नामक घर के मुख्य द्वार पर बांधे। शुभ रंग -हरा। शुभ अंक 9।

बीएन मंडल यूनिवर्सिटी के कुलपति को
पत्रिका भेंट करते राधेश्याम प्रसाद

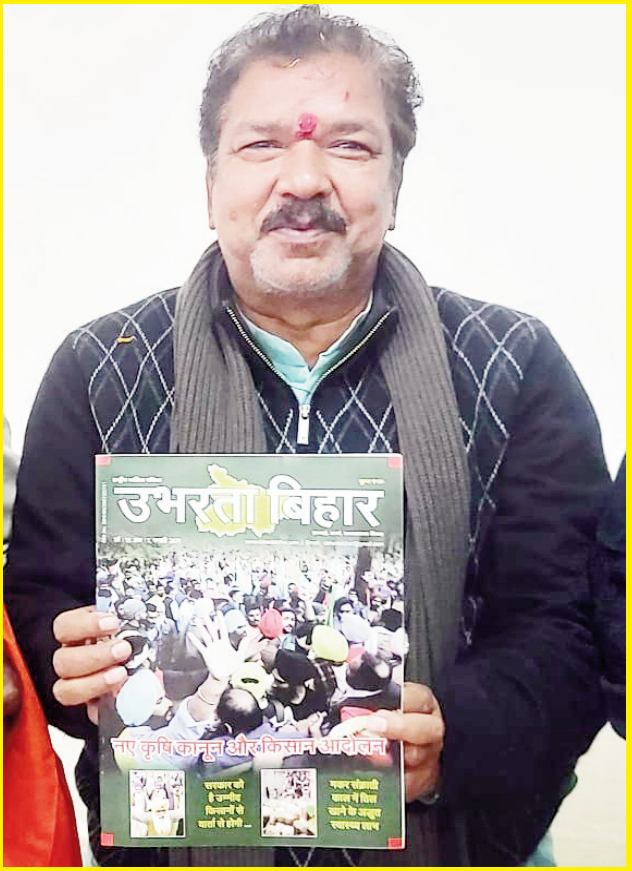

उभरता बिहार पत्रिका के साथ
डॉ दिलीप कुमार जायसवाल, माननीय विधान पार्षद

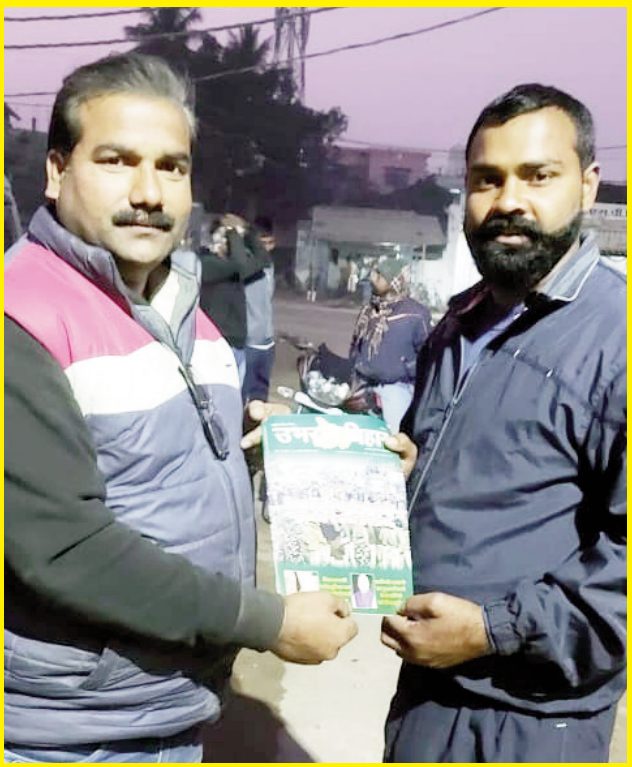

रजनीश कुमार उर्फ गोलू यादव को
पत्रिका भेंट करते विनोद कुमार

पूर्व डीजीपी एस के भारद्वाज को
पत्रिका भेंट करते संपादक राजीव रंजन

माननीय उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद को पत्रिका भेंट करते हुए संपादक राजीव रंजन।

माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा को पत्रिका भेंट करते हुए संपादक राजीव रंजन।

FORD HOSPITAL, PATNA

A NABH Certified Multi Super-Speciality Hospital

PATNA

A 105-Bedded Hospital Run by Three Eminent Doctors of Bihar

उत्कृष्टता एवं अपनत्व की अनुभूति

Dr. Santosh Kr.

Dr. B.B. Bharti

Dr. Arun Kumar

PATIENT SAFETY & QUALITY OF CARE

NABH

PRE ACCREDITED

हृदय रोग चिकित्सा के लिए बेहतरीन टीम

डॉ॰ बी॰बी॰भारती

डॉ॰ अनूप सिंह

डॉ॰ मनमोहन

Best Promising Multi Speciality Hospital 2018 Bihar.

2nd Multi Speciality NABH Certified Hospital of Bihar

फोर्ड हॉस्पिटल में उपलब्ध सेवाएँ

क्लीनिकल सर्विसेस

- कार्डियोलॉजी
- क्रिटीकल केयर
- न्यूरोलॉजी
- स्पाईन सर्जरी
- नेफ्रोलॉजी एवं डायलेसिस
- ऑर्थोपेडिक एवं ट्रॉमा
- ओब्स एवं गॉबनेकोलॉजी
- पेडिएट्रिक्स
- पेडिएट्रिक सर्जरी
- साइचिरेट्री एवं साइकोलॉजी
- रेस्पिरेट्री मेडिसिन
- यूरोलॉजी
- सर्जिकल ऑन्कोलॉजी

Empanelled with CGHS, ECR, CISF, NTPC, Airport Authority, Power Grid & other leading PSUs, Banks,Corp. & TPS

New Bypass (NH-30) Khemnichak, Ramkrishna Nagar, Patna-27
Helpline : 9304851985, 9102698977, 9386392845 Ph.: 9798215884/85/86
E-mail : fordhospital@gmail.com Web.: www.fordhospital.org

के.बी.पी.एल

देश का डीजल

प्रदूषण मुक्त

सस्ता दाम

माइलेज ज्यादा

KRRISHAY BIOFUELS

(Registered by Govt. of India)

(AN ISO 9001:2015) CERTIFIED COMPANY)
(AN ISO 14001:2015) CERTIFIED COMPANY)
(AN ISO 45001:2018) CERTIFIED COMPANY)

Corporate Office :

318, Maharaja Kameshwar Complex, Fraser Road
Infront Budh Smriti Park, Patna-800001
Website : www.krrishaybiofuels.com
Email : krrishaybiofuels@gmail.com
Mob. No. : 7541086226, 9709707583